चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 30 जनवरी-05 फरवरी 2012 | मूल्य 5 रुपये

फ़र्ज़ी दाख़िले से सुशासन पर शक

पेज-3

तेरह विधायकों की हार निश्चित है

पेज-4

क्या प्रियंका लक्ष्मण रेखा पार करेंगी

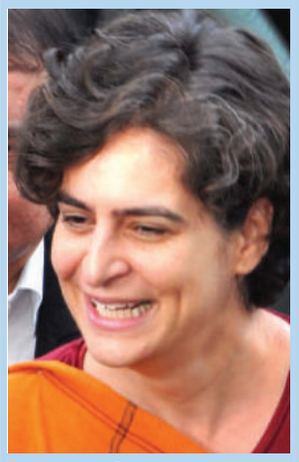

पेज-5

मातृभूमि का गौरव या कलंक कहना काफ़ी नहीं है

पेज-7

कांग्रेस सरकार इज़राइल की दोस्त है

फोटो-प्रभात पाण्डेय

इज़राइल के मंसूबों का बीजारोपण हिंदुस्तान में आडवाणी की वजह से हुआ. लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस बीज को ऐसा सींचा कि सात साल में ही यह एक वटवृक्ष बन गया है. भाजपा की सरकार के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसा लगा कि शायद इज़राइल के मंसूबों पर लगाम लगेगी ,लेकिन इससे ठीक उल्टा हुआ. जो काम शायद लालकृष्ण आडवाणी भी नहीं कर सके, वह काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले आठ साल में कर दिखाया.

मनीष कुमार

इज़राइल के अख़बारों में भारत-इज़राइल दोस्ती की कहानियां धड़ल्ले से छप रही हैं. दोनों देशों को एक नेचुरल फ्रेंड बताया जा रहा है. साथ में यह भी बताया जा रहा है कि किस तरह अमेरिका की यहूदी लॉबी ने अमेरिका, और भारत को एकजुट किया. यही यहूदी लॉबी भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील और इज़राइल से हथियार ख़रीदने की डील के पीछे है. इस यहूदी लॉबी की ताक़त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूक्लियर डील की वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था.

कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के साथ-साथ देश के कई बड़े ख़ुफ़िया और आला अधिकारी इज़राइल में थे. इज़राइली मीडिया के मुताबिक़, उनकी काफ़ी आवोभगत हुई. बताया गया कि यह भारत सरकार की तरफ़ से अब तक का सबसे उच्च स्तरीय और सफल दौरा था. भारत सरकार अब तक इज़राइल के साथ रिश्ते को छिपाती रही है. लेकिन जिस तरह कांग्रेस के विदेश मंत्री ने इज़राइल के साथ क़रार किया है, वह चौंकाने वाला है. कांग्रेस सरकार ने बंगलुरु में इज़राइल को कांसुलेट खोलने की इजाज़त दी है. साथ में प्रत्यार्पण संधि भी की है. फ़िलहाल दोनों देशों के बीच 5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जो अब बढ़कर 15 बिलियन डॉलर होने वाला है. कांग्रेस सरकार इज़राइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहती है, ताकि इज़राइली सामान बिना रोक-टोक भारत में बिक सके. दिसंबर 2011 में इज़राइल के वित्त मंत्री यह ऐलान कर चुके हैं कि उनके लिए अमेरिका के बाद भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है. मतलब यह कि अमेरिका के बाद इज़राइल का सबसे गहरा दोस्त भारत बन चुका है. हैरानी की बात है कि अमेरिका भी यह चाहता है कि इज़राइल और भारत की नज़दीकियां बढ़ें. बताया यह जाता है कि कांग्रेस सरकार और इज़राइल की दोस्ती के पीछे अमेरिका में सक्रिय यहूदी लॉबी अमेरिकन ज्यूइस एडवोकेसी ग्रुप भारत- इज़राइल के मज़बूत रिश्ते में अहम भूमिका निभा रहा है. यह यहूदी लॉबी अमेरिका की सरकार में काफ़ी दख़ल रखती है. कांग्रेस सरकार को लगता है कि इस यहूदी लॉबी के सहारे न सिर्फ़ इज़राइल के साथ, बल्कि अमेरिका के साथ भी रिश्ते मज़बूत होंगे. इस यहूदी लॉबी ने सबसे पहले बुश शासन के दौरान अमेरिका, भारत और इज़राइल को एक साथ किया और तीनों देशों की प्राथमिकता तय की. इसी यहूदी लॉबी की वजह से भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील पर साइन किया गया. इसी लॉबी की वजह से भारत, इज़राइल से सैन्य सामग्री ख़रीद रहा है.

कांग्रेस के शासनकाल में सत्ता के अलग-अलग केंद्रों पर यहूदी समर्थक अधिकारियों और विशेषज्ञों का क़ब्ज़ा हुआ. छात्रों का एक-दूसरे देश में जाने का सिलसिला तेज़ हुआ. देश भर में ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ, जिनका एकमात्र काम यह था कि देश में असुरक्षा की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके हथियार ख़रीदने के लिए ज़मीन तैयार की जाए. कुछ ऐसी ख़बरें भी आईं कि इज़राइल के साथ हुए रक्षा सौदों में नौ फ़ीसदी कमीशन की भी बंदरबांट हुई. इसके बाद भाजपा की सरकार ने इज़राइल से हथियार ख़रीदने का सिलसिला शुरू किया. इन डीलों से आए कमीशन और किक बैक की भी ख़बर आई. हैरानी की बात यह है कि न तो किसी ने इस मामले की तहक़ीक़ात करने के बारे में सोचा और न ही इसकी ज़रूरत समझी. ख़बरें आईं और चली गईं. क्या हमारे देश का सरकारी तंत्र इज़राइल के सामने इतना असहाय हो गया कि इससे जुड़ी किसी भी गड़बड़ी की तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती. क्या अधिकारी इज़राइल का नाम सुनते ही मामले को दबा देते हैं. अगर नहीं, तो इज़राइल के साथ हुए रक्षा सौदे पर जांच के बारे में देश की जनता को क्यों नहीं बताया गया. इसका मतलब साफ़ है कि मोसाद के पैर भारत में इतने जम चुके हैं कि वह हमारे ही तंत्र का इस्तेमाल करता है, और हमारी सरकार को कानो-कान ख़बर तक नहीं होती. रक्षा सामग्री का निर्यात इज़राइल की आमदनी का मुख्य ज़रिया है. हैरानी की बात यह है कि भारत, इज़राइल से हथियार ख़रीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है. अब यह सोचने वाली बात है कि यह कमाल कैसे हुआ. जिस देश के साथ हमारे संबंध को अभी कुछ ही साल हुए हैं, उसके हम इतने गहरे दोस्त कैसे बन गए. हमारे देश में जिस तरह से हथियार ख़रीदे जाते हैं, उससे तो यही लगता है कि बिचौलियों की भूमिका बहुत अहम है. इसका मतलब तो साफ़ है कि यह मामला सिर्फ़ दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच तक सीमित नहीं है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इज़राइल, भारत के साथ क्यों नज़दीकियां बढ़ाना चाहता है. दोनों देशों की रणनीति क्या है, और दोनों देशों को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है. इज़राइल और भारत सरकार की नीतियों के केंद्र में है पाकिस्तान की तबाही और जम्मू-कश्मीर की आज़ादी. सुरक्षा अधिकारी बताते हैं कि इस गठजोड़ का मक़सद मिलजुल कर इस्लामिक आतंकवाद के ख़तरे से निपटना और पाकिस्तान का सफ़ाया करना है. इस गठजोड़ का आधार यह है कि दोनों देशों का दुश्मन एक ही है, मतलब इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान. भारत सरकार ने इज़रायल और अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक एंड क्रश यानी हमला करने और कुचलने की नीति बनाई. इस तरह भारत में मोसाद ने अपने पैर जमाने शुरू किए. भारत की ख़ुफ़िया एजेंसी और मोसाद के बीच सहयोग बढ़ा. यह काम आडवाणी ने शुरू किया था, लेकिन इसे कांग्रेस अंजाम तक पहुंचा रही है. इस्लामिक आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के नाम पर भारत और इज़राइल में नज़दीकियां इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों ही देश एक-दूसरे की समस्या को समझते हैं. मिलजुल कर इसका हल भी निकालते हैं. मीडिया में क्या कहना है और किन चीज़ों से बचना है, सब योजनाबद्ध तरीक़े से अंजाम दिया जाता है. इसमें इज़राइल की ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुंबई हमले के बाद भारत सरकार को इज़राइल की याद आई. पूरे देश में चौकसी रखने वाले हाईटेक यंत्रों का ठेका इज़राइल को दे दिया. समझने वाली बात यह है कि ये यंत्र सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं. दोनों देशों की सरकारों में नज़दीकियां इतनी हैं कि इन यंत्रों को चलाने और मेंटेन करने में दोनों ही देशों की ख़ुफ़िया एजेंसियां एक साथ काम करती हैं. मतलब यह कि इन यंत्रों से प्राप्त जानकारी भारत सरकार के साथ-साथ इज़राइल के पास भी होती है

देखा जाए तो नीतिश कुमार को आईएएस अधिकारियों की अपेक्षा आईपीएस अधिकारियों से संपत्ति का ब्योरा प्राप्त करने में ज़्यादा परेशानी हो रही है.

दिल्ली का बाबू

संपत्ति का ब्योरा कब देंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबुओं के बीच फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो क़दम उठाए, वे कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए आधार बने. भले ही नीतीश कुमार को इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन उनका प्रयास काफ़ी नहीं है. उन्हें इसके लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के मुख्य सचिव नवीन कुमार को उन अधिकारियों के बारे में जो अपनी संपत्ति का ब्योरा देने वाले हैं, पत्र लिखा है. ग़ौरतलब है कि नीतिश कुमार ने बिहार के अधिकारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन कई अधिकारियों ने अभी तक इस निर्देश का पालन नहीं किया है. जिन अधिकारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उसमें कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं. देखा जाए तो नीतिश कुमार को आईएएस अधिकारियों की अपेक्षा आईपीएस अधिकारियों से संपत्ति का ब्योरा प्राप्त करने में ज़्यादा परेशानी हो रही है. अभी तक बिहार के 71 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है. इन अधिकारियों में मनोज नाथ, शफ़ी आलम, सुनीत कुमार और एनसी धोंधिया का नाम शामिल है. जनवरी के अंत तक सभी को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना है तो अब उन पर इसके लिए दबाव डाला जा सकता है.

सेवानिवृत्त बाबुओं से परेशानी

आजकल कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी सेवानिवृत होने के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी करने लगे हैं. इससे सरकार को परेशानी होती है. वैसे तो सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित समय तक किसी निजी संस्थान में नौकरी नहीं करना होता है. लेकिन इस समय सरकार इस मामले को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले रही है. कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के सामने उठाया है. सूत्रों का कहना है कि तीन वित्तीय विशेषज्ञ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ऐसे काम मिले हैं. साफ़ तौर पर रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामल गोपीनाथ, तेरहवे वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय केलकर और पूर्व व्यय सचिव सुषमा नाथ का मुद्दा उछला है. अधिकारियों के बीच इस बात की कानाफूसी चल रही है. सबसे महत्वपूर्ण वजह कुछ गुप्त सुचनाओं का लीक होना है. इन अधिकारियों के पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, जिसका लाभ निजी कंपनियां उठाती हैं.

कथनी और करनी में अंतर

जहां केंद्रीय सतर्कता आयोग असफल हो जाता है, वहां सीबीआई उसकी जगह लेती है. सीबीआई ने केंद्रीय आबकारी आयुक्त अनूप कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया. उन पर कर चोरी का आरोप लगाया गया है. इसी महीने उनके घर सीबीआई का छापा पड़ा था. इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले सीवीसी ने भी उनके बारे में कुछ छानबीन की थी. सीवीसी ने सिफ़ारिश की थी कि अनूप श्रीवास्तव का स्थानांतरण किसी ग़ैर संवेदनशील पद पर किया जाए. इसे सीवीसी की कमी ही कही जा सकती है कि उसने जो पत्र केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेजा था, वह वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया. वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी होने के बाद सीवीसी को कुछ परेशानी भी हुई है. जब सीवीसी (केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के प्रमुख एसके गोयल और अन्य सदस्य श्रीवास्तव का स्थानांतरण जयपुर करने को सहमत हो गए तो वित्त मंत्रालय के कुछ बाबुओं द्वारा इसमें बाधाएं डाली गईं. सूत्रों का कहना है कि इस बात की संभावना है कि अनूप श्रीवास्तव को उसी पद पर रखा जा सकता है.

दिलीप चेरियन
dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

अशोक कुमार एएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को रक्षा उत्पाद विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह पहले इसी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे.

रवि सिन्हा निदेशक बने

1984 बैच की आईडीएसई अधिकारी रवि सिन्हा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक बनाया जाना है. वह एके मिश्रा की जगह लेंगे, जिन्हें पदोन्नति मिली है.

अनीता चौधरी सचिव बनीं

1976 बैच की आईएएस अधिकारी अनीता चौधरी को भूमि संसाधन विभाग में सचिव बनाया गया है. वह पहले भी इस विभाग में सचिव रह चुकी हैं.

सरिता जेएस एंड एफए बनीं

1990 बैच की सीएसएस कैडर की अधिकारी सरिता मित्तल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) बनाया जाएगा. वह अजय नारायण झा की जगह लेंगी, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भेजा गया है.

एस विजय कुमार ग्रामीण विकास में सचिव बने

1976 बैच के आईएएस अधिकारी एस विजय कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. वह डॉ. विरेंद्र कुमार सिन्हा की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी, 2012 को सेवानिवृत हो रहे हैं.

कांग्रेस सरकार इज़राइल की दोस्त है

पृष्ठ एक का शेष

और भारत सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं. यह कहना ग़लत न होगा कि इज़राइल को भाजपा ने भारत में पैर रखने की जगह दी, लेकिन कांग्रेस ने उसे पूरी छूट दे दी है.

इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत और इज़राइल के बीच कोई सैन्य समझौता है, क्या ये दोनों देश स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं या दोनों किसी स्ट्रेटजिक एलायंस का हिस्सा हैं. सैन्य संधि का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा देश एक तय लक्ष्य को पाने के लिए एकजुट होते हैं. इसमें शामिल देश एक-दूसरे को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं. दो देशों के बीच सैन्य संबंधों का आधार कोई ख़तरा होता है. वह ख़तरा किसी दुश्मन देश से हो सकता है. यह रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें दोनों देशों को लगता है कि एक-दूसरे से हाथ मिलाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा. इस रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब यह है कि दोनों देश जब कोई यंत्र या हथियार बेचते हैं, तो साथ में उसे बनाने की तकनीक को भी दे देते हैं. यह तब होता है, जब दोनों देशों का कोई दीर्घकालिक एजेंडा हो. इसका मतलब यह भी है कि दोनों देशों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक नज़रिया है. इज़राइल-भारत संबंध के बारे में जितनी जानकारी अब तक बाहर आई है, उससे यह लगता है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यानी सैन्य समझौता तो नहीं हुआ है. लेकिन शंका इस बात की है कि दोनों देशों के बीच जो क़रार हो रहे हैं, उनकी सही और पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है. यही वजह है कि अख़बारों में जब यह छपता है कि भारत के साथ 1 बिलियन डॉलर का रक्षा सौदा हुआ है, लेकिन भारत में इसकी सुगबुगाहट नहीं होती और एक दिन के बाद अख़बारों में यह ख़बर आ जाती है कि इज़राइल का सौदा किसी एशियन देश के साथ हुआ है, लेकिन देश का नाम छुपा दिया जाता है. कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत-इज़राइल के रिश्ते में इतना पर्देदारी है कि इसे ख़ुफ़िया सैन्य समझौता यानी सिक्रेट स्ट्रेटजिक पार्टनर कहा जा सकता है. इसके कई कारण भी हैं.

पहला सवाल तो यह है कि भारत अचानक से इज़राइल के हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीददार कैसे बन गया. दूसरी बात यह कि दोनों देशों की नज़दीकियों का वह कौन सा गहरा राज़ है, जिससे इज़राइल न सिर्फ़ हथियार बेच रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है. सैन्य संबंध के अलावा यूपीए सरकार के दौरान इज़राइल-भारत की दोस्ती का ऐसा रंग चढ़ा कि भारत, इज़राइल के सैन्य सामान का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला दोस्त बन गया. 2008 में इसरो ने इज़राइली सैटेलाइट पोलारिस को लॉन्च किया. इसके तुरंत बाद 20 अप्रैल, 2009 को भारत ने इज़राइली स्टैलाइट रीसैट-2 को लॉन्च किया. इस इज़राइली सैटेलाइट का काम नक्शे तैयार करना है. इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई. हैरानी की बात है कि जब इसे लॉन्च किया जा रहा था, तब इसे दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया. इस सैटेलाइट के बारे में सही जानकारी तब मिली, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस आर रेड्डी की मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, तब इसी सैटेलाइट को उन्हें ढूंढने में लगाया गया था. मतलब यह कि यह एक ख़ुफ़िया सैटेलाइट है. वैसे सरकार को यह बताना चाहिए कि इन सैटेलाइट के अलावा कांग्रेस सरकार के दौरान इज़राइल के कितने ख़ुफ़िया सैटेलाइट को भारत से लॉन्च किया गया, जिनका काम इस्लामिक देशों पर नज़र रखना है. इसके अलावा 2008 में कांग्रेस सरकार ने ज़मीन से हवा में मार करने वाली स्पाइडर मिसाइल को साथ मिलकर बनाने का क़रार किया था.

मुंबई हमले के बाद भारत सरकार को इज़राइल की याद आई. पूरे देश में चौकसी रखने वाले हाईटेक यंत्रों का ठेका इज़राइल को दे दिया. समझने वाली बात यह है कि ये यंत्र सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं. दोनों देशों की सरकारों में नज़दीकियां इतनी हैं कि इन यंत्रों को चलाने और मेंटेन करने में दोनों ही देशों की ख़ुफ़िया एजेंसियां एक साथ काम करती हैं. मतलब यह कि इन यंत्रों से प्राप्त जानकारी भारत सरकार के साथ-साथ इज़राइल के पास भी होती है. इसका ग़लत इस्तेमाल हो सकता है. देश के कई मुस्लिम संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई, लेकिन सरकारी तंत्र पर इज़राइल की पकड़ इतनी मज़बूत है कि देश की सरकार को इन ख़तरों की परवाह नहीं है. जनवरी 2009 में भारत ने इज़राइल से तीन फॉल्कन-अवास्क (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) लिए, जिनका इस्तेमाल भारत, पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए करेगा. भारत सरकार ने इन ख़बरों को सामने नहीं आने दिया. लेकिन इज़राइल से ख़बर आई कि फॉल्कन डील के साथ-साथ इज़राइल भारत में आर्टिलरी शेल को बनाने वाली पांच फैक्ट्रियां लगाएगा. इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश में इज़राइल की सॉफ्टवेयर कंपनियों को खुली छूट दे रखी है. इज़राइल यहां न सिर्फ़ रिसर्च प्रोजक्ट लगा रहा है, बल्कि हैदराबाद को एक सॉफ्टवेयर हब बनाना चाहता है, जहां रक्षा और चौकसी के हाईटेक यंत्रों को बनाया जाएगा. नोट करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार है. इस पर 250 मिलियन डॉलर का ख़र्च आएगा. भारत अब तक इज़राइल से नेवल क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, पायलट रहित विमान के साथ सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर कई ख़तरनाक हथियार ख़रीद चुका है. बताया यह जाता है कि इन सबके अलावा सरकार ने इज़राइल के साथ ख़ुफ़िया तरीक़े से क्रूज मिसाइल, माइक्रो सेटेलाइट सिस्टम और लेजर गाइडेड सिस्टम का क़रार किया है.

अब सवाल यह है कि भारत सरकार ने इज़राइल की हथियार कंपनियों को देश में फैक्ट्री लगाने की अनुमति क्यों दी? क्या इन विषयों पर कभी संसद में चर्चा हुई? वैसे सरकार को इज़राइल के साथ किए गए क़रारों के लिए संसद की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह बात भूल गई कि भारत की आज़ादी के पहले से ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन के विभाजन का जमकर विरोध किया था. वे शुरू से ही इज़राइल के विरोधी रहे. 29 नवंबर, 1947 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के निर्माण के विरोध में वोट किया था. आज कांग्रेस सरकार जो कर रही है, वह भारत की विदेश नीति के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है. भारत फिलिस्तीन का हमेशा से समर्थक रहा है. आज़ादी से पहले गांधी और नेहरू ने इज़राइल के निर्माण का विरोध किया था. इज़राइल के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, यह 1948 से ही गुप्त रहा. यही वजह है कि दोनों देशों को अपने-अपने दूतावास खोलने में 44 साल लग गए. 1992 में नई दिल्ली में इज़राइली दूतावास और तेल अवीव में भारतीय दूतावास बना. इज़राइल और भारत के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव तब आया, जब भारत में भाजपा की सरकार बनी. इज़राइल पहले से ही फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कुचलता रहा है. कांग्रेस सरकार ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया और अरब देशों को नज़रअंदाज़ करके इज़राइल से दोस्ती कर ली. इस दोस्ती का मतलब यह है कि हमने फिलिस्तीन के मामले पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं.

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 47
दिल्ली, 30 जनवरी–05 फरवरी 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
सी-20, ट्रांस यमुना, एनएच-2, आगरा
फोन : 0526-4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

उपरोक्त आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति वास्तव में कितनी भयावह है. सरकार जो दावा कर रही है वह हक़ीक़त से कितनी दूर है.

बिहार

फ़र्ज़ी दाख़िले से सुशासन पर शक

सरकार कह रही है कि स्कूलों में फ़र्ज़ी दाख़िले को उसने ख़ुद पकड़ा. तथ्यों को जब ख़ुद सरकार उजागर कर रही है तो जांच की ज़रूरत क्या है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार चोरी के बाद सीनाज़ोरी कर रही है. चारा घोटाले की जांच लालू प्रसाद ने ख़ुद करवाई थी, यह बात नीतीश कुमार क्यों भूल रहे हैं. इसका फलाफल क्या हुआ, इसे पूरे देश के लोग जानते हैं.

सरोज सिंह

सेवा यात्रा के क्रम में पिछले दिनों मुख्यमंत्री मधुबनी के राजकीय अंबेडकर आवासीय स्कूल में गए तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले सवालों से रूबरू होना पड़ा. एक छात्र ने कहा कि छत से पानी टपकता है, तो दूसरे ने कहा कि यहां शौचालय नहीं है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव अंजनी सिंह से कहा कि बिना शौचालय के आवासीय स्कूल कैसे हो सकता है. अंजनी बाबू, देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. आनन–फ़ानन में शौचालय निर्माण का आदेश दे दिया जाता है. यह एक बानगी है कि सूबे में स्कूली शिक्षा में हुई बेहतरी के बड़े–बड़े दावों की. इससे पहले इस ख़ुलासे ने सरकार की नींद उड़ा दी कि सूबे के स्कूलों में एक अनुमान के अनुसार साढ़े तीन लाख फ़र्ज़ी दाख़िले हुए हैं. लाखों नाम हटाए गए हैं जिनको सरकार क्लीनिंग ऑफ रजिस्टर का नाम दे रही है. तथ्य सामने आने के बाद सरकार कह रही है कि समय रहते इस फ़र्ज़ी दाख़िले को उसने ख़ुद पकड़ा. विपक्ष का इसमें कोई हाथ नहीं, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार चोरी के बाद सीनाज़ोरी कर रही है. चारा घोटाले की भी जांच लालू प्रसाद ने ख़ुद करवाई थी, यह बात नीतीश कुमार क्यों भूल रहे हैं. इसका फलाफल क्या हुआ, इसे पूरे देश के लोग जानते हैं. बेहतर होगा इस शिक्षा घोटाले की सीबीआई जांच हो, ताकि दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके.

सरकार लाख कहे कि गुणवत्ता शिक्षा मिशन की जांच में ये फ़र्ज़ी दाख़िले पकड़े गए, पर सच्चाई यह है कि 2007 में संकल्प कार्यक्रम के दौरान ही इस बात के संकेत सरकार को मिल गए थे कि कुछ स्कूलों में पचास फ़ीसदी से ज़्यादा फ़र्ज़ी दाख़िले हुए हैं. लेकिन इन संकेतों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और रोज़ स्कूलों में दाख़िले के बड़े–बड़े दावे कर वाहवाही लूटने में मस्त रही. नतीजा यह हुआ कि केवल एक स्तर पर ही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर सूबे को नुक़सान उठाना पड़ा. पहला भरोसा तो सुशासन का टूटा है. सांसद जगदानंद सिंह सवाल करते हैं कि साढ़े तीन लाख फ़र्ज़ी दाख़िले हो गए और सरकार को ख़बर तक नहीं लगी. उनका आरोप है कि यह सब मिलीभगत का नतीजा है. नीतीश सरकार ने सूबे की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया. सिपाही की बहाली परीक्षा से और शिक्षक के प्रमाण पत्र से, ऐसा कहीं होता है क्या. शिक्षा के मामले में इसी ग़लत नीतियों की वजह से सूबा तीस साल पीछे चला गया है, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि एक से अधिक सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक ज़िम्मेदार होंगे. इसे व्यवस्थित करने के लिए टीसी की व्यवस्था फिर से लागू होगी. हमने ही व्यापक स्तर पर जांच का निर्देश दिया. अभिभावकों से उन्होंने अपील की कि राज आपका और राजकोष भी आपका है. पड़ताल से सही संख्या का पता चलेगा. नामांकन सरकारी स्कूल में और पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में अब यह नहीं चलेगा.

वहीं इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल सुलभ कहते हैं कि यह सौ फीसदी लापरवाही और लूट का मामला है. छात्रों के भविष्य और शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सुलभ के अनुसार यह सब सरकारी मिलीभगत का नतीजा है. इन्होंने पूरे मामले की जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की.

दूसरा नुक़सान भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग के दावे का भी हुआ है. पूर्व विधान पार्षद पीके सिन्हा कहते हैं कि इन्हीं फ़र्ज़ी आंकड़ों के आधार पर मिड डे मील, पोशाक, किताबें और साइकिलें बांटी गई हैं. जब दाख़िले ही फ़र्ज़ी हैं तो इस आधार पर बांटी गई राशि का बंटरबांट तो हुआ ही है. उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के मद में केंद्र सरकार बिहार को भारी रक़म देती है, इसलिए पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए. लेकिन शिक्षा मंत्री पीके शाही कहते हैं कि फ़र्ज़ी नामांकन की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें कोई घपला या घोटाला नहीं है, बल्कि उनके ही निर्देशन में विभाग द्वारा शिक्षण में गुणवत्ता के लिए नामांकन पंजी को दुरुस्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है. यदि हमारे ग़रीब राज्य में कुछ बच्चों ने दो जगह से पोशाक ले ही ली तो मैं इसे घोटाला नहीं समझता. सीबीआई जांच तब होती है, जब सरकार तथ्य छुपाती है. यहां तो सरकार ख़ुद जांच करा रही है. लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि फ़र्ज़ीवाड़ा तो हुआ है. इसके लिए छात्र और अभिभावक से कहीं अधिक शिक्षा विभाग के लोग ज़िम्मेदार हैं. आशंका जताई जा रही है कि एक स्कूल में दर्ज छात्रों के नामांकन रिकॉर्ड का दूसरे और तीसरे स्कूल में इस्तेमाल हुआ और छात्रों को मिलने वाले लाभ को कुछ लोगों ने हथिया लिया. इसलिए जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पूरे फ़र्ज़ीवाड़े से पर्दा उठना मुश्किल होगा.

फ़र्ज़ी दाख़िले के आंकड़ों पर बात करें तो प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके अनुसार, बांका में 70 हज़ार, पश्चिम चंपारण में 57 हज़ार, सीतामढ़ी में 53 हज़ार, सासाराम में 50 हज़ार, कटिहार में 34 हज़ार, मुज़फ्फ़रपुर में 33 हज़ार, जमुई में 32 हज़ार, दरभंगा में 4 हज़ार, कैमूर में तीन हज़ार, छपरा में 72 हज़ार, गया में 83 हज़ार और गोपालगंज में 45 हज़ार फ़र्ज़ी नामांकन का ख़ुलासा हुआ है. स्वयंसेवी संस्था प्रथम की रिपोर्ट में भी बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था की ओर इशारा किया गया है. कपिल सिब्बल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले चार सालों में बिहार के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में नौ फ़ीसदी की गिरावट आई है. तीसरी से पांचवीं कक्षा के 50 फ़ीसदी से अधिक बच्चों को सामान्य जोड़–घटाव करने में कठिनाई आ रही है.

उपरोक्त आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति वास्तव में कितनी भयावह है. सरकार जो दावा कर रही है, वह हक़ीक़त से कितनी दूर है. पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री जिस स्कूल में जाते हैं, अगर उसकी छत चू रही है और उस स्कूल में शौचालय न हो तो दूसरे स्कूलों की स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है. मिथिलेश सिंह कहते हैं कि झूठे आंकड़ों के आधार पर पुरस्कार पाने वाले को सारे पुरस्कार लौटाने चाहिए. इससे पूरे बिहार का अपमान हुआ है. वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू बाबू का मानना है कि यह गंभीर मामला है. जानते हुए भ्रष्टाचार को संरक्षण देना अपराध है. सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि शिक्षा मंत्री के कार्यकलापों की जांच होनी चाहिए. करोड़ों की राशि का ग़बन किया गया है. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार केवल हवा में महल खड़ा करने में जुटी है. जानकार बताते हैं कि फ़र्ज़ी दाख़िले को लेकर सरकार की हो रही किरकिरी से सहयोगी भाजपा भी सकते में है. जिन उपलब्धियों को वह पांच राज्यों के चुनाव में भुनाना चाहती थी, वही शक के घेरे में आ गई. सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी. फ़िलहाल स्कूलों में फ़र्ज़ी दाख़िले ने सुशासन का चेहरा तो बदरंग कर ही दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

पूछिए सवाल

विधायक जी, बैठक से ग़ायब क्यों थे

आप अपना विधायक चुनते हैं. इस उम्मीद के साथ कि आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने जो वादा आपसे वोट मांगते हुए किया था, उसे निभाएंगे. लेकिन होता ठीक इसके उलट है. चुनाव जीतते ही पता चलता है कि विधायक जी के तो तेवर ही बदल गए हैं. जनाब विधानसभा सत्रों की बैठकों से नदारद रहते हैं. अब चुनाव सामने हैं. अब जनता के पास मौक़ा है कि वह अपने वोट की ताक़त का अहसास भी कराएं.

शशि शेखर

जनता और जनप्रतिनिधियों का आमना–सामना पांच सालों में सिर्फ़ एक बार ही होता है. वह तब, जब विधायक जी विधायक बनने की आस में जनता के आगे हाथ फैलाकर वोटों की भीख मांगते हैं. चुनाव ख़त्म होते ही जनप्रतिनिधि असली रंग रूप में आ जाते हैं. सबसे पहले तो ये विधासभा में आने का अपना मक़सद ही भूल जाते हैं. भूल जाते हैं कि उन्हें विधानसभा में उन बैठकों में उपस्थित होने के लिए भेजा गया है, जहां वे अपने–अपने क्षेत्रों से जुड़ी जनता की समस्याओं पर चर्चा करेंगे. लेकिन हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपके चुने हुए विधायकों का विधानसभा में क्या प्रदर्शन रहा है. ये विधायक, विधानसभा में होने वाली बैठकों में कितने दिन मौजूद रहे हैं, कितनी बैठकें हुई हैं, कितने बिलों पर चर्चा हुई, जनहित से जुड़े कितने प्रश्नों को विधानसभा में उठाया गया और इस दौरान कितने बिल पास हुए.

एडीआर ने राज्यों की विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति के जो आंकड़ें पेश किए हैं, उनमें कई ऐसे तथ्य हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जनता के इन प्यारे विधायकों ने किस तरह उन्हें छला है. एडीआर की इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तथ्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा है. बात विधानसभा सत्रों की बैठकों में विधायकों के औसतन उपस्थिति की करें, तो उत्तर प्रदेश के विधायकों की विधानसभा में औसत उपस्थिति प्रतिवर्ष महज़ 23 फ़ीसदी ही रही, यानी विधायकों की सबसे कम औसतन उपस्थिति के मामले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं. अब जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से इस बार पूछना चाहिए, इस बात का हिसाब–किताब मांगना चाहिए कि जब उनके ख़ून–पसीने की गाढ़ी कमाई से विधानसभा के सत्र चलते हैं तो ये विधायक अपना क़ीमती वक़्त कहां ज़ाया कर रहे होते हैं. इनके पास ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम होता है, जो जनता की समस्याओं को भी ताक़ पर रखने के लिए मजबूर करता है. जिस दौरान विभिन्न बिलों पर चर्चा हो रही होती है, उस वक़्त आपके क्षेत्र के विधायक बैठक से ग़ायब रहकर न सिर्फ़ अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ते हैं, बल्कि क्षेत्र की उस जनता की आवाज़ को भी दरकिनार कर देते हैं. आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में महज़ 89 बैठकों में ही 157 बिल पास हो गए. पहले पहल तो ताज्जुब होता है कि यह कमाल कैसे हो गया. जहां एक बिल को पास करने में चर्चाएं इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि कई बिल तो सालों तक भी पास नहीं हो पाते, ऐसे में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 157 बिलों का पास होना हैरत में डाल देता है. लेकिन ग़ौर करें तो तस्वीर साफ़ हो जाती है कि इतनी कम बैठकों में इन बिलों को पास करने में कितनी सूझबूझ और समझदारी दिखाई गई होगी. आमतौर पर एक बिल को पास करने के लिए पर्याप्त चर्चा की जाती है और उस लिहाज़ से बैठकों और पास हुए बिलों की संख्या में कोई तर्कसंगत बात नज़र नहीं आती है. इस बात को कोई बच्चा भी समझ सकता है कि विधायकों ने किस ख़ानापूर्ति वाले रवैये का इस्तेमाल करके जनता के हित से जुड़े बिलों को आनन–फ़ानन में पास किया है. इन बिलों पर न तो ज़रूरी चर्चा हुई होगी और न ही बहस.

राज्य विधानसभा	माने गए वर्ष	विधानसभा के सत्रों की संख्या	बैठकों की कुल संख्या	बैठकों की औसत संख्या/वर्ष	विधायकों की औसतन उपस्थिति (%)	विधानसभा स्थगित किए जाने की समय संख्या
उत्तर प्रदेश (फरवरी 11 तक)	4 वर्ष	10	89	22	23%	26
पंजाब (जनवरी 11 तक)	5 वर्ष	17	240	48	71%	14
मणिपुर (अगस्त 11 तक)	4.5 वर्ष	11	110	24	65 %	11
उत्तराखंड (सितंबर 10 तक)	3.5 वर्ष	11	68	19	91%	108
गोवा (फरवरी 11 तक)	3.5 वर्ष	12	95	26	60%	85
लोकसभा (दिसंबर 10 तक)	2.5 वर्ष	9	208	77	मौजूद नहीं	मौजूद नहीं

5 राज्यों में पिछले पांच सालों की विधानसभा की सर्वाधिक बैठकों की औसतन संख्या पर बात करते हैं. अगर गोवा की बात करें तो यहां की विधानसभा की सर्वाधिक बैठकों की औसतन संख्या 26 है, यानी यहां पिछले पांच सालों में मात्र 26 बैठकें हुईं. उसके बाद मणिपुर में 24 और उत्तर प्रदेश में बैठकों की संख्या 22 है. इसके अलावा सबसे कम बैठकों की औसतन संख्या पंजाब और उत्तराखंड की है, यानी यहां की विधानसभा की सर्वाधिक बैठकों की औसतन संख्या 19 है. बैठकों की संख्या के अलावा अगर बात करें विधायकों की सर्वाधिक औसतन उपस्थिति की, तो उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों की औसतन उपस्थिति 91 प्रतिशत है, वहीं पंजाब में यह 71 प्रतिशत और मणिपुर में 65 प्रतिशत है. यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि इन पांच राज्यों में विधायकों की सबसे कम औसतन उपस्थिति के मामले में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है. जी हां, उत्तर प्रदेश में विधायकों की औसतन उपस्थिति सबसे कम यानी मात्र 23 प्रतिशत है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले पांच वर्षों में मणिपुर विधानसभा में सबसे अधिक 110 दिन विधानसभा की बैठकें चलीं और सबसे कम बैठकें उत्तराखंड में चलीं. यहां पिछले पांच सालों में महज़ 68 दिन ही बैठकें चलीं. यहां विधायकों द्वारा सबसे अधिक यानी 8796 प्रश्न गोवा विधानसभा में पूछे गए और सबसे कम प्रश्न मणिपुर विधानसभा में पूछे गए. यहां मात्र 565 प्रश्न ही पूछे गए. ग़ौरतलब है कि इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जवाब मुहैया ही नहीं कराया है. उत्तर प्रदेश एक मामले में अव्वल रहा है वह है बिल पास करने में. यहां महज़ चार साल में ही 157 बिल पास हुए. सबसे कम 35 बिल मणिपुर में पास हुए. सबसे कम महज़ 11 बार मणिपुर विधानसभा की बैठक स्थगित की गई.

बहरहाल, विधानसभा के चुनावों में जनता को सचेत रहने की ज़रूरत है. जनता अपने मौजूदा विधायकों की ज़िम्मेदारियां और उनके प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड देखे, समझे. फिर इस आधार पर इन सभी विधायकों से जवाब मांगे कि आख़िर उन्हें जनहित से भी ज़रूरी और कौन से काम आ गए, जो उन्होंने सत्रों की बैठकों से ग़ायब रहना उचित समझा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

31 मार्च, 2009 तक वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सबसे अधिक कमाई कांग्रेस की दिख रही है. इसी समयावधि के लिए कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर भाजपा है.

उत्तर प्रदेश

तेरह विधायकों की हार निश्चित है

उत्तर प्रदेश में परिसीमन के कारण कुछ विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण बिगड़ गया है. 13 सीटों पर हालत कुछ ऐसे बन गए हैं कि 13 सीटों पर विधायकों की जीत पर संशय पैदा हो गया है. कौन 13 विधायक होंगे, जो अगली विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, इसे लेकर सभी की जिज्ञासा बढ़ी हुई है.

प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं रही है. लखनऊ पश्चिम से दो वर्तमान विधायक आमने-सामने हैं. इसमें एक भाजपा का और दूसरा कांग्रेस का है. 2007 में यह सीट भाजपा के दिग्गज नेता लालजी टंडन के पास थी. 2009 के लोकसभा चुनाव में लालजी टंडन के जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफ़ा दे दिया. 2009 में हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीन ली और कांग्रेस के श्याम किशोर शुक्ला विधायक चुन लिए गए. वह एक बार फिर कांग्रेस की तरफ़ से अपनी क़िस्मत आज़मा रहे हैं. उनके सामने 2007 में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले भाजपा के सुरेश श्रीवास्तव ताल ठोंक रहे हैं. परिसीमन के बाद उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदल लिया है.

लखनऊ से लगे बाराबंकी ज़िले की तो दो सीटों पर चार विधायक चुनावी मैदान में हैं. सपा के अरविंद सिंह गोप हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित होने के बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी क़िस्मत आज़माने पहुंचे तो वहां बसपा के विधायक अमरेंद्र शुक्ला भी मैदान में ताल ठोंकते दिखे. अब गोप या शुक्ला में से कौन जीतेगा, यह फ़ैसला जनता को करना है. इसी तरह बाराबंकी की ही कुर्सी विधानसभा सीट पर भी बसपा और सपा के दो विधायक आमने-सामने हैं. बसपा से पाला बदलकर सपा में आए फ़रीद महफूज़ किदवई और बसपा से मीता गौतम चुनाव मैदान में उतर चुके हैं. कुर्सी सीट इस बार नई विधानसभा सीट है. फ़रीद पिछली बार बाराबंकी की मसौली सीट से विधायक चुने गए थे, जबकि मीता गौतम बाराबंकी के फ़तेहपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक थीं.

लखनऊ से लगे बाराबंकी ज़िले की तो दो सीटों पर चार विधायक चुनावी मैदान में हैं. सपा के अरविंद सिंह गोप हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित होने के बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी क़िस्मत आज़माने पहुंचे तो वहां बसपा के विधायक अमरेंद्र शुक्ला भी मैदान में ताल ठोंकते दिखे. अब गोप या शुक्ला में से कौन जीतेगा, यह फ़ैसला जनता को करना है.

कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा ने इरफ़ान सोलंकी और कांग्रेस ने संजीव दरियाबादी को चुनाव मैदान में उतारा है. संजीव दरियाबादी इससे पहले कानपुर शहर से विधायक थे. इस बार चुनाव जीतना दोनों विधायकों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है. दोनों हार भले ही जाएं, लेकिन जीत एक की ही होगी. परिमसीन के बाद कानपुर में ही नई बनी सीट महाराजपुर विधानसभा क्षे त्र पर भी दो विधायकों के बीच लड़ाई हो रही है. यहां पिछली बार कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे भाजपा के सतीश महाना और सरसौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहीं सपा की महिला नेत्री अरुणा तोमर आमने-सामने हैं.

इलाहाबाद की बात की जाए तो यहां उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से दो विधायकों के बीच टक्कर हो रही है. इसमें कांग्रेस के अनुग्रह नारायण और भाजपा के उदयभान करवरिया शामिल हैं. उदयभान पहले बारा से जीते थे. मिर्ज़ापुर में भी दो विधायक अपनी क़िस्मत आज़मा रहे हैं. इसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा बसपा से और कैलाश चौरसिया चुनावी जंग में आमने-सामने हैं. रंगनाथ मिश्रा पहले संत रविदास नगर की औराई विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन नए परिसीमन में औराई सीट सुरक्षित हो गई. सहारनपुर में भी दो विधायक आमने-सामने हैं. ये हैं कांग्रेस के इमरान मसूद और बसपा सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी. देखना यह है कि जनता की कसौटी पर कौन विधायक खरा उतरता है. इमरान मसूद कांग्रेस नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं. इससे पहले उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. आज़मगढ़ सदर से भी दो विधायक आमने-सामने हैं. ये हैं सपा के दुर्गा यादव और बसपा के सर्वेश कुमार सिंह. इसी तरह जौनपुर की शाहगंज सीट से सपा के शैलेंद्र सिंह ललई और बसपा से विधायक धर्मराज निषाद आमने-सामने हैं. मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक शाहिद मंज़ूर के सामने बसपा के मंत्री और विधायक लखीमल नागर खड़े हैं. लखीराम इससे पहले मेरठ की खरकौंदा सीट से विधायक थे. उधर, बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट पर भी दो विधायक आमने-सामने हैं. यहां समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र कश्यप और बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र सिंह चुनावी दंगल में हैं. हरदोई की सांडी विधानसभा सीट से बसपा विधायक विरेंद्र वर्मा और समाजवादी पार्टी से राजेश्वरी देवी हैं. कुल 26 विधायक आमने-सामने हैं, लेकिन कम से कम 13 की हार तो निश्चित है. कहीं-कहीं हालात बदले तो दोनों विधायक अपनी सीट गंवा सकते हैं. ऐसे में हारने वाले विधायकों की संख्या 13 से ऊपर जाकर 26 तक भी पहुंच सकती है.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

पार्टियों का लगातार बढ़ता फ़ंड

हाल के कुछ वर्षों में देश की माली हालत भले ही ख़राब हुई हो, लेकिन प्राय: सभी राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उनका फंड लगातार बढ़ा है.

इस समय चुनाव आयोग काले धन पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है. दरअसल, पैसा राजनीति की मेन पॉवर है. यह सारा पैसे का ही खेल है. अब एक नज़र डालते हैं कि राजनीतिक दलों के पार्टी फंड पर. किस पार्टी के पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है. यह आंकड़ा विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए इनकम टैक्स रिटर्न से लिया गया है. राजनीतिक दलों के फंड कई बड़ी कंपनियों की फंडिंग को भी मात देते दिख रहे हैं.

एग्रीगेट इनकम 2002-2003-2010

- वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2009-10 के सात साल की समयावधि के दौरान कांग्रेस को 1518 करोड़ रुपये की आय हुई.
- दूसरे स्थान पर मौजूद भाजपा की आय 754 करोड़ रुपये रही. यह कांग्रेस की आमदनी से लगभग आधी है.
- तीसरा स्थान बसपा का है. 2002-03 से 2009-10 के दौरान बसपा की आय 358 करोड़ रुपये रही है.
- इसी समयावधि के लिए सीपीएम की कमाई 339 करोड़ रुपये, समाजवादी पार्टी की कमाई 263 करोड़ रुपये, एनसीपी की कमाई 109 करोड़ रुपये रही, जबकि आरजेडी ने इस दौरान 15 करोड़ रुपये और सीपीआई ने 7 करोड़ की कमाई की.

एक साल की कमाई

- 31 मार्च, 2009 तक वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सबसे अधिक कमाई कांग्रेस की दिख रही है. इसी समयावधि के लिए कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर भाजपा है. भाजपा ने इस दौरान अपनी वार्षिक आय 220 करोड़ रुपये दिखाई है. तीसरा स्थान क्षेत्रीय दल से नेशनल पार्टी बनने की कोशिश कर रही बसपा का है. बसपा की इस समयावधि के लिए वार्षिक आय 182 करोड़ रुपये है.
- दूसरी पार्टियों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए सीपीएम की वार्षिक आय 63 करोड़ रुपये रही. एनसीपी ने इस समयावधि में 40 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि समाजवादी पार्टी की वार्षिक आय 39 करोड़ रुपये बताई गई है.
- वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए सबसे कम कमाने वालों में सीपीआई और आरजेडी रहे. आरजेडी ने इस समयावधि के लिए अपनी वार्षिक आय 4 करोड़ रुपये दिखाई है, जबकि सीपीआई की कमाई 1 करोड़ रुपये दिखाई गई है.

कौन कितना संपन्न

किसी की संपन्नता का अंदाज़ा उसके पास मौजूद संपत्ति से लगाया जाता है. हमारे देश के राजनीतिक दलों के पास भी ख़ूब संपत्तियां हैं. उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स बताते हैं कि 31 मार्च, 2009 तक कांग्रेस के पास 612 करोड़ की संपत्ति थी. संपत्ति के मामले में बसपा ने भाजपा को पीछे कर दिया और 31 मार्च, 2009 तक उसके पास 286 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. तीसरा स्थान भाजपा का रहा, जिसके पास 261 करोड़ रुपये की संपत्ति थी.

- अन्य पार्टियों में 31 मार्च, 2009 तक सीपीएम के पास 185 करोड़ रुपये, समाजवादी पार्टी के पास 178 करोड़ रुपये, एनसीपी के पास 32 करोड़ रुपये, सीपीआई के पास 7 करोड़ रुपये और आरजेडी के पास 3 करोड़ रुपये की संपत्ति थी.

विकास दर

- अगर राजनीतिक दलों की संपत्तियों या संपन्नता में विकास की बात करें तो सबसे आगे बसपा रही है. बसपा ने वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2009-10 के बीच 59 प्रतिशत की वृद्धि की. वित्तीय वर्ष 2002-03 में बसपा के पास 10.92 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो 2009-10 तक बढ़कर 286.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
- इसी समयावधि में एनसीपी कुल संपत्ति में 51 प्रतिशत, आरजेडी की 35 प्रतिशत, सीपीएम की 20 प्रतिशत, भाजपा की 18 प्रतिशत और सीपीआई की संपत्ति में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अख्तियार करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के चुनाव में 61 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, वहीं 2012 में उसने उनकी संख्या बढ़ाकर 85 कर दी है.

क्या प्रियंका लक्ष्मण रेखा पार करेंगी

अजय कुमार

भूतपूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम आते ही ज़हन में एक ऐसी महिला की तस्वीर उभर आती है, जिसने कभी झुकना और हारना नहीं सीखा था. ताउम्र उनका विवादों से नाता रहा. देश में इमरजेंसी लगाने जैसा फ़ैसला इंदिरा गांधी जैसी नेता ही ले सकती थीं, यह बात इमरजेंसी का विरोध करने वाले भी कहने से परहेज़ नहीं करते. भले ही इसका कांग्रेस और इंदिरा को भारी ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा. यह सिक्के का एक पहलू था. वह देश पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली नेत्री थीं. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उनकी अलग पहचान थी. वह विश्व पटल पर भारत के पक्ष को मज़बूती के साथ रखती थीं. तुरंत फ़ैसले लेने की उनमें अद्भुत क्षमता थी. कई मायनों में वह अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से भी दो क़दम आगे थीं. नेहरू की अकेली लाडली बिटिया इंदिरा ने जो कुछ हासिल किया, क्या उसकी वजह उनका अकेली औलाद होना ही था? यह सवाल आज राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना है. सवाल खड़ा किया जा रहा है कि यदि पंडित जवाहर लाल नेहरू के भी एक पुत्र होता तो इंदिरा की राजनीतिक तक़दीर वैसे ही होती है. आज प्रियंका गांधी वडेरा को सिर्फ़ इसलिए राजनीति से दूर रखा जा रहा है कि कहीं कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार से निकल कर वडेरा परिवार में न पहुंच जाए.

पिछले दिनों प्रियंका तीन दिन के दौरे पर क़रीब तीन साल बाद अमेठी–रायबरेली पहुंचीं तो यहां के बाशिंदे एक बार फिर कहने लगे कि यह दूसरी इंदिरा गांधी है. बुज़ुर्ग जिन्हें इंदिरा गांधी को पास से देखने–समझने का मौक़ा मिला है, वे कहते नहीं थकते हैं कि प्रियंका का अंदाज़ बिल्कुल दादी जैसा है. हावभाव वही, बालों की शैली वही और भीड़ में इसी तरफ़ घुल–मिल जाना जैसे इंदिरा मिल जाती थीं. मुस्कुराते हुए लोगों से हालचाल पूछना, वैसी ही तेज़ी से चलना. क्या फ़र्क़ है दोनों के बीच. शायद प्रियंका को भी अपनी दादी की इमेज से काफ़ी लगाव है, इसलिए उन्होंने अपना रहन–सहन दादी की तरह ही रखा है. वह अक्सर साड़ी में दिखती हैं, जबकि आज की युवतियां साड़ी पहनना भी पसंद नहीं करतीं.

आश्चर्य होता है कि जिस प्रियंका में देश इंदिरा गांधी की छवि देख रहा है, उसे गांधी परिवार सिर्फ़ इसलिए सत्ता से दूर रखे हुए है कि कहीं कांग्रेस में राजनीतिक नेतृत्व के दो केंद्र न हो जाएं. एक तरफ़ प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग कांग्रेसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ गांधी परिवार अपनी ही बेटी को फ़ायदे के लिए तो आगे लाना चाहता है, लेकिन जब बात राजनीतिक भागीदारी की आती है तो उसे पीछे कर दिया जाता है. गांधी परिवार शायद आज भी बेटी–बेटे के फ़र्क़ को मिटा नहीं पाया है. भले ही उसकी सरकार नारा देती हो बेटा–बेटी एक समान. अफ़सोस होता है जब प्रियंका कहती हैं कि अगर भैया चाहेंगे तो वह प्रदेश भर में चुनाव प्रचार करेंगी. प्रियंका को शायद इस बात का भी अहसास है कि राहुल की मर्ज़ी के बिना यूपी में उनके लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं है. दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि प्रियंका राजनीति में आती हैं, तो उनका स्वागत है. वह यह नहीं बता पाते कि वह क्यों राजनीति में नहीं आ रही हैं. यह कहना लोगों के गले नहीं उतरता कि राजनीति में आना या न आना प्रियंका का निजी मामला है.

एक तरफ़ गांधी परिवार प्रियंका को राजनीति से दूर रखता है तो दूसरी तरफ़ चुनाव के समय प्रियंका को इस्तेमाल करता है. इसलिए कभी प्रियंका लोकसभा चुनाव के समय दिखाई देती हैं, तो कभी विधानसभा चुनाव में. प्रियंका को प्रचार के लिए अमेठी–रायबरेली से बाहर निकालने के लिए सभी दिग्गज नेता और मंत्री पूरी ताक़त झोंके हुए हैं. सलमान ख़ुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी सभी प्रियंका के आगे आने का सपना देख रहे हैं. इन नेताओं का मानना है कि प्रियंका के कारण कांग्रेस के वोट बैंक में दो–तीन प्रतिशत भी इज़ाफ़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा. कांग्रेस का मीडिया प्रबंधन देख रहे नेता और सांसद राज बब्बर भी कहते हैं कि कई चुनाव क्षेत्रों से प्रियंका गांधी को प्रचार में भेजने की मांग आ रही है.

कांग्रेस में भी दो गुट हो सकते हैं, जिनमें से एक गुट प्रियंका का पक्षधर हो जाए और दूसरा राहुल के पीछे खड़ा रहे. दोनों मैदान में आ गए तो तुलना होना भी स्वभाविक है. अभी जब प्रियंका मैदान में नहीं हैं,तब भी यह चर्चा कभी–कभी छिड़ ही जाती है कि दोनों में कौन बेहतर है. वैसे गांधी परिवार राजनीतिक बलि लेने में कभी पीछे नहीं रहा है. आज जिस कसौटी पर प्रियंका हैं,कभी वहां नेहरू परिवार के अन्य लोग हुआ करते थे, चाहे जवाहर लाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित रही हों या फिर फ़िरोज़ गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी या अन्य कोई चेहरा. नेहरू–गांधी परिवार में किसी एक को ही आगे बढ़ाने की परंपरा रही है. इसी काम को अब राहुल गांधी आगे बढ़कर अंजाम दिया जा रहा है.

प्रियंका के लिए गांधी परिवार ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उससे प्रियंका भी इत्तेफ़ाक़ नहीं रखती हैं. वह कई बार कह भी चुकी हैं कि भले ही वह राजनीति में न हों, लेकिन राजनीतिक परिवार में होने के कारण राजनीति उनमें अंदर तक समाई हुई है. वह यह कहने से भी पीछे नहीं हटतीं कि उन्होंने अपने लिए राजनीति में आने के सभी विकल्प बंद कर दिए हैं. साथ ही वह यह भी कहती हैं कि राहुल जानते हैं कि उन्हें किस हद तक मेरी ज़रूरत है. रायबरेली के कुछ लोग बताते हैं कि 1999 में कांग्रेस से बग़ावत करके कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अरुण नेहरू भाजपा के टिकट से गांधी परिवार के ख़िलाफ़ रायबरेली से मैदान में कूद पड़े थे. तब कांग्रेसी प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा को जिताने के लिए प्रियंका ने भी कुछ जनसभाएं की थीं. वहां एक जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी बेहद नाराज़ शब्दों में जनता से मुख़ातिब होते हुए बोलीं कि आप लोगों ने इस ग़द्दार को यहां घुसने कैसे दिया. नतीजा, यह रहा कि कैप्टन की जीत हुई और अरुण नेहरू को चौथे स्थान पर रहकर हार का बुरी तरह से सामना करना पड़ा था. तब कांग्रेस की तरफ़ से नारा उछला–प्रियंका नहीं यह आंधी है, इस युग की इंदिरा गांधी है. अब देखना यह है कि क्या प्रियंका गांधी राजनीति में आकर अपने लिए खड़ी कि गई लक्ष्मण रेखा को लांघने का दुस्साहस करेंगी?

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस में भी दो गुट हो सकते हैं, जिनमें से एक गुट प्रियंका का पक्षधर हो जाए और दूसरा राहुल के पीछे खड़ा रहे. दोनों मैदान में आ गए तो तुलना होना भी स्वभाविक है. अभी जब प्रियंका मैदान में नहीं हैं,तब भी यह चर्चा कभी-कभी छिड़ ही जाती है कि दोनों में कौन बेहतर है. वैसे गांधी परिवार राजनीतिक बलि लेने में कभी पीछे नहीं रहा है. आज जिस कसौटी पर प्रियंका है, कभी वहां नेहरू परिवार के अन्य लोग हुआ करते थे, चाहे जवाहर लाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित रही हों या फिर फ़िरोज़ गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी या अन्य कोई चेहरा.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सियासी दलों के मुस्लिम चेहरे

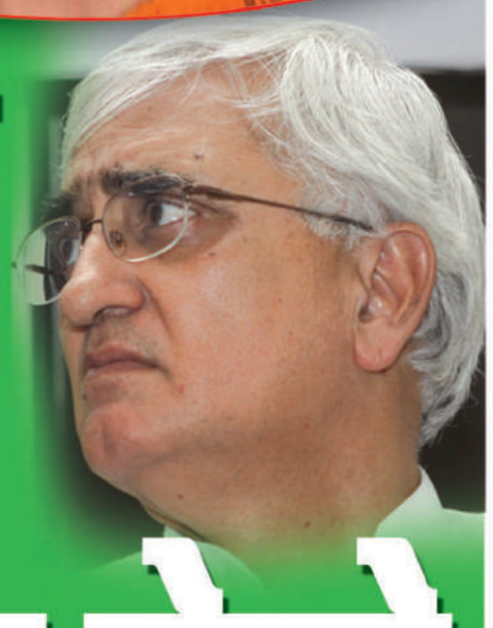

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जहां मुलायम सिंह ने मुसलमानों की रहनुमाई का किरदार निभाने के लिए आज़म ख़ां को आगे कर रखा है. खरी बात कहने वाले आज़म ख़ां फायर ब्रांड मुस्लिम नेता हैं. मुलायम के साथ अधिकतर जनसभाओं में मंच पर एक साथ संगत करते हुए देखे जाते हैं. बसपा नेत्री मायावती ने मुस्लिम वर्ग के बुंदेलखंड के क़द्दावर नेता नसीमुद्दीन को मुस्लिम वोटों के लिए बागडोर सौंप रखी है. उनके पास क़रीब डेढ़ दर्जन से अधिक विभाग हैं. जब-जब उत्तर प्रदेश में माया सरकार आई, तब-तब उन्हें भारी भरकम विभागों का दायित्व मिला. पार्टी के हर छोटे-बड़े निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का ज़िम्मा नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी ही संभालते रहे हैं. कांग्रेस ने मुस्लिमों की दमदार वकालत के लिए केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद के हाथ कमान सौंप रखी है. सलमान ख़ुर्शीद के बारे में यह कहा जाता है कि सोनिया के दरबार में सलमान की ख़ासी चलती है. अगर कांग्रेस यूपी में सत्ता में आती है, तो निश्चित ही मुसलमानों के लिए वह काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं. रालोद ने हाजी याकूब क़ुरैशी को मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए अगुवाकार बनाया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नक़वी को आगे किया है. वह रामपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं. वर्तमान में भाजपा के महासचिव और मीडिया प्रभारी हैं. सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अख्तियार करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के चुनाव में 61 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, वहीं 2012 में उसने उनकी संख्या बढ़ाकर 85 कर दी है. समाजवादी पार्टी ने 2007 में 57 मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया था, जबकि इस बार 2012 में यह संख्या बढ़ाकर 84 कर दी है. इससे ज़ाहिर होता है कि सपा और बसपा में मुस्लिम वोटों को लेकर बड़ी प्रतिद्वंद्विता है. दोनों को ही मुस्लिमों पर ज़्यादा भरोसा दिख रहा है. दोनों दल मुस्लिमों के हमदर्द बनने में पीछे नहीं रहना चाहते. कांग्रेस भी अपने प्रति मुस्लिम रुझान को कम नहीं आंक रही है. उसे लगने लगा है कि अब उसकी बारी मुस्लिम वोट लेने की आ चुकी है. इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या वर्ष 2007 के मुक़ाबले 2012 में 56 की जगह 61 कर दी है. इससे जान पड़ता है कि कांग्रेस की मुसलमानों के बीच स्वीकार्यता बढ़ी है. भाजपा मुस्लिम प्रत्याशियों के बारे में सबसे पीछे है. जहां उसने 2007 में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा था.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

क्यों नहीं बनते ये चुनावी मुद्दे

चुनाव आते ही सियासी दलों में इस बात की हलचल मच जाती है कि इस बार वे जनता के मुद्दों को ज़रूर देखेंगे, लेकिन चुनाव के परवान चढ़ते ही जनता के विकास के मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं. सिर्फ़ जाति धर्म, पैसा, पावर का बोलबाला रह जाता है, लेकिन यूपी की जनता के असल मुद्दे इस बार भी चुनावी मुद्दे नहीं बन पाए. यूपी के तराई इलाक़ों और पूर्वांचल में हर साल बारिश तबाही लेकर आती है. घाघरा, राप्ती, बूढ़ी गंडक, सरयू, कुआनो, शारदा नदियों का क़हर मीलों तक गांवों को डुबो देता है. बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती से लेकर पीलीभीत, लखीमपुर तक नेपाल से आने वाला बाढ़ का पानी लोगों का जीना मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से लाखों लोग घर बार छोड़कर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. एक तिहाई से ज़्यादा कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है, जो यहां की बदहाली की वजह है. लेकिन विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा न तो किसी कैंडिडेट और न ही किसी सियासी पार्टी के एजेंडे में है. दूसरी तरफ़ किसानों की आत्महत्याएं पिछले 5–6 वर्षों में बुंदेलखंड में सूखे के कारण हताशा और ग़रीबी के चलते सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली. हालात से जूझने में नाकाम तमाम लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए. राहुल गांधी से लेकर मनमोहन सिंह, मायावती, उमा भारती, मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता वहां जाते ज़रूर हैं, लेकिन चुनाव यहां की बदहाली के मुद्दे पर नहीं, बल्कि अलग सूबे की मांग या पैकेज पर लड़ा जाता है. राज्य के पूर्वांचल इलाक़े में दिमाग़ी बुख़ार से अब तक हज़ारों बच्चों की मौत हो चुकी है. यह मुद्दा विधानसभा में क़रीब पचास बार तक उठाया जा चुका है. दिल्ली दरबार तक भी धमक पहुंची. पांच साल तक विपक्ष भी इस सवाल पर सरकारों को कठघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश करता है, पर चुनाव के समय किसी की सभा में यह सवाल नहीं उठता और न ही इस मुद्दे पर कोई वोट मांगने का हौसला जुटाता है. इसके अलावा पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच का सवाल लंबे अरसे से लटका पड़ा है. विधानसभा में कई बार मुद्दा उछल चुका है. पश्चिमी यूपी के वकील हर साल इस मुद्दे को लेकर हड़ताल पर जाते हैं. अभी भी इस मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है. ज़ाहिर है, सियासी पार्टियां सिर्फ़ वैसे ही मुद्दे को हवा देती है जिससे तुरंत उन्हें फ़ायदा हो जाए, यानी वोट मिल जाए, यानी हींग लगे न फिटकरी रंग आए चोखा. किसान या बाढ़ के सवाल पर अगर वे वोट मांगेंगे तो फिर उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा. उन्हें जवाब देने से ज़्यादा आसान इमोशनल इश्यूज उठाना लगता है.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

प्रदेश में संभवतः बहुत कम ऐसी पंचायतें होंगी, जहां मुखियाओं पर ग़लत तरीक़े से धन उगाही करने और भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों.

बिहार में पंचायती राज नहीं, मुखियाराज है

ग्राम कचहरी का असल मक़सद ग्रामीणों को गांव में ही न्याय दिलाना था, लेकिन आम लोगों को न्याय मिलना तो दूर आज बिहार की हज़ारों ग्राम कचहरियां अपने लिए ही न्याय मांग रही हैं. वर्ष 2006 में हुए त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच पद के लिए भी चुनाव हुए थे. एक उम्मीद के साथ लोग सरपंच बने, लेकिन धीरे-धीरे इस पद से उनका मोहभंग होने लगा. वित्तीय अधिकार विहीन, सीमित न्यायिक अधिकार और ग्राम कचहरी के लिए एक अदद भवन का न होना, बिहार में ग्राम न्यायालय के साथ एक क्रूर मज़ाक़ ही कहा जा सकता है.

अभिषेक रंजन सिंह

एक समय सरपंच ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था, लेकिन बिहार में इस पद की अहमियत कम होने लगी है. लगभग ढाई दशक बाद बिहार में वर्ष 2001 में पंचायत के चुनाव हुए तो लोगों को लगा कि ग्राम स्वराज का जो सपना महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देखा था, वह साकार होने वाला है. काफ़ी अरसे बाद बिहार में पंचायतों के चुनाव हुए और हज़ारों जनप्रतिनिधि भी जीते, लेकिन इस जीत में अंततः गांव हार गया. मौजूदा समय में बिहार की ग्राम पंचायतें पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी हैं और इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं निरंकुश मुखिया. सुशासन की दुहाई देकर दूसरी बार सत्ता संभालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सबके बावजूद ख़ामोश हैं. अगर उनकी चुप्पी टूटती भी है तो वह दो-चार घोषणाएं कर अपनी फ़र्ज़ अदायगी कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर पिछले साल मुख्यमंत्री ने पंचायतों में मची लूट रोकने के लिए लोकप्रहरी नियुक्त करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कहीं कोई नियुक्ति होने की ख़बर नहीं है. इसे मुख्यमंत्री की लाचारी कहें या सब्ज़बाग़ दिखाने की उनकी आदत.

पिछले साल जब पंचायत के चुनाव हुए तो सरपंच पद के लिए मुखिया पद की तुलना में कम लोगों ने उम्मीदवारी के नामांकन भरे. जहां मुखिया के एक पद के लिए औसतन दस लोगों ने नामांकन किया, वहीं सरपंच पद के लिए महज़ चार लोगों ने ही नामांकन दाख़िल किए. इससे यह बात साबित हो जाती है कि मुखिया बनने के लिए यहां कितनी मारामारी है. राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक़, पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए 79,423 लोगों ने चुनाव लड़ा, वहीं सरपंच पद के लिए 36,560 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरे. इसकी वजह साफ़ है कि सरपंचों के पास कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं है, जबकि मुखियाओं का विकास योजनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण है, जिनसे मोटी कमाई होती है. राज्य में एक कहावत अमूमन कही जाती है कि केंद्र में पीएम, स्टेट में सीएम, डिस्ट्रिक में डीएम और पंचायत में मुखिया ही पावरफुल हैं. गांव की बैठकों में कही जाने वाली ये बातें बिहार में अक्षरशः सत्य साबित हो रही हैं.

प्रदेश में संभवतः बहुत कम ऐसी पंचायतें होंगी, जहां मुखियाओं पर ग़लत तरीक़े से धन उगाही करने और भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों. हालांकि कई दाग़ी मुखिया गिरफ्तार भी हुए हैं, जिन्होंने शिक्षक भर्ती, मनरेगा, इंदिरा आवास, वृद्धापेंशन जैसी योजनाओं में जमकर लूट मचाई. भोजपुर निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता सूरज प्रकाश पांडे ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दाह संस्कार के लिए मिलने वाली राशि में भी मुखिया कमीशन लेते हैं. इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है. पढ़े-लिखे लोग जब सुनते हैं कि दूसरे राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार मिलता है, लेकिन उसमें बिहार के पंचायत प्रतिनिधि के नाम शामिल न होने पर उन्हें बेहद तकलीफ़ होती है. बिहारवासियों को ऐसी सुखद अनुभूति तभी मिलेगी, जब उनके पंचायत प्रतिनिधि भी स्वार्थ और लालच से ऊपर उठकर ग्रामीण विकास के लिए समर्पित होंगे. बिहार में सरपंच के पास अर्द्ध न्यायिक शक्तियां हैं. वहीं पंच की तो कोई ख़ास पूछ भी नहीं है. यही वजह रही कि कई पंचायतों में काफ़ी संख्या में पंच निर्विरोध चुन लिए गए. हालांकि यह लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई के लिए अच्छा संकेत नहीं है. अगर हालात ऐसे ही बने रहे और सरपंचों की उपेक्षा इसी तरह होती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अगले चुनाव में काफ़ी तादाद में सरपंच भी निर्विरोध चुन लिए जाएं.

मुखियाओं की पहली पसंद सोलर लाइट

अगर आप बिहार जाएं तो आपको हर गांव में जगह-जगह लोहे के खंभे पर टिकी सोलर लाइट दिख जाएगी. पहली नज़र में आप यह सोचकर बेहद ख़ुश होंगे कि अंधेरे में डूबे रहने वाले बिहार के गांव की तस्वीर बदल गई है, लेकिन शाम ढलते ही हो सकता है आपकी यह सोच बदल जाए, क्योंकि यहां जो सोलर लाइटें लगी हैं, उनमें ज़्यादातर ख़राब हैं. कुछ चोरी हो गई हैं और बहुत सारे खंभे अब गाय-भैंस और बकरी बांधने के काम आ रहे हैं. दरअसल, ग्रामीण विकास के तहत मिलने वाली धनराशि में एक बड़ा हिस्सा हमारे माननीय मुखिया ने सोलर लाइट लगाने के नाम पर ख़र्च किया. पूरे राज्य में हज़ारों की संख्या में सोलर लाइटें लगाई गईं. इसे आप सोलर क्रांति भी कह सकते हैं, लेकिन इस सोलर लाइट क्रांति के अर्थशास्त्र को समझना बेहद ज़रूरी है. दरअसल सोलर लाइटें लगाने से गांव भले ही रौशन न हुआ हो, लेकिन मुखिया जी का घर ज़रूर रौशन हो गया. जिस योजना में बंपर कमीशन मिले तो भला कौन मुखिया इसे ठुकराना चाहेगा. इस काली कमाई में केवल मुखिया ही शामिल नहीं हैं, बल्कि ब्लॉक में बैठे बीडीओ और पंचायत सचिव भी मालामाल हो गए.पचायत में मुखिया के अधीन शिक्षक नियोजन, सोलर लाइटें लगाने की योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, बाढ़-सूखा से बर्बाद हुई फ़सल के मुआवज़े की राशि, कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि, छात्रवृत्ति की राशि का वितरण करने समेत ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाएं हैं. इन सभी योजनाओं में किस तरह ग़ैर बराबरी कर उसमें अनियमितता बरती जाती है, यह किसी से छुपा नहीं है. इसे काली कमाई का ही असर कहें कि जो मुखिया कल तक पैदल, साईकिल या रिक्शा से चलते थे, वे अब बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ी से चलने लगे हैं. साथ में जब उनके सिपहसलार हाथ में राइफल लिए चलते हैं तो मुखिया का वास्तविक रुतबा देखते ही बनता है. यह हमारी व्यवस्था का एक शर्मनाक पहलू है, जब मुखिया जनता के धन पर ऐशो-आराम और सामंती आचरण के साथ जी रहा है, वहीं आम आदमी बुनियादी सुविधाओं तक को तरस रहा है.

ग्रामसभा की बैठक या मुखिया दरबार

जिस तरह संसदीय लोकतंत्र में संसद और विधानसभा की भूमिका है, उसी तरह लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की अहमियत है, लेकिन बिहार के अधिकतर पंचायतों में ग्राम सभा महज़ काग़ज़ों पर ही संचालित हो रहे हैं. कितनी धनराशि किस मद में आती है और उसे कहां ख़र्च किया जाता है, ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं है. कहने को तो तमाम फ़ैसले ग्राम सभा की बैठकों में तय होते हैं, लेकिन जब ग्राम सभा ही कुछ लालची मुखिया, पंचायत सेवक और दबंग लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाए तो इस सूरत में यह कैसे उम्मीद करें कि गांव का विकास सही मायनों में होगा. बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के मुताबिक़, ग्राम सभा की बैठक नियमित बुलानी चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन भी नहीं हो रहा है. नतीजतन मुखिया अपने चहेतों के साथ मिलकर अपने मनमाफिक काम करते हैं. पंचायतों में मची इस लूट को रोकने में ग्रामीण आबादी चाहे तो अहम भूमिका निभा सकती है. इसके लिए जनता तो अपने गांव में एक ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनना होगा, जो नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक कराए. पंचायत से जुड़े सभी फ़ैसले ग्राम सभा की खुली बैठक में करे. कोउ नृप हो हमें का हानि इस मानसिकता का त्याग ग्रामीणों को करना होगा, तभी एक बेहतर माहौल बनेगा और गांव का संपूर्ण विकास होगा.

ग्राम कचहरी को अपना भवन नसीब नहीं

वर्ष 2006 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे, उस वक़्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम-कचहरी को सशक्त बनाने को लेकर कई घोषणाएं की थीं. ग्राम कचहरी को लेकर नीतीश कुमार ने मीडिया के ज़रिये काफ़ी सुर्ख़ियां बटोरीं, क्योंकि बिहार देश का ऐसा पहला सूबा बना जहां ग्राम न्यायालय का सपना साकार हुआ. कई साल बीत गए, लेकिन बिहार में ग्राम कचहरी को अपना भवन आज तक नसीब नहीं हो सका. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपये की लागत से हर पंचायत में दो-मंज़िला पंचायत सरकार भवन बनाने की घोषणा की, लेकिन हक़ीक़त की धरातल पर यह योजना अभी तक उतर नहीं पाया है. यही वजह है कि भवन के अभाव में ग्राम-कचहरी या तो स्कूल के बरामदे, खुले मैदान या फिर किसी पेड़ के नीचे लगाए जा रहे हैं.

arsingh@chauthiduniya.com

डायस्पोरस या डायस्प्रोवेस

मातृभूमि का गौरव या कलंक कहना काफ़ी नहीं है

हाल में पिछले दशक में भारतीय प्रवासियों पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट–2001 आने के बाद से और भारतीय नीति के परिप्रेक्ष्य में मील का पत्थर साबित होने वाले कुछ संक्रमणों के साथ भारत सरकार दुनिया भर में फैले अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के अत्यंत कुशल भारतीय प्रवासियों को अपनी पहुंच के भीतर लाने का प्रयास कर रही है. नेहरू–इंदिरा युग की अतीत की उदासीनता को तोड़ने की कोशिश में यह सरकार उन्हें प्रतीकात्मक रूप में देशद्रोही न कहकर मातृभूमि के नए खोजे गए देवदूत के रूप में देखने का प्रयास कर रही है. 21वीं सदी में प्रतिभा पलायन के नकारात्मक स्वरूप की जगह उन्हें प्रतिभा लाभ जैसा सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है. ख़ास तौर पर भविष्य के संदर्भ में जब भारत को उदीयमान दक्षिणी अर्थव्यवस्था के नेतृत्व के लिए पेश किया जा रहा है, तो इस संभावना को अमलीजामा पहनाने के लिए वैश्विक आप्रवास के व्यवस्थापन के क्षेत्र में मात्र प्रवासियों को साथ लेकर चलना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ करना होगा?

भारतीय आप्रवासन में नया मोड़

21वीं सदी में, जैसा आज की प्रवृत्तियों से झलकता है, यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक आप्रवासन के प्रवाह की दिशा का निर्धारण मानव पूंजी की वैश्विक मांग से ही होगा. विकसित देशों में चौवन मिलियन कामगारों की अतिरिक्त मांग होगी, जिसे अमेरिकी जनगणना ब्यूरो–2002–2003 के अनुसार मोटे तौर पर भारत के सैंतालीस मिलियन कामगारों की अनुमानित अधिशेष सप्लाई से ही पूरा किया जा सकेगा. इन उम्मीदों के पीछे जो उत्साह है, उसका कारण यही है कि भारतीय प्रवासियों द्वारा जो पैसा भारत को भेजा जाता है, उसमें वृद्धि हो रही है और जब वे घर लौटते हैं तो उनके पास उच्च स्तर का कौशल और निवेश करने के लिए भारी बचत का ख़ज़ाना होता है, जिससे एक ही छलांग में महाशक्ति बनने का भारत का सपना साकार हो सकता है. लेकिन दो ऐसी अदृश्य चेतावनियां हैं, जिनके कारण भविष्य में इसकी संभावना धूमिल होती सी लगती है.

पहली चेतावनी तो यह है और इस तथ्य की अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है कि विदेशों में बसे भावी भारतीय प्रवासियों द्वारा हाल में विदेशी भारतीय छात्र अध्ययन निधि के रूप में विकसित देशों की ओर संभावित धन प्रेषण के चुपचाप समुद्री तरंग की तरह वापस आने की प्रवृत्ति के कारण इसके प्रवाह में रुकावट आने की संभावना है. एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ऑफ़ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, धनप्रेषण का यह प्रवाह 7.5 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, जो भारत को भेजे जाने वाले वैश्विक धन प्रेषण का औसतन छठा भाग होगा.

दूसरी चेतावनी यह है कि कदाचित हमारे स्मृति पटल पर अभी भी ताज़ा है कि इस सदी के अंत में जब पिछली अमेरिकी मंदी के दौरान आईटी का गुब्बारा फूटा था तो बीपीओ के उदय के कारण भारतीयों की वापसी का तांता बंध गया था. बहुत कम लोगों को यह पता है कि जो लोग स्वदेश वापस लौटे थे, वे सर्वश्रेष्ठ डिग्रीधारी आईटी पेशेवर न होकर दूसरी पंक्ति के आईटी पेशेवर थे और इनमें से अधिकांश लोग स्वेच्छा से भारत नहीं लौट रहे थे, बल्कि मंदी की मार से ग्रस्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कारण नौकरी के ठेके का नवीयन न होने के कारण विवश होकर लौट रहे थे.

प्रवासियों की वापसी में हितों का अदृश्य टकराव

प्रवासियों की स्वदेश वापसी के अपने भी कई निहितार्थ हैं. यद्यपि गंतव्य देश के श्रम बाज़ार में प्रवासियों की संख्या कुछ प्रवासियों की घर वापसी के बावजूद बढ़ती रह सकती है और व्यक्तिगत स्तर पर उनके चेहरे बदलते रह सकते हैं, फिर भी गंतव्य समाज में जातीय संघर्ष का तत्व कम बने रहने की संभावना हो सकती है. प्रवासियों (या आप्रवासियों के आवागमन, जिसे आजकल प्रोत्साहित किया जा रहा है) की वापसी की स्पष्ट घोषित नीति के कारण, जिसमें विदेशियों के केवल अस्थायी निवास के अधिकार ही शामिल हैं, अनेक देशी नागरिकों के मन में आर्थिक दृष्टि से प्रतियोगिता से बाहर हो जाने का डर निकल जाता है. इसलिए स्वाभाविक रूप में ही संघर्ष की आशंका से ग्रस्त गंतव्य देश आगे बढ़कर प्रवासियों की वापसी और उनके आवागमन को बढ़ावा देते हैं.

दूसरी ओर अस्थायी आप्रवास के सामाजिक निहितार्थ, जिनमें आप्रवासियों और उनके परिवारजनों की अपने मूल देश में वापसी के नीतिगत प्रचार या प्रवासियों के आवागमन की बात निहित है, प्रवासियों के संसाधनों के रिसाव को रोकने के लिए उनके हितों में बाधक सिद्ध हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, किसी प्रवासी द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर घर लौटने के निर्णय में यह भी निहित है कि पहले वह स्वयं अपना ही उत्प्रवास चाहता है या चाहती है या अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों को भी अपने साथ ले जाना चाहता या चाहती है. जब काम पर अनुपस्थिति की छुट्टी विदेश में उसकी पत्नी/पति के काम के अनुरूप न हो तो क्या उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए? मूल देश में स्कूल में प्रवेश/पुन:प्रवेश की कठिनाई को देखते हुए क्या बच्चों का स्कूल छुड़वाना ठीक होगा? मोटे तौर पर आप्रवासियों के

प्रवासियों की स्वदेश वापसी के अपने भी कई निहितार्थ हैं. यद्यपि गंतव्य देश के श्रम बाज़ार में प्रवासियों की संख्या कुछ प्रवासियों की घर वापसी के बावजूद बढ़ती रह सकती है और व्यक्तिगत स्तर पर उनके चेहरे बदलते रह सकते हैं, फिर भी गंतव्य समाज में जातीय संघर्ष का तत्व कम बने रहने की संभावना हो सकती है.

लिए अंतरराष्ट्रीय पद को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा पारिवारिक होती है (62 प्रतिशत), उसके बाद भाषा की (13 प्रतिशत), मूल देश में वापसी की समस्याओं (8 प्रतिशत) की, सुरक्षा (5 प्रतिशत) की, लागत (5 प्रतिशत) की और जीवन स्तर (4 प्रतिशत) की.

आप्रवासन और प्रवासन के भावी संचालक

ज़ाहिर है कि मूल देश के प्रवासी न तो डायस्पोरस होते हैं और न ही डायस्प्रोवेस अर्थात वे अपनी मातृभूमि के न केवल गौरव होते हैं और न ही कलंक, बल्कि वे मैक्रो स्तर पर उत्प्रवास या भारत में वापसी के सच्चे संचालक होंगे. इसके बजाय पारदेशीय श्रम बाज़ार के गंतव्य स्थल पर वे ऐसे दीर्घकालीन रणनीतिक कारक हैं, जो उनका निर्धारण करेंगे. इन सामान्य रणनीतियों को तीन याद रखने लायक़ लयबद्ध शब्दों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एज, वेज और विंटेज अर्थात आयु, मज़दूरी और विंटेज.

एज अर्थात आयु, आयु के संरचनागत परिवर्तन के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने का काम करती है, जिसे वापस लौटे हुए प्रवासियों के उन युवा साथियों के ज़रिये संपन्न किया जा सकता है, जो दूसरी या तीसरी बार आप्रवास कर रहे होते हैं. बड़ी आयु के वापस लौटे हुए प्रवासी अपने मूल देश में ही बस जाना चाहते हैं और पुराने कामगारों के झुंड के साथ जुड़ जाना चाहते हैं. दूसरी रणनीति है वेज अर्थात मज़दूरी की, जिसका अर्थ है तुलनात्मक लागत का लाभ, जिसे मूल देश ने वैश्विक व्यापार करते हुए तब खो दिया था जब दोबारा वापस लौटे हुए युवा प्रवासी अपनी कम मज़दूरी, भत्तों और पेंशन के सामाजिक लाभ को साथ लेकर गंतव्य देशों में गए थे और वापस लौटे हुए बड़ी आयु के प्रवासी उत्पादन की लागत में उसे जोड़ देते हैं और इस प्रकार यह लागत उनके द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं में जुड़ जाती है. इसके अलावा यह लागत परोक्ष रूप में मज़दूरी, भत्तों और पेंशन को कम करके भारत के बाहर प्रेषित धन के प्रवाह को शांत रूप में तरंगित होकर वापस लौट आती है, जिससे प्रवासी की धन–प्रेषण क्षमता का निर्धारण होता है. तीसरा रणनीतिक निर्धारक है, विंटेज जिसका अर्थ है युवा छात्र प्रवासी पीढ़ी की अधुनातन तकनीकी जानकारी व कौशल और नवीनतन पाठ्यक्रम तक उसकी पहुंच. इससे उनकी पढ़ाई पूरी होने और पेशेवर बनने से पहले ही यह अनुमान लगाया जा सकता है और इससे यह तथ्य सामने आता है, जिसे अर्ध निर्मित मानव पूंजी का पूर्व–प्रवासन कहा जा सकता है.

विश्व को नेतृत्व प्रदान करने के लिए नया भारतीय परिप्रेक्ष्य

आप्रवास नीति के परिवर्तन की अस्थिरता और आप्रवासियों को संभालने के लिए कॉन्सुलर परिपाटियों में अनौपचारिक विचलन का मनमानापन–दो ऐसे तत्व हैं, जो नीतिगत प्रवृत्तियों को रूपायित करने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हस्तक्षेप के लिए आवश्यक आप्रवासन को शासित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित क्षेत्र हैं. जब भी बहुपक्षीय वार्ताएं शुरू होती हैं, जिनमें दोनों ही देशों के नीति–निर्माता और बुद्धिजीवी एक साथ खड़े होकर अन्य देशों के निर्णयों की पैरवी करके या नैतिक दबाव डालकर प्रभावित कर सकते हैं, उस समय दुर्भाग्यवश यह एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, जिसे दो देश अपरक्राम्य प्रभुता संपन्न क्षेत्र मानते हैं. इन परिस्थितियों में यह सवाल उठता है कि क्या भारत, जिसे दुनिया आरएससी के रूप में निहार रही है और जिसमें आप्रवासियों का विकासशील स्त्रोत देश होने के नाते संभावित महाशक्ति के रूप में संक्रमित होने की संभावना है, विकसित देशों को यह दिखाना आरंभ कर सकता है कि आप्रवासन की नीतियों और परिपाटियों को किस प्रकार प्रवासी केंद्रिक बनाया जा सकता है. इस प्रकार से भारत के वैश्विक नेतृत्व ग्रहण करने का संकेत इस बात से मिल सकता है कि भारत ने अपने प्रवासियों के प्रति अतीत की अपनी उदासीनता को जिस तरह से ख़त्म किया है और अब उनके प्रति प्रत्यक्ष रूप में सकारात्मक रुख़ अपना रहा है और अब एक और बड़ा क़दम उठाकर विश्व में सुरक्षा: आप्रवासन केंद्रिक नीतियों और परिपाटियों के नाम पर आगे बढ़ने वाले विश्व में आप्रवासन की नीतियों के उदारीकरण के समर्थन में अब तक जिसका वह प्रचार करता रहा है. अब उन भावी प्रवासियों के लिए जो अनिवार्यत: विदेशों में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में भारत का वीज़ा लेने के लिए आते हैं और फिर मैत्री भाव से भारत के अंदर भारतीय आप्रवासन के उन चैक पोस्टों के संपर्क में रहते हैं, जहां से वे सबसे पहले इस देश में आए थे, उन पर आचरण भी कर रहा है. यह महाशक्ति के रूप में वैश्विक रूप में उभरने वाले भारत की वास्तविक पहचान होगी और भारतीय प्रवासियों की सीमित शक्ति से कहीं आगे बढ़कर उन्हें विश्व नागरिक के रूप में पहचान देने वाला क़दम सिद्ध होगा और इसी प्रक्रिया में उन तमाम देशों के लिए जो अंधकार में डूबने के कारण विश्व की बिरादरी से बाहर होकर अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, प्रकाश पुंज के रूप में उभर रहा है. दुर्भाग्यवश, भारत की वीज़ा नीति की नवीनतम प्रवृत्ति से ऐसा लगने लगा है कि भारत भी अपनी पहचान बनाने के बजाय अन्य देशों की भीड़ में खोता जा रहा है.

बिनोद खडरिया
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं.)

आप्रवास नीति के परिवर्तन की अस्थिरता और आप्रवासियों को संभालने के लिए कॉन्सुलर परिपाटियों में अनौपचारिक विचलन का मनमानापन-दो ऐसे तत्व हैं, जो नीतिगत प्रवृत्तियों को रूपायित करने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हस्तक्षेप के लिए आवश्यक आप्रवासन को शासित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित क्षेत्र हैं.

हिसाब-किताब के मामले में रोकड़-बही-खाता इत्यादि सब ही तरह के क्लर्की के कामों में ये मध्यमवर्गीय लोग ही दक्ष होते थे.

पूंजी-विकास के माध्यम

महावीर प्रसाद आर मोरारका

इस परिस्थिति को संभालने के लिए, जैसा स्वाभाविक है, एक तीसरी श्रेणी, जो इन दो श्रेणियों का जोड़-तोड़ बैठा सके, खड़ी हुई. यह तीसरी श्रेणी मध्यम श्रेणी के नाम से पुकारी जाती है. यह मध्यम श्रेणी किस तरह से उत्पन्न हुई, इसका भी विचित्र इतिहास है. राजा, ठाकुर या जमींदार भूमि के स्वामी थे. मान लीजिए, एक भू-स्वामी की 10 हज़ार एकड़ ज़मीन हो. उसके लगान महसूल या पैदावार से वह नितांत धनिक समझा जाता था. समय पाकर उसके 5 लड़के हो गए, फिर उन 5 लड़कों में से हर एक के 4-4 या 5-5 लड़के पैदा हो गए. तो आप समझ लीजिए, तीसरी पीढ़ी तक अगर ज़मीन का बंटवारा होता रहे तो दस हज़ार एकड़ भूमि के बदले कुछ सौ एकड़ भूमि ही 1 व्यक्ति के पास रह जाएगी. परिणामत: जो दादा या परदादा नितांत धनिक समझे जाते थे, उनके पौत्र या प्रपौत्र दरिद्र की कोटि में गिने जाने लगे. भारत में लड़कियों को या स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार पहले था नहीं. इसलिए उदाहरण में सिर्फ़ लड़कों का ही जिक्र है. उस समय के समाज ने यह परिस्थिति देखकर यह नियम सा बना लिया कि उस ठाकुर, राजा या जमींदार का जो ज्येष्ठ पुत्र (सबसे बड़ा लड़का) हो, वही उसकी ज़मीन, साम्राज्य या जागीर का उत्तराधिकारी हो, बाक़ी सब छोटे भैय्या खाने पीने जितनी वार्षिक रकम ही प्राप्त करें. यह व्यवस्था उस समय के समाजशास्त्रियों ने संपत्ति को बिखर जाने से रोकने के लिए बनाई थी. वे जो छोटे भैय्या होते थे, उन्हें शिक्षा तो उच्च कोटि की मिली हुई थी, साथ ही उनका जीवन स्तर, रहन-सहन, आदत-व्यवहार सब ही उन बड़े आदमियों की तरह का होता था, जो पूंजीपति या जमींदार थे.

पूंजी को कहां लगाना ज़्यादा लाभप्रद होगा, किस जगह कितनी पूंजी का उपयोग हो, यह निर्णय भी अधिकतर ये ही लोग करते थे. इस तरह से यह मध्यम श्रेणी कालांतर में दोनों श्रेणियों से ज़्यादा महत्व का स्थान ग्रहण कर गई और इस श्रेणी के बिना धनिक वर्ग और मज़दूर वर्ग दोनों ही अपने आपको असहाय समझने लगे. स्वाभाविक है कि जिस श्रेणी का या वर्ग का समाज में महत्व होता है, उसी श्रेणी या वर्ग में शरीक होने की हर आदमी इच्छा रखता है.

अब, जबकि इन जमींदारों और पूंजीपतियों को अपने काम कराने के लिए मज़दूरों तथा सेवकों की आवश्यकता होती तो वे इतने परवश और दिग्विमूढ़ हो जाते कि यह सब उनके वश के बाहर की बात लगने लगती. ये छुटभैय्या ये सब काम कर लेते थे. एक तरफ़ पूंजीपति श्रेणी को सेवक या मजदूर उपलब्ध करा देना और दूसरी तरफ़ मजदूरों को रोटी-वस्त्र के एवज में काम उपलब्ध करा देना. यही काम प्रधानत: ये छोटे भैय्या या मध्यम-पंथीय लोग किया करते थे. अपने पारिश्रमिक के रूप में ये लोग हर वस्तु का हिस्सा बंटवा लेते. वे पूंजीपति धनाढ्य जैसे-जैसे अधिक समृद्ध होते गए, अधिक अकर्मण्य भी होते गए. अपने कार्य का भार ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्हीं कारिंदों, मुनीमों या मुसाहिबों पर डालने लगे. हिसाब-किताब के मामले में रोकड़-बही-खाता इत्यादि सब ही तरह के क्लर्की के कामों में ये मध्यमवर्गीय लोग ही दक्ष होते थे. सारा बंदोबस्त या इंतज़ाम इन्हीं के हाथ में होता. ज़मीन का लगान वसूल करने का काम, कितनी ज़मीन किसको जोतने के लिए देनी है, इसका सारा लेखा-जोखा ये ही रखते थे. इसके सिवाय बाकी मकान अथवा जायदाद के भाड़े की आय का या पूंजी के ब्याज की आय का लेखा-जोखा ये मध्यम श्रेणी वाले लोग करते.

पूंजी को कहां लगाना ज़्यादा लाभप्रद होगा, किस जगह कितनी पूंजी का उपयोग हो, यह निर्णय भी अधिकतर ये ही लोग करते थे. इस तरह से यह मध्यम श्रेणी कालांतर में दोनों श्रेणियों से ज़्यादा महत्व का स्थान ग्रहण कर गई और इस श्रेणी के बिना धनिक वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों ही अपने आपको असहाय समझने लगे. स्वाभाविक है कि जिस श्रेणी का या वर्ग का समाज में महत्व होता है, उसी श्रेणी या वर्ग में शरीक होने की हर आदमी इच्छा रखता है. कालांतर में उसी मज़दूर, किसान या ग़रीब वर्ग में से भी कई लोग मध्यम वर्ग में शामिल होने की कोशिश करने लगे. ग़रीबों के लिए विद्याध्ययन संभव नहीं था. आज से 100 वर्ष पूर्व भारत का कोई मजदूर या किसान अगर लिखना-पढ़ना जान जाता तो महान चमत्कार समझ लिया जाता था. उनको पढ़ने देना उच्च वर्ग वाले कभी गवारा नहीं कर सकते थे. शुरू-शुरू में काफी कठिनाइयां उपस्थित हुईं. अंग्रेजों के राज में जब क्रिश्चियन मिशनरी ने हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्मावलंबियों को ईसाई बना-बनाकर शिक्षा देना और स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया तो धीरे-धीरे यह भावना कि ग़रीबों को विद्या या शिक्षा का अधिकार नहीं है, समाप्त हो गई. जब ये लोग पढ़-लिखकर शिक्षित हुए तो इनमें से अधिकांश मध्यम श्रेणी में अपने आप शामिल हो गए. उनको श्रमजीवी काम के अलावा ऑफिस में बैठकर लिखा-पढ़ी का काम मिल गया. उधर धनिक वर्ग, जो अपने आपको असहाय समझने लगा था, उसने भी हाथ से काम करने की प्रवृत्ति अपनाई और कई मायनों में वे भी अपने को उसी मध्यम श्रेणी के नागरिक मानने लगे.

इस मध्यम श्रेणी वाले कार्यकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा रही है व्यापारी वर्ग से. व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार करता है और विद्या, बुद्धि या कला में बहुत नीचे दर्जे का होता हुआ भी इन मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों से कई गुना ज़्यादा रकम कमा सकता है. एक व्यापार में कुछ भी हिकमत करके लाखों के वारे-न्यारे कर सकता है. यह ईर्ष्या ज़रूरी रही. स्त्रियों का स्थान भारत में 20-25 वर्ष पहले तक एकदम उपेक्षित और शोषित ही रहा था. भारत पुरुष प्रधान समाज का अगुवा था. स्त्रियों को दासी या अधीन के ही स्वरूप में देखा या माना जाता था. आज भी पर्याप्त मात्रा में वह प्रक्रांत है. अंततोगत्वा उनका शोषण पुरुष जाति ने किया ही है.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

बढ़ती जनसंख्या अभिशाप नहीं

आम तौर पर यह धारणा बनी हुई है कि जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है. इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है. आर्थिक दृष्टिकोण के सभी पैमाने भी इसी की पुष्टि करते हैं. अर्थशास्त्रियों की परिभाषा का निष्कर्ष यही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही खाद्यान्न की कमी होती है, क्योंकि जिस अनुपात में आबादी में इज़ाफ़ा होता, उस अनुपात में पैदावार नहीं हो पाती है. इसलिए जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो या अर्द्ध विकसित अथवा अल्प विकसित राष्ट्र.

माना जाता है कि दुनिया भर में बढ़ती ग़रीबी की जड़ जनसंख्या वृद्धि में निहित है. इसके कारण एक तरफ़ जहां जन सेवाएं चरमरा रही हैं, वहीं बेरोज़गारी और भूख भी भयंकर रूप दिखा रही है. खाद्यान्न संकट और यहां तक कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बढ़ती जनसंख्या को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है. भारत समेत समूचा विश्व इस पर चिंता जताता रहा है और नियंत्रण के सभी फार्मूले अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विश्व के अधिकतर अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि बढ़ती आबादी पर नियंत्रण से ही विकास संभव है. इसके पीछे मज़बूती के साथ यह तर्क दिया जाता है कि कम लोगों में सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान किया जा सकता है, जो अधिक जनसंख्या में मुमकिन नहीं है.

जनसंख्या वृद्धि के इस नकारात्मक पहलू के अतिरिक्त एक पहलू और भी है. वर्तमान परिदृश्य में इसे श्राप की जगह वरदान के रूप में देखा जाना चाहिए. अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अनुसार मानव शक्ति ही आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है. श्रमिक अर्थात मानव शक्ति को संपत्ति का सृजक माना जाता है. श्रमिक उत्पादन का सक्रिय साधन है, जो प्रकृति प्रदत्त साधनों तथा अन्य निष्क्रिय साधनों जैसे पूंजी को सक्रिय बनाता है और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है. मनुष्य उत्पादक के साथ-साथ उपभोक्ता भी होता है. अत: जनसंख्या दूसरे उत्पादक कार्यों के विस्तार तथा उद्योगों की बनी चीज़ों के लिए ग़ैर बाज़ार मांग का सृजन करता है. इस तरह मानव शक्ति साधनों के प्रयोग एवं उद्योगों के अलावा ग़ैर कृषि क्षेत्र में बनी वस्तुओं के लिए भी बाज़ार उपलब्ध कराता है और श्रमिकों की आपूर्ति द्वारा देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है.

भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है. यहां की तेज़ी से बढ़ती आबादी पर लगातार चिंता जताई जाती रही है. विश्व क्षेत्रफल के 2.7 प्रतिशत भारतीय भू-भाग पर विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यह संख्या एक अरब 22 करोड़ से भी अधिक है तथा इसमें 1.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है. तथ्य बताते हैं कि आबादी के बढ़ने की यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ वर्षों में यह चीन को भी पीछे छोड़ देगी, परंतु यही जनसंख्या वृद्धि हमारे विकास के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार, विश्व की क़रीब आधी जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है जिसका अधिकांश भाग भारत में निवास करता है, जबकि विकसित देशों में बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है और काम करने वाले ऊर्जावान शक्ति की कमी हो रही है. यही कारण है कि भारतीय युवा देश और दुनिया के लिए उत्पादकता की नई मिसाल क़ायम कर रहे हैं और विश्व की सभी कंपनियां इन्हें श्रेष्ठतम मानव संसाधन की संज्ञा दे चुकी हैं. शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर आधारित जनसंख्या नीति ने इस पीढ़ी की तैयारी की, जो आर्थिक तरक्क़ी की सूत्रधार साबित हो रही है. भारतीय जनगणना की पश्चिम बंगाल इकाई के निदेशक विक्रम सेन के अनुसार, देश जनसंख्या के लाभदायक चरण में पहुंच रहा है. आज भारत में लगभग आधी आबादी 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग की है, जो ऊर्जावान है, जिनकी क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सकता है. यह स्थिति वर्ष 2045 तक बनी रहेगी, वहीं आश्रितों की संख्या में कमी के कारण जनसंख्या का यह चरण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक साबित होगा. ख़ास बात यह है कि बढ़ती जनसंख्या पर चिंता के साथ-साथ सरकार द्वारा लगातार शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने भी भारतीय युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने में भरपूर मदद की है. इस संदर्भ में विक्रम सेन का तर्क है कि शिक्षा बेहतरीन अर्थव्यवस्था और नियंत्रित आबादी की कुंजी है.

गुणात्मक एवं प्रतिभा संपन्न युवाओं का यह वर्ग भारत को विश्व का सबसे बड़ा मानव संसाधन निर्यातक एवं रोज़गार आयातक दोनों ही बना रहा है. यह जल्द ही अंतरराष्ट्रीय सेवा कारोबार के 37 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लेगा, जो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को चीन से आगे ले जा सकता है. यही कारण है कि आबादी के लिए भारत को कोसने वाले विश्व को आज इसकी युवा क्षमता से जलन हो रही है. विस्तृत रूप से देखा जाए तो हर सार्वजनिक मंच पर जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जताई जा रही है, वही आबादी संकट की बजाय संकट मोचक साबित होती रही है. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविड कैनन के अनुसार जो मनुष्य जन्म लेता है, वह अपने मुंह और पेट के साथ-साथ काम करने के लिए दो हाथ भी लाता है, जिससे अधिक श्रमशक्ति के प्रयोग द्वारा कृषि और उद्योग की उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है और इसे भारतीय युवा पीढ़ी सच साबित कर रही है.

डॉ.गज़ाला ऊर्फी
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

सौर ऊर्जा के दोहन की ज़रूरत

अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का दोहन किया जाना अति आवश्यक है. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने कहा है कि आज दुनिया में मनुष्यों द्वारा जितनी ऊर्जा की खपत होती है, उसकी तुलना में क़रीब दस ट्रिलियन गुना ऊर्जा सूर्य अपनी किरणों के ज़रिए बिखेरता है. अगर ऊर्जा की इस मात्रा का छोटा सा भाग हम निकाल सकें तो यह भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी. ऊर्जा संरक्षण की दिशा में यह एक बेहतर सुझाव है, किंतु दु:ख इस बात का है कि देश के कई गांवों, शहरों में बिजली की आपूर्ति दिनोंदिन घटती जा रही है. शायद इसका कारण जल-कोयला आदि का हमेशा अभाव होना रहा है. बिजली कम मिलने से कई गांव-शहर इनवर्टरों पर आश्रित हो गए हैं. छोटे गांवों में मोबाइल टार्च, चिमनी कंदील एवं गैस कंदील द्वारा उजाला प्राप्त किया जा रहा है. ज़रा सोचिए, कम बिजली से हमारी ज़िंदगी में एक प्रकार का तनाव पैदा हो रहा है. शासकीय, घरेलू, व्यापार एवं कृषि आदि से जुड़े कार्यों की गति भी धीमी हो गई है. जब बिजली शत-प्रतिशत मिलने लगेगी, तब समझा जाएगा कि देश-प्रदेश का संपूर्ण विकास हुआ. यह सब सौर ऊर्जा के दोहन से ही संभव हो सकेगा.

–संजय वर्मा दृष्टि, *मनावर, मध्य प्रदेश.*

अदालत का प्रशंसनीय क़दम

अश्लीलता फैलाने, आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित एवं प्रसारित करने को लेकर दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसी कई विदेशी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और अन्य पोर्टलों को आपराधिक समन जारी करके एक प्रशंसनीय क़दम उठाया है. उक्त सोशल साइट्स अश्लीलता फैलाने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का माध्यम बन रही हैं. विभिन्न धर्मों के महापुरुषों के ख़िलाफ़ इन पर ज़हर उगला जा रहा है. ऐसे में इन पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी हो गया है.

–असलम ख़ान, *दिल्ली.*

अश्लील फोटो से परहेज़ करें

चौथी दुनिया देखा. सफ़ेदपोशों को बेनक़ाब करने का कार्य प्रशंसनीय है. आपसे एक अनुरोध है कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की अश्लील फोटो से परहेज़ करें, ताकि अख़बार का स्तर सही रहे.

–समीर गुप्त, *बदायूं, उत्तर प्रदेश.*

बिना दबाव के मतदान करें

लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार. लोकतंत्र में जनता यानी मतदाता सर्वोच्च है और नेता एवं प्रशासक जन-सेवक हैं. वे जनता के लिए हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं. इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बिना किसी लालच या दबाव के मतदान करें, क्योंकि ऐसा करने पर ही योग्य जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो बेहतर सरकार दे पाएंगे.

–कुलदीप सिंह परमार,
कानपुर

ख़बरों का खेल

आजकल तो ख़बरों का भी खेल होता है
प्रकाशकों में भी अक्सर मेल होता है,
मीडिया के संवाददाता भी वहीं पहुंचते हैं
जहां तिलों में तेल होता है,
बाहुबली नेता, असरदार अभिनेता, बड़े उद्योगपति
सब मीडिया की नज़रों में रहते हैं,
आम आदमी के पास कोई नहीं जाता
बड़े नेता और चमचे ही ख़बरों में रहते हैं,
नए-नए टीवी सीरियल और फिल्मों की चर्चा
किस अभिनेत्री ने कितना किया मेकअप पर ख़र्चा,
प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जनसेवा का पर्चा,
ख़बरों का खेल देख जनता का दिल रोता है
क्या मिलता है किसी को, हर व्यक्ति सिर्फ़ खोता है,
देवी-देवता भी ख़ामोश तमाशा देख रहे हैं दूर से
लंबी तानकर विधाता भी गहरी नींद में सोता है.

–सीताराम शर्मा, *सीकर, राजस्थान.*

ग़ैर मुस्लिम देशों को मिटाने की साज़िश

आलेख पाक-अमेरिका का तनाव स्थायी नहीं पढ़ा. भारतीय समाचार पत्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी भी भारत-चीन, पाकिस्तान-अमेरिका के संबंधों पर ही विश्लेषण करते हैं. भारतीय पत्रकारों को विश्वस्तरीय राजनीति को समझ कर ही अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीति की समीक्षा करनी चाहिए. अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हथियारों की बिक्री करना चाहता है. चीन सस्ते मज़दूरों से तैयार सस्ते उत्पादों को विश्व भर में बेचना चाहता है. अरब समर्थित पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन एवं जापान जैसे देशों का गठबंधन ग़ैर मुस्लिम देशों को मिटा देना चाहता है.

–परमानंद मिश्र, *चंपारण, बिहार.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जनता भोली होती है, बेवकूफ़ नहीं

उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल क्या है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में किन सवालों के जवाब जनता देगी. इसके बारे में सिर्फ़ इतना कहना चाहते हैं कि जिन सवालों पर जनता को जवाब देना चाहिए, वे सवाल जनता के सामने नहीं लाए जा रहे हैं. जिन सवालों पर जनता को ख़ामोश रहना चाहिए, वे सवाल उनके सामने लाए जा रहे हैं. लोगों के इमोशन से भी खेलने की कोशिश हो रही है. सवाल चाहे जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, हर तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. जनता भोली होती है, लेकिन मूर्ख नहीं होती है. वे सारे सवाल, जिनका उनकी ज़िंदगी से मतलब नहीं है, उन्हें उठाना आम आदमी को बेवक़ूफ़ समझने का भ्रम पालना है. ऐसा ही एक सवाल मुस्लिम रिजर्वेशन का है. सरकार की तरफ़ से घोषणा हुई कि मुसलमानों को साढ़े चार फ़ीसदी रिजर्वेशन दिया गया है. यह रिजर्वेशन सारे देश के मुसलमानों के लिए घोषित हुआ है. वक़्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रखा गया, ताकि उस घोषणा का फ़ायदा मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उठाया जा सके. शब्द इस्तेमाल हुआ मुस्लिम रिजर्वेशन और इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी, जबकि दोनों पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं कि यह रिजर्वेशन, जो केंद्रीय सरकार ने 27 प्रतिशत के रिजर्वेशन के अंदर दिया है, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए है. इसमें ईसाई, सिख और जैन भी आते हैं. यह सब जानने के बावजूद मुस्लिम रिजर्वेशन शब्द इस्तेमाल हुआ. भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द का इस्तेमाल ग़ैर मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए किया, जबकि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए किया.

शुरू में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी इसमें फंस गए, पर बाद में समझ में आया कि उनके साथ धोखा हुआ है. पहले उन मुसलमानों के सामने, जो मंडल कमीशन के तहत रिजर्वेशन में आ रहे थे, एक बड़ा मैदान था. अगर वे अपने लोगों को पढ़ा-लिखा लें तो वे जितना चाहें, 27 प्रतिशत में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं. अगर नहीं पढ़ेंगे-लिखेंगे तो एक प्रतिशत भी उनकी हिस्सेदारी नहीं बनती. लेकिन पढ़ेंगे-लिखेंगे तो उनके पास 27 फ़ीसदी रिजर्वेशन तक पाने का रास्ता खुला था. इस रिजर्वेशन के बाद उनके लिए साढ़े चार फ़ीसदी का ही मैदान रह गया. इस साढ़े चार फ़ीसदी में उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो गए ईसाई, सिख, जैन. इसमें ईसाइयों और जैनियों की सारक्षता दर लगभग 100 फ़ीसद है, सिखों का लगभग 70 फ़ीसद है और मुसलमानों का चार से पांच फ़ीसद है. मुसलमानों का कुल सक्सेस रेट चार साढ़े चार फ़ीसद है. प्रतियोगिता की सीमा रेखा में अगर हम देखें तो पाएंगे कि मुसलमानों के जिस तबक़े को रिजर्वेशन के साढ़े चार फ़ीसदी वाले मैदान में डाला गया है, उनके पास असली हिस्सा तो आधा प्रतिशत ही आएगा. उनके यहां लोग पढ़े-लिखे हैं ही नहीं, पढ़ने-लिखने की सुविधाएं भी नहीं हैं. पढ़ने-लिखने की प्रेरणा नहीं है, नौकरी में कहां से आएंगे. अन्य अल्पसंख्यक नौकरी के इन अवसरों को छीन ले जाएंगे. मुसलमानों को यह बात समझाने की किसी ने कोशिश नहीं की.

लेकिन एक अफ़सोस की बात है. केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल अधिकांश दल इस देश की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी यानी मुसलमानों के पक्ष के माने जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये सेकुलर हैं और मुसलमानों को उनका हक़ देने में ये बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. लेकिन हक़ीक़त में देखें तो ये लोग मुसलमानों के लिए वैसे ही ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, जैसे एनडीए के लोग. अगर हम एनडीए का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि एनडीए में जब जॉर्ज फर्नांडिस शामिल हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉर्ज फर्नांडिस एवं उनके साथियों की वजह से एनडीए की मुख्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्य मुद्दे छोड़ने पड़े थे. इनमें पहला था बाबरी मस्जिद की जगह राममंदिर बनाना, कश्मीर में धारा 370 को हटाना और कॉमन सिविल कोड को लागू करना.

उत्तर प्रदेश में दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है, जहां नीतीश कुमार और शरद यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ चुनाव प्रचार करेंगे. अब इसे अंतर्विरोध न कहें तो क्या कहें. जो एनडीए मुसलमानों के ख़िलाफ़ मानी जाती है, वह तो मुसलमानों या सेक्युलरिज्म के हित में काम कर जाती है, जबकि यूपीए जो मुसलमानों की समर्थक और सेकुलर मानी जाती है, वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर देती है. अब जब यह मांग उठी है कि अगर मुसलमानों को 9 फ़ीसद आरक्षण की घोषणा में दम है या ईमानदारी है तो क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी अध्यादेश निकाल कर, एक्जिक्युटिव ऑर्डर जारी कर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में तत्काल प्रभाव से मुसलमानों को 9 फ़ीसदी आरक्षण दे देती है.

अगर जॉर्ज नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले सरकार बनाने लायक़ सांसद होते या जयललिता जैसे सहयोगियों के पास इतने सांसद होते तो शायद उस समय देश में एक बुनियादी बदलाव आ जाता. पर जॉर्ज फर्नांडिस और आज की तारीख़ में उनके साथी शरद यादव और नीतीश कुमार मिलकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों से दूर रखने में कामयाब हुए हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उसका कट्टर समर्थक जी भरकर कोस रहा है. शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को आख़िरी समय तक भ्रम में रखा कि वह उसके साथ समझौता कर रही है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे. जनता दल यूनाइटेड ने कोई ख़ास चुनावी तैयारी नहीं की. आख़िरी वक़्त में आकर भाजपा ने कहा कि वह जदयू के साथ कोई समझौता नहीं करेगी.

उत्तर प्रदेश में दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है, जहां नीतीश कुमार और शरद यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ चुनाव प्रचार करेंगे. अब इसे अंतर्विरोध न कहें, तो क्या कहें. जो एनडीए मुसलमानों के ख़िलाफ़ मानी जाती है, वह तो मुसलमानों या सेक्युलरिज्म के हित में काम कर जाती है, जबकि यूपीए जो मुसलमानों की समर्थक और सेकुलर मानी जाती है, वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर देती है. अब जब यह मांग उठी है कि अगर मुसलमानों को 9 फ़ीसद आरक्षण की घोषणा में दम है या ईमानदारी है, तो क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी अध्यादेश निकाल कर, एक्जिक्युटिव ऑर्डर जारी कर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में तत्काल प्रभाव से मुसलमानों को 9 फ़ीसदी आरक्षण दे देती है. अगर 9 फ़ीसदी आरक्षण यहां मिल जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान यह मान लेगा कि कांग्रेस में ईमानदारी है और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 9 फ़ीसदी आरक्षण देकर उन्हें वैसे ही मुख्यधारा में लाना चाहती है, जैसे जवाहर लाल नेहरू के समय कांग्रेस ने दलितों को आरक्षण देने का समर्थन करके उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश की थी.

आज दलित हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर मुक़ाबला करने के लिए खड़े हैं. उनमें पढ़ने की ललक जागी है. वे समाज में अपना हिस्सा मांगने के लिए हिम्मत के साथ हर जगह खड़े दिखाई देते हैं और इसका उदाहरण मायावती, रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे नेताओं के रूप में देखा जा सकता है. कांग्रेस अगर ऐसा फ़ैसला करे तो इस देश के सारे सेकुलर लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे और मुसलमान तो अगले पचास सालों तक कांग्रेस को वोट देते रहेंगे. लेकिन लगता यही है कि ऐसा होगा नहीं. अगर ऐसा नहीं होता है, तो इस मुल्क का मुसलमान यह समझेगा कि कांग्रेस हमेशा चुनाव के वक़्त कुछ नए शगूफ़े छोड़ती है, कुछ नए वादे करती है और उसके बाद आराम से उन वादों को भूल जाती है. राजस्थान में ऐसा ही हुआ, हरियाणा में ऐसा ही हुआ और दिल्ली प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ. जो वादे मुसलमानों से किए गए, वे पूरे नहीं हुए. मैं जब मुसलमान कहता हूं, तो मैं किसी धर्म विशेष से जुड़े लोगों की बात नहीं करता. मैं जब मुसलमान कहता हूं, तो मेरे सामने वंचित लोगों का वह तबक़ा आ जाता है, जिसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं और मुसलमान भी हैं. क्योंकि जब भारत सरकार की बनाई सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन हालात का जायज़ा लेने बैठते हैं, तो कहते हैं कि इस देश का मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा कमज़ोर है, तो यह लगता है कि इस मुल्क को चलाने वाले लोगों की न्याय प्रियता में कहीं कुछ कमी है. यह तो हम सबको मानना ही चाहिए कि अगर इस देश के 18 फ़ीसदी लोग दबे-कुचले और वंचित श्रेणी में रहते हैं और उन्हें उनका हक़ नहीं मिलता है, तो इस देश में शांति क़ायम रहना मुश्किल है. इसलिए जो सत्ता में होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है. उत्तर प्रदेश चुनाव में जब सत्ता से जुड़े लोग कोई घोषणा करें तो उस पर अमल हो, यही नैतिकता का तक़ाज़ा है. पर नैतिकता आख़िर आज बची कहां है. यही सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव का बड़ा सवाल है. और देखना यह है कि वहां के लोग, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी शामिल हैं, किस तरह के सवालों को समर्थन देने या वोट देने का पैमाना बनाते हैं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

धर्म के नाम पर राजनीति के शिकार मुसलमान

अगर कहीं चुनाव हों और वहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी हो तो संविधान के तमाम प्रावधानों को धत्ता बताते हुए उनकी असल समस्याएं न उठाकर सुरक्षा और अन्य ऐसे ही मुद्दे उठाने को कोई बड़ी बात नहीं कहा जा सकता. इस तरह के अनुमान न लगाना हास्यास्पद है. दारुल उलूम ने कुछ समय पहले ही एक आधुनिक उदारवादी मुस्लिम विद्वान को पहले नियुक्त किया और फिर उन्हें हटा दिया. इस घटना को अभी अधिक दिन नहीं हुए थे कि उसने सलमान रुश्दी और सैटेनिक वर्सेस का मुद्दा छेड़ दिया. उसने कहा कि सलमान रुश्दी को वीज़ा न देकर भारत आने से रोक दिया जाए. तस्लीमा नसरीन को भी धमकी दी जाती है. वह बांग्लादेश की हैं और एक महिला भी हैं. यहां तक कि वामदल भी तस्लीमा नसरीन और उनकी मानवाधिकार की लड़ाई में उनके साथ नहीं है, बल्कि वे उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं, जो तस्लीमा का विरोध कर रहे हैं. वह मुस्लिम हो सकती हैं, लेकिन वह हमारे देश की तरह की मुसलमान नहीं हैं. यह समझने की बात है कि पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र होने के बावजूद हमें इस बात का प्रमाणपत्र मुल्लाओं से लेना पड़ता है कि किसे हम सही मुसलमान मानें और किसे ग़लत.

दारुल उलूम ने कुछ समय पहले ही एक आधुनिक उदारवादी मुस्लिम विद्वान को पहले नियुक्त किया और फिर उन्हें हटा दिया. इस घटना को अभी अधिक दिन नहीं हुए थे कि उसने सलमान रुश्दी और सैटेनिक वर्सेस का मुद्दा छेड़ दिया. उसने कहा कि सलमान रुश्दी को वीज़ा न देकर भारत आने से रोक दिया जाए. तस्लीमा नसरीन को भी धमकी दी जाती है. वह बांग्लादेश की हैं और एक महिला भी हैं.

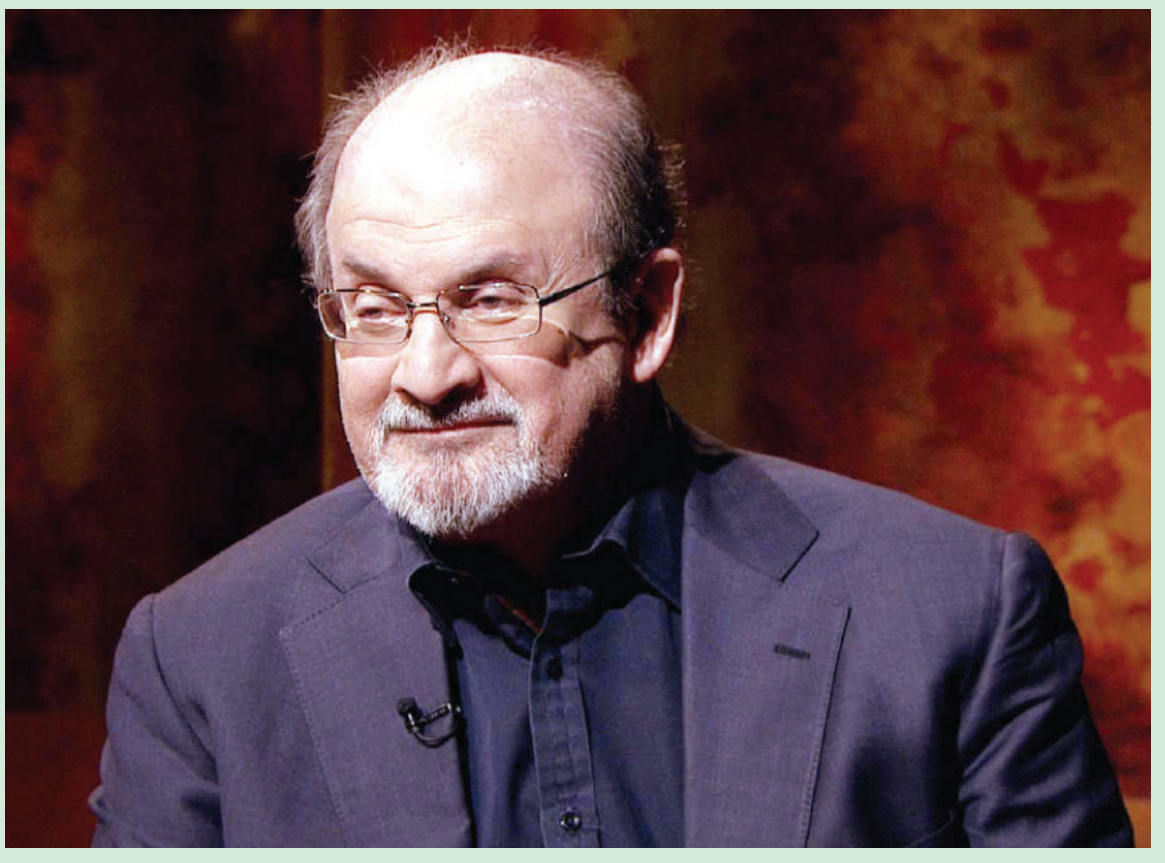

इन लोगों ने रुश्दी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया, लेकिन रुश्दी इनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान साबित हुए. उनका जन्म भारत में हुआ है और उनके पास पीआईओ कार्ड है. इसका मतलब है कि सलमान रुश्दी को वीजा की आवश्यकता ही नहीं है. क्या हमें भाजपा या आरएसएस से यह जानने की आवश्यकता है कि पीआईओ के तौर पर किन मुस्लिमों को अधिकार है और किन्हें नहीं. दारुल उलूम और आरएएस यह फ़ैसला नहीं ले सकते कि सलमान रुश्दी को पीआईओ कहा जाए या नहीं. ध्यान रहे कि केवल भारतीय पासपोर्ट होना ही भारत में रहने के लिए काफी नहीं है और मुसलमानों के लिए तो और भी नहीं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दल आपको सही समझते हैं या नहीं. एक व्यक्ति के लिए जो नियम हमारे यहां होते हैं, वही नियम दूसरे के लिए भी हों, यह ज़रूरी नहीं है. किसी को ग़लत मुसलमान होने का दंड भुगतना पड़ता है तो किसी को ग़लत भारतीय होने का. मकबूल फिदा हुसैन के अधिकारों की रक्षा धर्मनिरपेक्ष यूपीए सरकार भी नहीं कर सकी, क्योंकि बजरंग दल के कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ हंगामा खड़ा कर दिया था. यूपीए सरकार मकबूल फिदा हुसैन के मुद्दे पर पीछे हट गई और उन्हें देश के बाहर ही मरना पड़ा. अगर आप भारत के मुसलमान हैं तो आपको अपनी सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र सभी हिस्सों के कट्टरपंथी संगठनों से लेना होगा.

अभी जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, मुस्लिम वोट पाने की राजनीति चरम पर है. दारुल उलूम की तरफ़ से रुश्दी पर उठाया गया सवाल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने बाटला हाउस का मुद्दा उछाल दिया. इस पर हंगामा शुरू हो गया है. यह मुस्लिम वोट हासिल करने की एक नई राजनीति है. इस मुक़दमे पर बहस की गई और फ़ैसला भी हो गया. न्यायपालिका ने उस पीआईएल को भी ख़ारिज कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई फिर से की जाए, जिसमें पुलिस ने षड्यंत्र के तहत अपने ही एक अधिकारी की हत्या कर दी थी, ताकि मुस्लिमों को बदनाम किया जा सके. दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को फिर से उठा दिया. इसका कारण मुसलमानों का वोट लेना ही कहा जा सकता है. आख़िरकार मुस्लिमों के जीवन स्तर, शैक्षणिक स्थिति, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, अधिक वेतन वाले निजी क्षेत्रों में उन्हें प्रतिनिधित्व देने जैसे मुद्दों की ओर मुसलमानों के इन हमदर्दों का ध्यान क्यों नहीं जाता. मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की जा रही है, वह भी इतने सालों के बाद! आरक्षण की बात तब की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है. वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और इसी कारण कांग्रेस को वहां मुसलमानों के वोटों की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई. बेशक चुनाव आयोग ने मुस्लिम आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को चुनाव परिणाम आने तक स्थगित कर दिया है, लेकिन आख़िरकार मुद्दा तो उछाल ही दिया गया. आरक्षण पर फ़ैसला तो अब चुनाव के बाद आएगा, लेकिन इसका लाभ चुनाव के समय लेने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस सहित अन्य धर्मनिरपेक्ष संगठनों का मुस्लिम प्रेम महज़ दिखावा है. वे केवल इसे हथियार बनाना चाहते हैं, ताकि भाजपा को पराजित किया जा सके. मुसलमानों को इस पर ग़ौर करना चाहिए और आम भारतीय नागरिकों की तरह अपना अस्तित्व बनाना चाहिए, ताकि उनका इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर न किया जा सके. चुनाव के समय उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति सुधारने की बात की जाती है. यहां तक की सच्चर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा भी चुनाव के समय ही की जाती है. इस स्थिति से मुसलमानों को निकलना चाहिए, ताकि वे अपने विकास के लिए सोचने पर राजनीतिक दलों को मजबूर कर सकें. उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का कर कोई उनका वोट न ले, बल्कि उनका वोट उनके विकास की बात करने वालों को मिल सके.

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञान पत्रिका पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के अनुसार, विशेषज्ञ इन तस्वीरों पर लिखित संदेश के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल कर सकते हैं.

जब पीआईओ सूचना न दे

RIGHT TO INFORMATION

एक आरटीआई आवेदक के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सूचना का न मिलना, ग़लत सूचना मिलना या आधी-अधूरी सूचना मिलना. ज़ाहिर है, इसके पीछे लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ की लापरवाही या जानबूझ कर सूचना न देने की मंशा होती है. कई बार आवेदकों को परेशान करने के लिए भी ऐसा किया जाता है. आम तौर पर अगर आपने सूचना पाने के लिए किसी सरकारी विभाग में आवेदन किया है तो उसका जवाब 30 दिनों के भीतर मिल जाना चाहिए, लेकिन जब 30 दिन बीत जाने के बाद भी आपको सूचना नहीं मिली या मिली भी तो ग़लत या आधी-अधूरी या भ्रामक अथवा फिर सूचना का अधिकार क़ानून की धारा 8 के प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर आपको सूचना देने से मना कर दिया गया हो, तब क्या किया जाना चाहिए. कई बार आपसे यह भी कहा जा सकता है कि अमुक सूचना दिए जाने से किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है या फलां सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है इत्यादि. अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ज़ाहिर है, चुपचाप तो बैठा नहीं जा सकता. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप सूचना अधिकार क़ानून के तहत ऐसे मामलों में प्रथम अपील करें. जब आप आवेदन जमा करते हैं तो उसके 30 दिनों बाद, लेकिन 60 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जो सूचना क़ानून के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, के यहां अपील करें. यदि आप द्वारा अपील करने के बाद भी कोई सूचना या संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है या आपकी प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं. दूसरी अपील के लिए आपको राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में जाना होगा. फ़िलहाल इस अंक में हम सिर्फ़ प्रथम अपील के बारे में ही बात कर रहे हैं. हम प्रथम अपील का एक प्रारूप भी प्रकाशित कर रहे हैं. अगले अंक में हम आपकी सुविधा के लिए द्वितीय अपील का प्रारूप भी प्रकाशित करेंगे. प्रथम अपील के लिए आम तौर पर कोई शुल्क निर्धारित नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रथम अपील के लिए भी शुल्क निर्धारित कर रखा है. प्रथम अपील के लिए कोई निश्चित प्रारूप (फॉर्म) नहीं होता है. आप चाहें तो एक सादे काग़ज़ पर भी लिखकर प्रथम अपील तैयार कर सकते हैं. हालांकि इस मामले में भी कुछ राज्य सरकारों ने प्रथम अपील के लिए एक ख़ास प्रारूप तैयार कर रखा है. प्रथम अपील आप डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालय जाकर जमा करा सकते हैं. प्रथम अपील के साथ आरटीआई आवेदन, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (यदि उपलब्ध कराई गई हो तो) एवं आरटीआई आवेदन के साथ दिए गए शुल्क की रसीद आदि की फोटोकॉपी लगाना न भूलें. इस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि लोक सूचना अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है तो आप प्रथम अपील में सारी सूचनाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए भी कह सकते हैं. इस क़ानून में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है. भले ही सूचना हज़ार पृष्ठों की क्यों न हो. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अंक में प्रकाशित प्रथम अपील के प्रारूप का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

प्रथम अपील का प्रारूप

सेवा में,
प्रथम अपील अधिकारी,
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,
1. मैंने सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है:-
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है.
-मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/गलत है/मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है.

आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें और लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें. सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें.

धन्यवाद

नाम:
पता:
दिनांक:

संलग्नक:-
1. आवेदन की प्रति
2. आवेदन शुल्क की रसीद की प्रति
3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब की प्रति

ज़रा हट के

कैमरा बोले तो डॉक्टर

हाल में हुए एक अध्ययन में यह ख़ुलासा हुआ है कि कैमरा फोन चिकित्सा निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. नीदरलैंड के रॉयल ट्रापिकल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता कोसजे तुईज्न ने बताया कि दो मेगा पिक्सल कैमरा स्पष्ट माइक्रोस्कोपी छवियां लेने में सक्षम है, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण के लिए वेबसाइट पर भेजा जा सकता है. विज्ञान पत्रिका पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के अनुसार, विशेषज्ञ इन तस्वीरों पर लिखित संदेश के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल कर सकते हैं. चिकित्सक इस नेटवर्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पर दूरस्थ और कम आबादी वाले इलाक़ों में कम समय में ज़्यादा मरीजों की मदद करने के लिए कर सकते हैं. तुईज्न ने कहा कि इस नई तकनीक से अल्प अनुभवी स्वास्थ्यकर्मियों और प्रयोगशालाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को रोगों के निदान में मदद मिलेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फेसबुक की करतूत

विश्व में तलाक के एक तिहाई मामलों के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ज़िम्मेदार है. यह दावा एक विधिक परामर्शदाता कंपनी ने किया है. बताया गया कि तलाक के मामलों में फेसबुक का प्रयोग बतौर सबूत किया जा रहा है. कंपनी ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान फेसबुक शब्द वाली तलाक याचिकाओं में 50 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है. तलाक की 5000 याचिकाओं में कम से कम 33 फ़ीसदी में फेसबुक के नाम का उल्लेख किया गया. डाइवोर्स ऑनलाइन के प्रबंध निदेशक मार्क कीनन ने कहा कि लोग अपने पूर्व मित्रों के साथ सरलता से संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन अंत समस्याप्रद होता है. यदि कोई अपने विपरीत लिंग के साथ ठिठोली करना या संबंध बनाना चाहता है तो यह आरामदायक स्थान है. कीनन ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किलों को तलाक की कार्यवाही के दौरान फेसबुक से दूर रहने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि फेसबुक पर लोग जो भी सूचनाएं रखते हैं, उनके प्रति सचेत रहना चाहिए.

भारत सबसे आगे है, लेकिन...

अनचाहे ई-मेल या स्पैम भेजने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है. इंटरनेट सुरक्षा को लेकर कमज़ोर क़ानूनों के चलते यहां थोक में ई-मेल भेजे जाते हैं. ई-मेल का कुल 80 प्रतिशत हिस्सा स्पैम होता है. मॉस्को स्थित इंटरनेट सुरक्षा कंपनी कास्पेर्सकी लैब का कहना है कि दक्षिण एशिया से जितना स्पैम आता है, उतना पूरी दुनिया में और कहीं से नहीं. कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल जुलाई से सितंबर के बीच भेजे गए ई-मेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि 79.8 प्रतिशत ई-मेल जंक या स्पैम थे. इनमें से 14.8 प्रतिशत भारत, 10.6 प्रतिशत इंडोनेशिया और 9.7 प्रतिशत ब्राजील से भेजे गए. कंपनी की स्पैम विशेषज्ञ दरया गुडकोवा का कहना है, आंकड़े दिखाते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों और लैटिन अमेरिका से जंक बढ़ रहा है. दरया का कहना है कि भारत में इंटरनेट सुरक्षा को लेकर सख्त क़ानूनों की कमी है. इसी के चलते वहां से इतना स्पैम आता है. इसके अलावा लोगों में इंटरनेट सुरक्षा को लेकर बहुत कम जानकारी है. भारत में इंटरनेट सुरक्षा केजानकार विजय मुखी का कहना है कि जबसे अन्य देशों में सख्त क़ानून बने हैं, तबसे स्पैम भेजने वाले लोगों ने भारत को अपना अड्डा बना लिया है. हमारे यहां 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया, लेकिन उसके अंतर्गत कभी किसी पर अपराध साबित नहीं किया गया और स्पैम के बारे में उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है.

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अपनी आजीविका या व्यवसाय में छवि सुधारने की चिंता रहेगी. आपके मित्रों एवं शुभचिंतकों की एक लंबी सूची है, यदि आप चाहें तो सप्ताह के अंत में उन सबके साथ अपना मेलजोल बढ़ाने के लिए कोई पार्टी या डिनर का आयोजन कर सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
कोई ऐसी सलाह पर अमल करना होगा, जिससे पारिवारिक जीवन या घर के सदस्यों की नाराज़गी दूर हो जाए. हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो, जिसकी शिक्षा, रोज़गार या वैवाहिक सबध बनने में परेशानी आ रही हो अथवा आपका समय समस्याएं दूर करने में न लग पा रहा हो तो आप उपेक्षा और नफरत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अपने भी अपनों से ही ख़ुश या नाराज़ होते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आप किसी पिछली घटना को बार-बार याद करके उत्साहहीन हो सकते हैं. यदि आपको आगे जाना है तो उन हदों को तोड़कर काम करने का साहस करना होगा, जिनके कारण पहले आपको हार का मुंह देखना पड़ा. सप्ताह के मध्य में, चाहे घर हो या कार्यस्थल, सफलता हासिल करने के लिए औरों के साथ स्वयं भी जुटना होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
विशेष परिश्रम और पुरुषार्थ के बावजूद मायूसियां बनी रहेंगी. यदि आप आजीविका या नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं या पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपको सप्ताह मध्य तक अनुशासन एवं कड़ी मेहनत करने की बात स्वीकार करनी होगी. कई बार आप ख़ुद को ढीला छोड़ देते हैं या फिर किसी काम के अंतिम छोर पर पहुंच कर उम्मीद गंवा देते हैं. यह आपके लिए ठीक नहीं है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
उन्नतिगामी प्रयासों पर आरंभिक कार्यवाही तत्काल करेंगे. इस वक्त आप अपनी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, शेयर, फंड या निवेश के चक्कर में अधिक रहेंगे. यदि आप जोखिम भरे कामों से धन कमाना चाहते हैं तो यह उम्मीद आपको आगे चलकर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आपकी सोच और विचार शक्ति कुछ अधिक भौतिकवादी हो रही है. घर के अंदर जो सामान बेकार और फालतू पड़ा है, उसे ठीकठाक करने के बजाय आप नया सामान लाने की तरकीब लड़ा रहे हैं. बेहतर यह होगा कि अपनी जेब का ख्याल रखें, घर में उपलब्ध स्थान पर नज़र दौड़ाएं.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नियमित आमदनी का भी ख्याल रखना होगा. अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धन लाभ के साधन पैदा करने होंगे. आपकी जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं, जब आपके हाथ में उनके अनुसार रकम भी आती रहे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
खुद को सफल बनाने के लिए मजबूत इरादे और मेहनत के साथ कोई ऐसी राह बनानी होगी, जो असलियत और वास्तविक जिंदगी से नजदीक हो. आपके जीवन में कुछ विवादास्पद मामले ऐसे हैं, जिन्हें सप्ताह मध्य तक सुलझा लेना ज़रूरी होगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आपने जो काम का बोझ अपने सिर पर लिया था, वह कुछ कम हो सकता है. दूसरों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण दिन-रात जुटकर आपने अपनी कमर भी सीधी नहीं की. सप्ताह मध्य में आप इन सबसे फुर्सत पाएंगे, वहीं आराम करने के लिए भी एक सिग्नल मिल जाएगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
आप अपने रुके हुए काम पूरे करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे, जो अप्रत्याशित होंगे. दूसरों की तारीफ़ करके या अपने सहकर्मियों को खाने-पीने की दावत देकर आप जल्दी-जल्दी अपने कार्यभार से मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आपकी बौद्धिक और शारीरिक ऊर्जा शिखर पर है. आपने सफलता प्राप्त करने के लिए सही सीढ़ी या मार्ग का चुनाव भी कर रखा है. सप्ताह मध्य में यदि आप अपनी इच्छाशक्ति, प्रभाव, प्रतिष्ठा और तौर-तरीकों का सही इस्तेमाल करेंगे तो धन वृद्धि के अलावा आप यश के भी भागीदार हो सकते हैं.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
बहुत कोशिशों के बावजूद आप अपने कामकाज को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं. दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपनी छवि सुधारने और कामकाज बेहतर करने का हुनर सीखना चाहिए. विजय और मान-प्रतिष्ठा हमेशा कायम रखना आसान काम नहीं है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

जून 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ इनलाई भारत आए तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी अक्टूबर 1954 में चीन की यात्रा की.

भारत–चीन

संबंध सुधार की कोशिश सिर्फ़ काग़ज़ों तक

राजीव कुमार

भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए प्रयास करने की बात काग़ज़ों में बहुत पहले से ही होती आ रही है. इसी काग़ज़ी कार्रवाई का एक और दौर शुरू हुआ, दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर वार्ता का. यह 15वें दौर की वार्ता है, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने भाग लिया तो चीन का प्रतिनिधित्व वहां के स्टेट काउंसिलर दाई बिंगुआ ने किया. इस वार्ता में भी वही बड़े–बड़े वादे किए गए, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि वे सीमा मसले पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में अब तक हुई प्रगति के बारे में अपनी–अपनी सरकारों के लिए एक संयुक्त सहमत रिकॉर्ड तैयार करेंगे. सीमा विवाद संबंधी मामलों के अलावा विशेष प्रतिनिधियों ने अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी विचार–विमर्श किया. भारत सरकार के अनुसार, यह विमर्श व्यापक, उपयोगी और दूरदर्शी था. भारत का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच हुई इस वार्ता में अनेक मामलों पर विचारों में समानता थी. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति का सकारात्मक मूल्यांकन किया तथा दोनों देशों के मध्य नियमित उच्चस्तरीय आदान–प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में मज़बूत सहयोग के महत्व का उल्लेख भी किया. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि वैश्विक मामलों पर अधिकाधिक समन्वय की गुंजाइश है. विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का अगला दौर चीन में आयोजित किए जाने का फ़ैसला लिया गया. दोनों देशों के बीच एक क़रार भी हुआ, जिसमें सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य तंत्र की स्थापना की बात की गई है. इस कार्यकारी तंत्र के प्रमुख भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे. वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना तथा सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए समुचित प्रयास करना इसका काम होगा. यह कार्यकारी तंत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों के सैन्य कार्मिकों और संस्थापनाओं के बीच आदान–प्रदान एवं सहयोग को संचालित एवं संवर्धित करने के तौर तरीक़ों का अध्ययन करेगा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा. पारस्परिक सहमति के बाद अन्य कार्य भी करेगा, लेकिन न तो सीमा संबंधी मामलों के समाधान पर चर्चा करेगा और न ही विशेष प्रतिनिधि तंत्र को प्रभावित करेगा. इसके अलावा यह कार्यकारी तंत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा तथा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण माहौल बनाए रखने की दिशा में सक्रिय प्रयास करेगा. कार्यकारी तंत्र साल में एक या दो बार भारत या चीन में परामर्श बैठकें करेगा तथा अगर ज़रूरत पड़ी तो आपातकालीन बैठकें भी आपसी सहमति के आधार पर करेगा. ऐसी ही बड़ी–बड़ी बातें और शब्दों का मायाजाल इस वार्ता के दौरान बुना गया तथा यह उम्मीद जताई गई कि दोनों देशों के बीच के सीमा विवाद को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश की जाएगी. लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि इस बार भी यह क़रार काग़ज़ों पर ही रह जाएगा न कि इसे धरातल पर लाया जाएगा.

इससे पहले भी भारत और चीन के बीच कई क़रार हो चुके हैं, लेकिन उन क़रारों का नतीजा क्या निकला, वही ढाक के तीन पात. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई थी और भारत पहला ग़ैर कम्युनिस्ट राष्ट्र था, जिसने इसे मान्यता दी थी. जून 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ इनलाई भारत आए तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी अक्टूबर 1954 में चीन की यात्रा की. दोनों देशों के बीच इसी वर्ष पंचशील समझौता हुआ. लेकिन इसका परिणाम क्या निकला. चीन ने 1962 में यानी पंचशील समझौते के महज़ आठ साल बाद भारत को नीचा दिखाने के लिए हमला कर दिया. हिंदी चीनी भाई–भाई कहते हुए चीनी सैनिक भारत की ओर बढ़ रहे थे और हमारी सेना आदेश का इंतज़ार कर रही थी. दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश तो फिर से शुरू हो गई तथा भारत धीरे–धीरे चीन के आक्रमण को भूलने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन चीन है कि उसे भूलने ही नहीं देता है. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अलगाववादी संगठनों को किसी न किसी स्तर पर चीन का सहयोग प्राप्त होता है. यह बात अलग है कि भारत सरकार चीन पर कम ही आरोप लगाती है. पाकिस्तान को चीन का सहयोग जारी रहता है, जबकि पाकिस्तान खुले तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है. भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानता है. हाल में भारत की ओर से चीन जाने वाले तीस सदस्यीय सैन्य प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ग्रुप कैप्टन पांगिंग को वीजा नहीं दिया. यह अधिकारी अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इस प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानता है, तो फिर अपने ही देश में आने के लिए किसी को वीजा कैसे दे सकता है. ग़ौरतलब हो कि दोनों देशों के बीच हुई चौथे दौर की रक्षा वार्ता में यह तय किया गया था कि दोनों देश सैन्य अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एक–दूसरे के यहां भेजेंगे, जिससे सैन्य संबंधी विवादों के निपटारे में सुविधा होगी. लेकिन चीन के इस रवैये का क्या मतलब निकाला जा सकता है. हालांकि भारत सरकार का कहना है कि इससे प्रतिनिधिमंडल के भेजे जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या यह संभव है. भारत सरकार इस अधिकारी को किसी दूसरे राज्य का दिखाकर वीजा लेने की बात कर रही है. यह हमारी सरकार के लिए तो शर्म की बात है. पता नहीं भारत चीन के मामलों में इतना नरम रुख़ क्यों अपनाता है. यही नहीं चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. विदेश मंत्रालय ने भी यह माना है कि लद्दाख़ में चीनी सैनिक की घुसपैठ जारी है. लद्दाख़ के लोगों का कहना है कि चीनी सैनिक उनके क्षेत्रों में आकर उत्पात मचाते हैं. भारतीय सीमा के भीतर सड़क निर्माण करने वाले मज़दूरों ने तो यहां तक कहा है कि चीनी सैनिक उनका सामान तक उठाकर ले जाते हैं. लगभग ऐसी ही स्थिति पूर्वोत्तर भारत में भी है. वहां भी चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तथा लोगों को परेशान करते हैं. यही नहीं भारत को चारों ओर से घेरने की नीति पर भी चीन काम कर रहा है. हाल में वियतनाम के साथ जब भारत ने तेल खोजने का समझौता किया तो चीन ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह चीन के अधिकारों का अतिक्रमण है. कुछ दिन पहले ही चीन में भारतीय राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया. ऐसी स्थिति में हमें इस वार्ता को किस रूप में लेना चाहिए, कितनी उम्मीद की जानी चाहिए. दोनों देशों के बीच अगर किसी क्षेत्र में संबंध सुधरे हैं तो वह है व्यापार, क्योंकि चीन को भारत के साथ आर्थिक संबंध बहाल रखने में लाभ है. इसी कारण वह हमेशा कहता है कि आर्थिक संबंधों पर सीमा विवाद का कोई असर नहीं होगा. अब इस समझौते का हश्र क्या होता है, यह तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि काग़ज़ों पर हो रहे इन समझौते से संबंध सुधरने वाले नहीं हैं. इसके लिए दोनों देशों को अपना छद्म स्वार्थ छोड़ना होगा तथा लंबे समय में होने वाले लाभों पर ध्यान देना होगा. जब तक भारत और चीन के बीच विश्वास बहाली नहीं होगी और चीन यह विश्वास नहीं दिलाएगा कि वह वास्तव में भारत के साथ मधुर संबंध बनाना चाहता है तब तक ऐसे समझौते महज़ दिखावा ही कहे जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

यह ग़लत परंपरा की शुरुआत है

ईरान अभी कुछ देशों के निशाने पर है. अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश ईरान पर परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित करने का आरोप लगा रहे हैं. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व के लिए ख़तरा बताकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के कई देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा भी कर दी है. हालांकि रूस ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वह परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित कर रहा है. चीन, जापान ने भी ईरान से तेल ख़रीदते रहने का फ़ैसला किया है. भारत का भी कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा किसी अन्य प्रतिबंध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और ईरान से तेल न ख़रीदने का प्रतिबंध अमेरिका तथा यूरोसंघ का है, इसलिए भारत ईरान से तेल ख़रीदता रहेगा. यहां तक बात ठीक है कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर ईरान को कमज़ोर करके उसके परमाणु कार्यक्रम को कमज़ोर किया जाए. अगर सही प्रमाण हो तो उस पर और कड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है. लेकिन हाल फ़िलहाल में एक बुरी ख़बर आई, जिसे ग़लत परंपरा की शुरुआत कही जा सकती है. ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्या कर दी गई. ईरान में परमाणु वैज्ञानिक की हुई यह पहली हत्या नहीं है. पिछले दो वर्षों में ईरान के तीन अन्य परमाणु वैज्ञानिकों मसूद अली मोहम्मद, माजिद शहरीयारी तथा रेजेनेयाद की हत्या हो चुकी है तथा एक वैज्ञानिक अब्बासी द्वानी हमले के शिकार होने के बाद बच गए. ईरान से साफ़ तौर पर आरोप लगाया है कि उसके वैज्ञानिकों की हत्या में अमेरिका तथा इजरायल का हाथ है. हालांकि दोनों देशों ने उसके इस आरोप का खंडन किया है. कुछ यूरोपीय देशों का तो कहना है कि इन वैज्ञानिकों की हत्या में ईरान का ही हाथ है, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने ईरान में सही लोकतंत्र स्थापित करने तथा वर्तमान सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी. वैसे ईरान की बात में ज़्यादा दम है. उसके परमाणु कार्यक्रम से इजरायल, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश ज़्यादा ही नाराज़ दिखते हैं. इन देशों को विश्व की चिंता सबसे अधिक है. हालांकि इसके पीछे का राज़ कुछ और ही है. अमेरिका की नज़र ईरान पर बहुत दिनों से अटकी हुई है. उसे तो मौक़ा मिलना चाहिए. अब तो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांगने वाले प्रत्याशियों ने भी ईरान के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया है. एक प्रत्याशी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव जीतने के बाद वह ईरान पर हमला करेगा. ऐसी स्थिति में ईरान के किसी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या होती है तो संदेह इन देशों पर तो होगा ही. इजरायल तो यह चाहता है कि इसी बहाने ईरान उसके ऊपर हमला करे, जिससे उसे ईरान को तबाह करने का मौक़ा मिल जाए. लेकिन ईरान भी इसके झांसे में आने वाला नहीं है. उसने भी कहा है कि वह उन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा, जिनका इस्तेमाल उसके ख़िलाफ किया जा रहा है. अगर ईरान भी इन देशों के वैज्ञानिकों की हत्या का षड्यंत्र करता है, तो इससे एक ग़लत परंपरा की शुरुआत होगी. हालांकि इसके लिए ईरान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. अगर इस तरह की हत्याओं का दौर शुरू हो गया तो फिर विज्ञान की प्रगति की रफ्तार पर तो ब्रेक हीं लग जाएगा. इस तरह की कार्रवाइयों की वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना होनी चाहिए. ईरान ने तो इस हत्या पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं विशेषकर मानवाधिकार संस्थाओं के मौन की आलोचना की है. ईरान की मांग जायज़ भी है. अगर मानवाधिकार संस्थाएं इतना भी नहीं कर पाएंगी तो उन्हें भी पिछलग्गू ही कहा जाएगा. ईरान के जख्मों को कुरेदने की बजाय सहलाने की ज़रूरत है. ऐसा न हो कि प्रतिक्रिया के चक्कर में विश्व के वैज्ञानिकों को राजनीति का शिकार होना पड़ जाए. उसे परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ग़लत परंपरा क़ायम नहीं की जानी चाहिए, जिससे विश्व ही विनाश के कगार पर पहुंच जाए.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

छोटी उम्र में बड़ों जैसे कारनामे करने वाले इन होनहारों को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले एक समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सम्मानित किया.

श्रीमती तर्खड और साईं बाबा

एक बार श्रीमती तर्खड ने तीन वस्तुएं यानी भरित (भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही), काचर्या (बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए) और पेड़ा (मिठाई) बाबा के लिए भेजीं. बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया, अब इसे देखेंगे. बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे. एक बार वह शिरडी जा रहे थे. श्रीमती तर्खड ने श्रीमती पुरंदरे को दो बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वह एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें. शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गईं. बाबा उसी समय भोजन के लिए बैठे ही थे. उन्हें भुर्ता बहुत स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा-थोड़ा सभी को वितरित किया. इसके पश्चात राधाकृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचर्या मांग रहे हैं. वह असमंजस में पड़ गईं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बैगन की तो अभी ऋतु नहीं है. अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो. जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थीं और फिर उन्हें ही काचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया. अब हर आदमी को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ.

दिसंबर,1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे. प्रस्थान करने से पूर्व वह श्रीमती तर्खड से मिलने आए. श्रीमती तर्खड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थीं. उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था. फिर भी अति प्रेम के कारण उन्होंने वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया. उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे. शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए. बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब गोविंद पुन: संध्या समय बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो फिर बाबा शांत न रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं. बाबा ने पुन: प्रश्न किया और गोविंद ने फिर वही उत्तर दोहरा दिया. अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें मां (श्रीमती तर्खड) ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब गोविंद को स्मृति हो आई और वह बहुत लज्जित हुए और बाबा से क्षमायाचना करने लगे. वह दौड़कर गए और फिर पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया. बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया. इस प्रकार श्रीमती तर्खड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूं, यह भगवद्वचन भी सत्य साबित हुआ.

एक बार श्रीमती तर्खड शिरडी आईं. दोपहर का भोजन प्राय: तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थीं कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा. श्रीमती तर्खड तुरंत उठीं और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया. कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया. संध्या के समय जब वह मस्जिद में जाकर बैठीं तो बाबा ने उनसे कहा, मां, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली. सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा. इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा. सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो. पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो. इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो. बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूं, मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूं और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूं. बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं. भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था. इसी प्रकार अन्य प्राणी (बिल्लियां, सुअर, मक्खियां एवं गाय आदि) भी मेरे ही स्वरूप हैं. मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं. जो इन सब प्राणियों में मेरे दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है. इसलिए भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो. यह अमृत समान उपदेश ग्रहण कर वह द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा.

यूरोपियन महाशय

एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पाकर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए. उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया. वह तो बाबा के समक्ष नत मस्तक होकर उनके करकमलों का चुंबन करना चाहते थे. इसी कारण उन्होंने तीन बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया. उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली. इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के लिए वह वहां आए. बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी. अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वह सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए. कुछ दूर तक तो घोड़े ठीकठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक साइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गये और तेज गति से दौड़ने लगे. फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ-साथ घिसटते चले गए. उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो लोग बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं, उन्हें किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है और जो आज्ञा का पालन करते हैं, वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं.

शिक्षा

समस्त प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है. उपनिषदों एवं गीता का यही उपदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम् यानी सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो.

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार-2011

जज़्बे की कोई उम्र नहीं होती

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

अगर दिल में बहादुरी का जज़्बा हो तो उम्र की ज़ंजीरें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार-2011 के लिए चयनित नन्हें जांबाज़ों के कारनामे कुछ यही बयां करते हैं. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इस बार 24 बच्चों को दिया गया. इनमें कुछ बच्चों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया. वीरता पुरस्कार पाने वाले ये सभी वे बच्चे हैं, जिन्होंने विभिन्न घटनाओं में अपनी जान की परवाह किए बिना न सिर्फ़ दूसरों की जान बचाई, बल्कि सभी को संदेश दिया है कि जज़्बे की कोई उम्र नहीं होती है. किसी ने अपने साथियों को जलती आग की लपटों से बाहर निकाला तो किसी ने गहरे पानी में ख़ुद डूबकर दूसरों की जान बचाई. किसी ने चोरों का सामना किया और अपनी गर्दन कटने के बावजूद अंत तक डटे रहे तो कुछ ने भूस्खलन में भी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा और अपनी जान अपने दोस्तों पर न्योछावार कर दी. छोटी उम्र में बड़ों जैसे कारनामे करने वाले इन होनहारों को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले एक समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सम्मानित किया. इन सभी बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भी भाग लिया. इस बार के वीरता पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में 16 लड़के और आठ लड़कियां हैं. इनमें पांच बच्चों ने अपनी जान गंवाकर दूसरों की जान बचाई है. ग़ौरतलब है कि अब तक 824 बच्चों को यह सम्मान मिल चुका है, जिसमें से 584 लड़के और 240 लड़कियां शामिल हैं. आपको बता दें कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद के तत्वावधान में 1975 से प्रदान किए जा रहे हैं.

इस वर्ष 16 लड़के और आठ लड़कियों को राष्ट्रीय वीरता सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें से पांच बच्चों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया. इस साल केरल व छत्तीसगढ़ से तीन-तीन, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मणिपुर से दो-दो बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है. उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मिज़ोरम व उड़ीसा से एक-एक बच्चे को चुना गया है. प्रतिष्ठित गीता चोपड़ा पुरस्कार गुजरात की 13 वर्षीया मित्तल महेंद्रभाई पताडिया को दिया गया. उसने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हथियारबंद अपराधियों का सामना किया था और डकैती के प्रयास को विफल कर दिया था. चोरों ने उसकी गर्दन तक काट डाली थी. इसके बावजूद उसने चोरों को पकड़े रखा. पड़ोसियों ने मित्तल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चार घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान उसके गले पर 351 टांके लगे, इसके बाद उसे बचाया जा सका. चार घंटे की सर्जरी में मित्तल का घाव बंद किया जा सका. इस वर्ष का भारत पुरस्कार उत्तराखंड के कपिल नेगी 15 वर्ष को मरणोपरांत प्रदान दिया गया. 8 सितंबर 2010 को कपिल अपने साथियों के साथ स्कूल जा रहा था. नज़दीक में ही एक नाला था. अधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन होने लगा. नतीजतन पुल का रास्ता अवरुद्ध हो गया. कपिल अपने साथियों को पीठ के सहारे पुल पार कराने लगा. इस काम में उसके अन्य साथी भी मदद कर रहे थे. तभी पास की पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे. यह देख सभी साथी भाग लिए लेकिन कपिल अपने साथियों की मदद करता रहा. तभी अचानक भारी चट्टान उस पर आ गिरी. कपिल की मौक़े पर ही मौत हो गई. कपिल ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देकर असाधारण साहस का उदाहरण पेश किया. वहीं संजय चोपड़ा पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के 12 वर्षीय ओम प्रकाश यादव को चयनित किया गया है. मास्टर ओम प्रकाश ने जलती स्कूल वैन से अपने स्कूल के 8 दोस्तों को निकालकर उसकी जान बचाई थी. दिल्ली के साढ़े 12 वर्षीय उमा शंकर, अरुणाचल प्रदेश के साढ़े 14 वर्षीय स्व. आदित्य गोयल तथा छत्तीसगढ़ की रहने वाली 14 वर्षीय अंजली सिंह गौतम को बापू गैधानी पुरस्कार प्रदान किया गया.

इसके अलावा वर्ष 2011 के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान के सात वर्षीय डूंगर सिंह, उत्तर प्रदेश की सवा 12 वर्षीय लवली वर्मा (मरणोपरांत), केरल के पौने 14 वर्षीय अंशिफ़ सीके, छत्तीसगढ़ की रहने वाली सवा 10 वर्षीय शीतल साध्वी आहूजा, मिजोरम के रहने वाले 16 वर्षीय सी लालदुआमा (मरणोपरांत) को प्रदान किया गया. उत्तर प्रदेश की लवली 23 जून, 2011 को अपने नाना के यहां थी. इस दिन उसकी सहेलियां पास के ही तीन से चार मीटर गहरे तालाब में स्नान कर रही थीं. तभी अचानक लवली को दिखाई दिया कि उसकी सहेलियां पानी में डूब रही हैं. लवली ने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी. उसने किसी तरह अपनी सहेलियों को तो किनारे तक पहुंचा दिया, लेकिन ख़ुद पानी से बाहर नहीं आ पाई. वह गहरे पानी में डूब गई, लेकिन इस छोटी बच्ची ने अपनी जान देकर भी अपनी सहेलियों की जान बचाई. इसी तरह मिज़ोरम के रहने वाले सी लालदुआमा ने भी एक गड्ढे में फंसे अपने साथियों की जान बचाई. सी लालदुआमा उस वक़्त गहरे गड्ढे में अपने साथियों को बचाने के लिए कूद पड़ा, जब उसको सही से तैरना भी नहीं आता था. बहादुरी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है.

इसके अलावा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की फ़ेहरिस्त में छत्तीसगढ़ के साढ़े 14 वर्षीय रंजन प्रधान, कर्नाटक की रहने वाली पौने 14 वर्षीय सिंधुश्री बीए, आंध्र प्रदेश के 14 वर्षीय एस शिवा प्रसाद, केरल के सवा तेरह वर्षीय मोहम्मद निशाद, उड़ीसा के सवा 11 वर्षीय प्रसन्नता शांडिल्य, मणिपुर के सवा 13 वर्षीय राकेश सिंह, केरल के पौने 17 वर्षीय सहशाद के, गुजरात की 13 वर्षीय दिव्याबेन चौहान, मणिपुर की 14 वर्षीय जॉनसन तौरांगबम और कर्नाटक के रहने वाले साढ़े 16 वर्षीय संदेश पी हेगड़े शामिल हैं. सभी ने किसी न किसी तरह से अपनी बहादुरी का परिचय देकर मानवता का नाम रोशन किया.

बता दें कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को पदक, प्रमाण पत्र और नक़द राशि प्रदान की जाती है. भारत पुरस्कार के तहत 50 हज़ार रुपये, गीता चोपड़ा व संजय चोपड़ा पुरस्कार के तहत 40 हज़ार रुपये और बापू गैधानी पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 24 हज़ार रुपये तथा अन्य को 20-20 हज़ार रुपये प्रदान किए जाते हैं. इसके अलावा परिषद की ओर से बच्चों को हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले बच्चों को उनकी पेशेवर पढ़ाई पूरी करने के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी. ख़ैर, ये ईनाम तो इनकी बहादुरी की सलामी में कुछ भी नहीं है फिर भी हम इन सभी नन्हें बहादुरों के इस जज़्बे को सलाम करते हैं.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

हम चाहें जो कुछ सोचें एक बिंदु पर हम यह अनुभव करते हैं कि न चाहते हुए भी हम इस अधडूबे लबादे के एक कोने का प्रयोग करते हैं.

अनंत विजय

71 के अशोक

बीती सोलह जनवरी को हिंदी के वरिष्ठ कवि, आलोचक, स्तंभकार अशोक वाजपेयी इकहत्तर बरस के हो गए. उनके जन्मदिन के मौक़े पर इंडिया इंटरनेशलन सेंटर की एनेक्सी में एक बेहद आत्मीय सा समारोह हुआ. उस मौक़े पर वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल के संपादन में अशोक वाजपेयी पर एकाग्र एक किताब का विमोचन मशहूर चित्रकार रज़ा साहब, अशोक जी और उनकी पत्नी रश्मि जी ने किया. डॉ. अग्रवाल द्वारा संपादित इस पुस्तक का नाम कोलाज : अशोक वाजपेयी है, जिसे राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ने छापा है. समारोह के दौरान ही रज़ा साहब ने यह सवाल उठाया कि किताब का नाम कोलाज क्यों, जिस पर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सफ़ाई देते हुए बताया कि उसमें अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व के विभिन्न रंगों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, इस वजह से पुस्तक का नाम कोलाज रखा गया है. इस किताब को देखने का मौक़ा अभी नहीं मिला है, लेकिन जैसा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बताया उससे अंदाज़ा लगा कि उसमें अशोक जी के मित्रों के लेख और उनके कुछ पुराने फोटोग्राफ्स संकलित हैं. पुरुषोत्तम जी ने इस किताब की तैयारी और उसमें होने वाली देरी के बारे में बताया. कृष्ण बलदेव वैद ने अशोक वाजपेयी को सैकड़ों विशेषणों से बेहद ही रोचक तरीक़े से नवाज़ा है, जो कि कोलाज में संकलित हैं.

कविता में अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल पर तो कविवर जानें, लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजी के वे शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में स्वीकृत होकर हमारी ही भाषा के शब्द जैसे हो गए हैं उनका इस्तेमाल गद्य में तो कम से कम ग़लत नहीं है. जैसे अगर हम कहीं चयनित पारदर्शिता की जगह सेलेक्टिव ट्रांसपेरिंसी लिखें तो प्रभाव भी ज़्यादा होता है और ग्राह्यता भी. अशोक जी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदी के कई बड़े लेखक भाषा की शुद्धता को लेकर ख़ासे सतर्क रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा तो हमारी भाषा भ्रष्ट हो जाएगी.

पुस्तक विमोचन और पुरुषोत्तम अग्रवाल के संक्षिप्त भाषण के बाद अशोक वाजपेयी से सवाल–जवाब हुए. कई शास्त्रीय क़िस्म के सवाल हुए जिसका जवाब अशोक जी ने अपने ही अंदाज़ में दिया. पहला सवाल उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आपकी कविताओं में परिवार बार–बार आता है तो कविता के परिवार और ख़ुद के परिवार में कोई अंतर नज़र आता है. पत्नी के सवालों को वो भी सार्वजनिक तौर पर सामना करना मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन वह भी ठहरे अशोक वाजपेयी. क्रिकेट की शब्दावली में कहें तो अशोक वाजपेयी ने अपनी पत्नी के सवाल को स्टेट ड्राइव करने की बजाय हल्के से टर्न देकर फ्लिक कर दिया. उन्होंने कहा कि मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे परिवार को जितना वक़्त देना चाहिए था, उतना दे नहीं पाया. यहीं पर उन्होंने यह भी कहकर रश्मि जी को ख़ुश कर दिया कि उनका रश्मि में इस बात को लेकर अगाध विश्वास था कि उनके अंदर एक परिवार चलाने की क्षमता है. रश्मि जी के सवालों से ही उन्होंने उनको ख़ुश करने का एक और मौक़ा ढूंढा और सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी की तारीफ़ करके उनको प्रसन्न कर दिया. हालांकि पति के पास कोई विकल्प होता भी नहीं है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि वह बहुलतावाद के हिमायती हैं, लेकिन अगर उनको चुनना पड़ा तो वह अनिच्छापूर्वक कविता और भारत भवन को चुनेंगे. इस बात पर अफ़सोस भी जताया कि वह पूर्वग्रह को नहीं चुन पाए. कविता में बेवजह और फैशन में अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल पर अशोक जी ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई. उन्होंने कहा कि कविता में अंग्रेजी शब्दों का ग़ैरज़रूरी इस्तेमाल उन्हें बौद्धिक लापरवाही लगता है. इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, उससे कविता में कोई विशेष रस भी पैदा नहीं होता. लेकिन अशोक वाजपेयी ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि भाषा का खुलापन बेहद आवश्यक है. कविता में अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल पर तो कविवर जानें, लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजी के वे शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में स्वीकृत होकर हमारी ही भाषा के शब्द जैसे हो गए हैं उनका इस्तेमाल गद्य में तो कम से कम ग़लत नहीं है. जैसे अगर हम कहीं चयनित पारदर्शिता की जगह सेलेक्टिव ट्रांसपेरिंसी लिखें तो प्रभाव भी ज़्यादा होता है और ग्राह्यता भी. अशोक जी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदी के कई बड़े लेखक भाषा की शुद्धता को लेकर ख़ासे सतर्क रहते हैं और

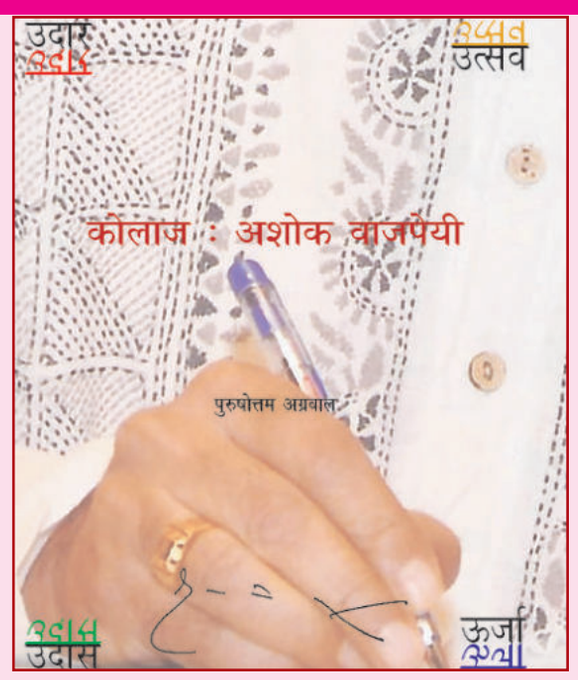

उन्हें लगता है कि अगर हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा तो हमारी भाषा भ्रष्ट हो जाएगी. हिंदी के उन शुद्धतावादियों से मेरा आग्रह है कि वे हिंदी को इतनी कमज़ोर भाषा नहीं समझें कि अंग्रेजी के दो चार शब्दों के इस्तेमाल से वह भ्रष्ट हो जाएगी. मेरा तो मानना है कि किसी भी अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण करने वाली भाषा समृद्ध होती है. अंग्रेजी वालों को तो किसी भी भाषा के शब्दों को लेने में और उसके उपयोग में कभी कोई दिक्क़त नहीं होती. हर वर्ष अंग्रेजी के शब्दकोश में हिंदी के कई शब्दों को शामिल कर उसका धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है. अब जंगल, बंदोबस्त आदि अंग्रेजी में भी उपयोग में आते हैं और पश्चिम के कई लेखकों की कृतियों में इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल को देखा जा सकता है. किसी भी शब्द को लेकर आग्रह और दुराग्रह ठीक नहीं है. हमें तो उस शब्द की स्वीकार्यता और संप्रेषणीयता को देखने और तौलने की ज़रूरत है.

हम फिर से वापस लौटते हैं अशोक जी के सवाल–जवाब के सत्र की ओर. वहां कई छोटे–बड़े सवाल हो रहे थे, शास्त्रीयता कुछ बढ़ रही थी, लेकिन आयोजकों ने समय कम रखा था. जनसत्ता के संपादक ओम थानवी ने अशोक जी पर एक सवाल दाग़ा. थानवी जी ने कहा कि अशोक वाजपेयी उनके जानते सबसे ज़्यादा प्रेम कविताएं लिखने वाले कवियों में से एक हैं. सवाल यह था कि इन प्रेम कविताओं के पीछे राज़ क्या है. लगा कि ओम थानवी की गुगली पर वाजपेयी जी बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक सधे हुए बल्लेबाज़ की तरह ओम जी की गुगली को पहले ही भांप लिया और सीधे बल्ले से उसको खेल दिया. वाजपेयी जी ने माना कि उनकी हर प्रेम कविता किसी ना किसी को संबोधित है. लेकिन यहां एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह यह जोड़ना भी नहीं भूले कि उन्हें यह नहीं पता कि जिनको ये प्रेम कविताएं संबोधित हैं उन तक वे पहुंच पाई या नहीं.

अशोक वाजपेयी के बोलने के अंदाज़ में एक चुटीलापन है. वह बेहद कठिन से कठिन सवाल को भी हल्के–फुल्के अंदाज़ में निबटाने की क्षमता रखते हैं. जब उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि उन्होंने नए लोगों के लिए क्या किया और उनके साथ क्यों नहीं उठते–बैठते हैं तो अशोक जी ने बेहद खिलंदड़े अंदाज़ में यह कहा कि नई पीढ़ी को उनकी सलाह की ज़रूरत ही नहीं है. वे लोग ख़ुद से बहुत समझदार हैं. लेकिन नई पीढ़ी के लिए अपने किए गए कामों को याद भी दिलाया और वहां मौजूद लोगों को यह याद दिलाया कि पहचान सीरीज़ के तहत उन्होंने उस दौर के कई कवियों का पहला कविता संग्रह प्रकाशित करने में अहम भूमिका निभाई थी. इस छोटे लेकिन गरिमापूर्ण कार्यक्रम के बाद रज़ा साहब ने रात्रिभोज का आयोजन किया था. रज़ा साहब ने इस बात पर ख़ुशी ज़ाहिर की कि वह इतने लंबे समय तक फ्रांस में रहने के बाद अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर मुल्क लौट आए हैं. मेरी इच्छा थी कि रज़ा साहब से यह पूछूं कि दशकों तक विदेश में रहने के बाद वह कौन सी वजह थी, जो उनको भारत खींच लाई. लेकिन रज़ा साहब के इतने चाहने वालों ने उनको घेर रखा था कि यह सवाल मेरे मन में ही रह गया. दो साल पहले भी रज़ा साहब का एक इंटरव्यू किया था, लेकिन समारोह में कई कैमरों के बीच उतना वक़्त नहीं मिल पाया था कि तफ़सील से बात हो सके. यह ख्वाहिश है कि रज़ा साहब का एक लंबा इंटरव्यू करूं और उनसे पेंटिंग्स के अलावा उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर बात करूं. देश की राजनीति से लेकर उनके समकालीन पेंटरों के संस्मरण को कैमरे में क़ैद कर सकूं.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समीक्षा

पश्चिमी संस्कृति, साहित्य और क्रांति की रोचक गाथा

कश का विनाश इतालवी लेखक की पुस्तक द रुइन ऑफ कश का हिंदी अनुवाद है. यह एक अच्छी बात है कि विदेशी भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद आसानी से मिल जाता है. इस पुस्तक का अनुवाद बृजभूषण पालीवाल ने किया है. वास्तव में यह किताब पश्चिमी संस्कृति, साहित्य, क्रांति और प्रबोधन की गाथा है. पैनोरामा मेस में इटालो काल्विनो लिखते हैं–द रुइन ऑफ कश, दो विषय लेती है. प्रथम है टैलीरॉ और दूसरा है बाक़ी सब चीज़ें. और बाक़ी सब चीज़ों में वे सब चीज़ें शामिल हैं, जो मानव इतिहास में घटित हुई हैं, सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक. यह एक ऐसी पुस्तक है जो अपने आपको एक भटकन और आवारापन में उजागर करती है, अपनी कल्पना, मनमर्ज़ी और कभी न तृप्त होने वाली जिज्ञासा से मार्गदर्शन प्राप्त करती है, और बनी हुई है टुकड़ों से, इधर–इधर भटकने से, कहानियों, लघुकथाओं और कहावतों से. यह सब इसलिए कि इसे एक अविरल आनंद के साथ पढ़ा जा सके.

सिविलिजेशन में जे टॉल्सन लिखते हैं–ऐसा लगता है कलासो ने मांग करती और कुरेदने वाली पुस्तक को बनाने में कम से कम एक राष्ट्रीय पुस्तकालय को खंगाला होगा. इसकी विषय वस्तु आधुनिक मस्तिष्क का छिछलापन है और आधुनिक संस्कृति की कार्यविधि के कारण ही जिसका कलासो ऐसी बारीकी से विश्लेषण करते हैं. मैं इस विश्लेषण का प्रयोग करने में हिचक रहा हूं जिसके योग्य यह पुस्तक सर्वथा है. सभी महान पुस्तकों की भांति यह पुस्तक हमें अधिक पढ़ती है, हम इसे कम पढ़ते हैं और कला या चिंतन की महान रचनाओं के समान ही यह आपको अपना जीवन बदलने के लिए विवश कर सकती है.

रॉबर्तो कलासो लिखते हैं– सबसे सहज और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वैदिक संबंध सच्चे हैं. उनका अध्ययन करते समय हम धीरे–धीरे उनके अद्भुत पेचीदा जाल को, हर चीज़ पर फैला हुआ है, दोबारा बना लेते हैं. और जिस क्षण से हम संसार में प्रवेश करते हैं, हम यह देखने पर विवश हैं कि यह माचिस की तीलियों का विशाल गिरजाघर है, श्रेष्ठ और निरर्थक. हम जानते हैं कि जीवन स्वयं को किसी न किसी तरीक़े से, उनकी सहायता के बिना भी पुन: उत्पन्न कर लेता है. फिर भी हम गुंजन की इन परतों की ओर, जो हर चीज़ को अपने अंदर लपेटे हुए है, अदम्य रूप से आकृष्ट होते हैं. और हम चाहें जो कुछ सोचें एक बिंदु पर हम यह अनुभव करते हैं कि न चाहते हुए भी हम इस अधडूबे लबादे के एक कोने का प्रयोग करते हैं. वैदिक संबंधों को पूरी तरह अस्वीकार करने में सफल होने वाला जीवन का एकमात्र स्वरूप बैन्थम का है, हमारा फराओ आज लंदन में एक ममी है. एक अनजान जीवन. वैदिक संबंध भव्य रूप में निरर्थक हैं तो बैन्थम भव्य रूप से अपर्याप्त. हम अधर में लटके रहे हैं, भटकते हुए.

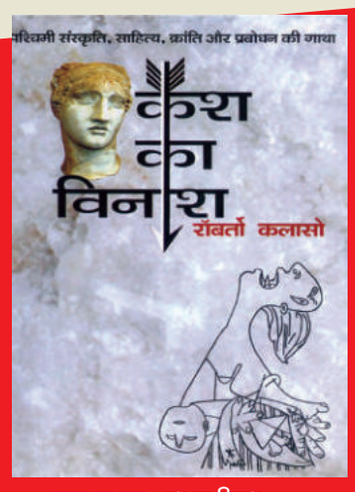

पुस्तक का नाम : कश का विनाश
लेखक : रॉबर्तो कलासो
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
पृष्ठ : 432
मूल्य : 600 रुपये

किसी ऐसे व्यक्ति के होठों पर बलिदान की भाषा सर्वाधिक घिनौनी या काल्पनिक लगती है, जो इसके आधार वाक्य को नहीं जानता. किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों बलिदान का कर्म अत्यंत विध्वंस भरा लगता है जो इसके आधार वाक्य तक को नहीं जानता. किसी ऐसे व्यक्ति से बलिदान संबंधी शब्द सुनने और इसके हाव–भावों को देखने से अधिक बुरा कुछ नहीं जो इसके आधार वाक्य तक को नहीं जानता. वरुण वह उद्गम है जो जीवन को रोकता है और जिसके बिना जीवन असंभव है. जीना शुरू करने के लिए वरुण के फंदे कटने चाहिए और जीते रहने के लिए हमें आदिकालीन द्रव से गीला होने, इससे जुड़ने की ज़रूरत है.

वर्षों के शोध के पश्चात दो बड़े विद्वान वैदिक ऋषियों के विषय में यह कहते हैं–

लिलियन सिल्बर्न के अनुसार, वैदिक ऋषि की दृष्टि में तात्कालिक, आदिकालीन के अनंत, अनेक रूपाकार वाले, जटिल पहलू हैं. दिन के बाद दिन आने की कोई गारंटी नहीं है और ब्रह्मांड की स्थिरता निरंतर ही पुन: स्थापित की जानी है. वैदिक ब्रह्मांड, व्यवहार में क्षोभ, संकुचन और दबाव का दुख भरा ब्रह्मांड है, जो उद्गम के गहरे अंधेरे सागर की सी छवि लिए हुए है. वैदिक ऋषि के लिए कुछ भी निश्चित नहीं है. मानव जीवन या नहीं, सूर्योदय, या पानी का गिरना भी नहीं. इस प्रकार ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाएं एकाकी योजना के अनुरूप हैं. जिस ईश्वर का आह्वान किया जाता है, उसे फिर बतलाया जाता है कि वह इसी कल्याणकारी, सहायक कार्य को करे, जो उसने बहुत पहले किसी ब्रह्मांडीय अथवा श्रेष्ठ बलिदानी व्यक्ति के लिए किया था और अंतिम ऋचाओं में उससे विनय की गई है कि वह उसी कार्य को अगले सूर्योदय के समय पुन: करे, क्योंकि लोग सामान्यत: इस क्षोभ से बचना, रक्षित होना चाहते हैं, जो रात्रि में किसी सहारे के अभाव में उन्हें घेर लेता है.

जेसी हीस्टरमैन के अनुसार, वैदिक चिंतन के लिए समूचा विश्व निरंतर दो ध्रुवों के बीच घूमता रहता था. जन्म और मृत्यु समग्रीकरण और विखंडन, आरोहण और अवरोहण के ध्रुवों के बीच जो अपनी अंतर्क्रिया द्वारा ब्रह्मांड में एक चक्रीय लय उत्पन्न करते हैं.

अंत में, यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि इस पुस्तक के बिना आपकी लाइब्रेरी अधूरी है.

सरफ़राज़ ख़ान
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
सोज़ो गुदाज़

लेखक
बी एस जैन जौहर

प्रकाशक
एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस

मूल्य
250 रुपये

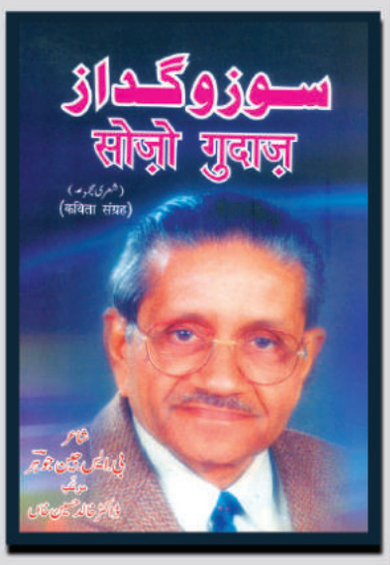

यह किताब कविता संग्रह है. इसमें देवनागरी और फारसी लिपी में कविताएं दी हुई हैं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया | एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

सैमसंग ने हाल में एमवी 800 कैमरा लॉन्च किया है, सैमसंग के इस ख़ास डिजिटल कैमरा एमवी 800, डिजिटल कैमरों की दुनिया में ख़ास है.

अपने मोबाइल को सजाएं

अब आप अपने मोबाइल को नए अंदाज़ में सजाएं. फ्लाई मोबाइल्स ने हाल ही में डीएस109 नाम से एक नया स्टाइलिश फोन डायमंड कट ग्लॉस, डायमंड कट कीपैड और डायमंड शेप्ड मेनू की ख़ूबियों के साथ लांच किया है.

डायमंड कट ग्लॉस, इस उपकरण को अधिक स्टाइलिश और आकर्षक बनाता है. यह फोन, 3 रंग बदलने वाले रिंग्स के साथ पेश किया गया है, जिससे आप फोन को आपके अलग–अलग मूड और साज–सज्जा के अनुरूप नया रूप दे सकते हैं. यह स्टाइलिश और वाजिब क़ीमतों से भरपूर ख़ूबियों वाला फोन, निश्चित रूप से आज के युवाओं की पहली पसंद बनेगा, जिनके लिए मोबाइल महज़ बातचीत करने का साधन न होकर स्टाइल स्टेटमेंट बन गए हैं. यह पैसे का पूरा मूल्य प्रदान करने वाला फोन है, जो आकर्षक रूप रंग और प्रभावशाली डिज़ाइन से सुसज्जित है. 32 जीबी विस्तार योग्य मेमोरी और मॉइक्रो एचडी कॉर्ड के लिए कॉर्ड स्लॉट के साथ, यह आपकी स्टोरेज संबंधी सभी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है. समग्र रूप में यह उपकरण आपको आपकी इच्छानुसार अधिकाधिक डाटा स्टोर करने और संगीत, फिल्मों और वीडियो का असीमित आनंद लेने की सुविधाएं प्रदान करता है. इसमें फोन बुक में 100 प्रविष्टियों और 50 एसएमएस की क्षमता है.

इसकी मुख्य विशेषताएं हैं टेलिस्कोपिक एफएम रेडियो, ऑडियो प्लेयर इक्किलाइज़र के साथ, बड़े स्पीकर 20/30 एमएम, 100 प्रविष्टि वाली फोनबुक, 50 एसएमएस क्षमता, दोहरा सिम, 4.6 सेमी क्यूक्यूवीजीए कलर डिस्प्ले, 1.3 एमपी कैमरा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, टार्च लाइट. फ्लाई डीएस109 की क़ीमत 1199 रुपये मात्र है.

सीगेट का वेरीजोन वायरलेस से गठजोड़

सीगेट टेक्नोलॉजी पीएलसी बैट्री से चलने वाले पहले वायरलेस स्टोरेज समाधान गो लेक्स सैटेलाइट ड्राइव–की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सीगेट ने वेरीजोन वायरलेस के साथ गठजोड़ किया है, ताकि दुनिया के पहले 4जी एलटीई मोबाइल वायरलेस स्टोरेज सोल्यूशन का टेक्नोलॉजी शोकेस मुहैया कराया जा सके. उद्योग की यह पहली खोज वेरीजोन बूथ में काम करती देखी जा सकती है. 4जी एलटीई कनेक्टेड मोबाइल वायरलेस स्टोरेज टेक्नोलॉजी निम्नलिखित के लिए अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेगी. यह आपके मोबाइल उपकरण की स्टोरेज क्षमता इतनी बढ़ा देगा कि आप 300 से ज़्यादा एचडी मूवी अपने आईपैड या एनरायड टैबलेट पर देख सकेंगे. 4जी एलटीई पर म्यूज़िक, मूवी और फोटो डाउनलोड कीजिए और इसे अपने तीन मोबाइल उपकरणों के लिए पूरे वाईफाई में स्ट्रीम कर दीजिए. बिजली जैसी तेज़ वेरीजोन 4जी एलटीई नेटवर्क का उपयोग आते–जाते मनोरंजन की अनंत लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए कीजिए. साथ ही यह तीन वाई फाई एनैबल्ड मोबाइल उपकरणों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराता है. उद्योग में पहला, नए थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी समाधान है. सीगेट ने पहली बार अपना बहुप्रतीक्षित गो लेक्स थंडरबोल्ट एडैप्टर और गो लेक्स डेस्क थंडरबोल्ट एडैप्टर पेश करने का प्लान किया है. सीगेट ने पहले इन दोनों उन्नत इंटरफेस उत्पादों का कामकाजी प्रोटोटाइप पेश किया था और इसे नवंबर 2011 में पेश किया गया था. नई थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले ये दोनों उत्पाद पहले हैं और उपभोक्ता उनका उपयोग सिंगल ड्राइव एनक्लोजर के लिए ख़ूब करते हैं. गो लेक्स थंडरबोल्ट एडैप्टर इस साल की पहली तिमाही के दौरान उपलब्ध रहेंगे, जबकि गो लेक्स डेस्क थंडरबोल्ट एडैप्टर इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही से पहले उपलब्ध होने की संभावना है. नए पुरस्कार प्राप्त मोमेनटस एक्सटी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड हार्ड ड्राइव की स्पीड और परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करने के लिए सीगेट एक गेमिंग डिमांसट्रेशन का आयोजन करेगा, जिसमें एक जैसे दो एलियनवेयर एम18एक्सडुअल ड्राइव लैपटॉप कंप्यूटर का आमने–सामने का मुक़ाबला होगा. एक में सीगेट का नया सॉलिड स्टेट हाइब्रिड मोमेनटस एक्सटी ड्राइव होगा और दूसरे में 7200 आरपीएम 2.5 ईंच हार्ड डिस्क ड्राइव होगा.

स्कैनर विद कैमरा

आई बॉल ने स्कैनर को कैमरे के साथ पेश किया है. यह स्कैनर विद कैमरा किसी भी तरह के ए4 साइज़ के डॉक्यूमेंट को एक सेकंड में कैप्चर कर सकता है, चाहे वह स्कैन करना हो या फोटोकॉपी करना हो. इसमें एम्बिएंट लाइट यानी चारों तरफ़ से एक सामान लाइट है और सॉफ्टवेयर के ज़रिये इनबिल्ट ओसीआर फीचर है. ओसीआर फीचर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीकगनिशन फीचर जिससे टेक्सट कैरेक्टर को एडिट कर बदला जा सकता है. इससे कैप्चर हुए डॉक्यूमेंट का किसी भी प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं.

इसका प्रेजेंटर किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिये बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकता है. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन किसी भी ऑपरेशन या डेमो को रिकॉर्ड करते हैं. इसका इमेज सेंसर 2 मेगापिक्सल वाला सीएमओएस एक्टिव पिक्सल डिजिटल इमेज सेंसर है. इसका स्कैनर आसानी से फोल्ड हो सकता हैं. इससे किसी भी तरह के आने वाले कैप्चर के आउटपुट का ईमेज रिजोल्यूशन 1600/1200 पिक्सल्स है और इंटरफेस यूएसबी 2.0 है. इसके कैप्चर ईमेज फॉरमेट जेपीजी, बिटमैप टिफ, पीडीएफ, पीएनजी, टीजीए और पीसीएक्स में होंगे. यह स्कैनर विंडोज एक्स पी, विस्टा, विंडोज 7, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है.

इस स्कैनर के साथ दिए जा रहे बंडल्ड एक्सेसरीज हैं ड्राइवर यूएसबी, यूएसबी केबल, ड्राइवर सीडी और सॉफ्ट पैड. यह स्मार्ट गैजेट कहीं लाने ले जाने में आसान तो है ही इस्तेमाल करने में भी आसान है. इस स्कैनर विद कैमरा की क़ीमत है लगभग सात हज़ार रुपये. यह एक साल के मैन्यूफैक्चरर वारंटी पीरियड के साथ बाज़ार में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कूल डिजाइन के हेडफोन लॉन्च

हेडफोन भी धीरे–धीरे मोबाइल फोन की तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. आईपॉड हो या फिर स्मार्टफोन हेडफोन की चाहत हर किसी को होती है. बाज़ार में हर वर्ग के अनुसार अलग–अलग क्वालिटी के हेडफोन उपलब्ध हैं. सोनी, जाबरा के अलावा फिलिप्स और सेनहाइजर भी हेडफोन बनाने की अग्रणी कंपनी है. कूल डिज़ाइन के साथ कूल कलर से लैस सेनहाइजर ने नए हेडफोन लांच किए हैं. हेडफोन का लुक देखने में दूसरे हेडफोन्स के मुक़ाबले काफ़ी अलग और अट्रैक्टिव है. हेडसेट मैन्यूफैक्चर ने नए हेडफोन को बनाने में नई तकनीक के साथ यूजर कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है. सेनहाइजर ऑडियो बाज़ार की दिग्गज कंपनी है जिसने यूज़र के कलर ऑप्शन देने के लिहाज़ से हेडफोन को रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्रोंज, ब्राउन और ब्लू कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है. इसमें से सेनहाइसर ने सीएक्स 215 और एमएक्स 365 नाम से दो हेडफोन लांच किए हैं, जिनकी क़ीमत 2000 रुपये से शुरू होती है. हेडफोन में सभी मॉडलों में सॉफ्ट ईयर पैड दिए गए हैं, जो यूजर को देर तक म्यूज़िक सुनने में काफ़ी सहूलियत देते हैं. हेडफोन में क्लियर और क्रिस्पी ऑडियो क्वालिटी दी गई है. और यह बिना किसी तरह का दर्द पहुंचाए कानों में पूरी तरह से फिट बैठते हैं. यह वज़न में काफ़ी हल्के हैं और इनकी ख़ासियत है सुप्रीम क्वालिटी का साउंड. यह पोर्टेबल साइज में बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं.

सैमसंग का एमवी 800 कैमरा लॉन्च

डिजिटल कैमरे में फीचर और नई तकनीक का होना बेहद ज़रूरी है. अगर आप कोई भी डिजिटल कैमरा ख़रीदने जा रहे हैं तो कैमरे में दिए गए फीचरों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैमरे में अच्छे रेजोलूशन और लेंस का होना बेहद ज़रूरी है. सैमसंग ने हाल में एमवी 800 कैमरा लॉन्च किया है, सैमसंग के इस ख़ास डिजिटल कैमरा एमवी 800, डिजिटल कैमरों की दुनिया में ख़ास है, क्योंकि साधारण डिजिटल कैमरों के मुक़ाबले सैमसंग एमवी 800 की स्क्रीन को 180 डिग्री पर घुमाया जा सकता है. तकनीकी रूप से कैमरे में 16.5 मेगापिक्सल का लेंस सपोर्ट दिया गया है. अगर क़ीमत के हिसाब से देखा जाए तो सैमसंग एमवी800 में मौजूद रोटेटिंग स्क्रीन का फीचर इस रेंज के किसी भी कैमरे में मौजूद नहीं है. कैमरे में 3 इंच की एलसीडी टच स्क्रीन दी गई है. घुमावदार टच स्क्रीन की वजह से फोन की तरह ही किसी भी एंगल से फोटो आसानी से खींचे जा सकते हैं. एमवी 800 से फोटो खींचने के साथ 720 पिक्सल सपोर्ट के साथ 30 फ्रेम प्रति सेंकेंड की गति से हाइडिफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है. सैमसंग एमवी 800 के कुछ ख़ास फीचर में इसमें लगा सीसीडी सेंसर, ड्युल इमेज स्टेबलाइजेशन, स्मार्टफोन ऑटो की सुविधा, फेस डिटेक्शन रिकग्नाइजेशन सपोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर दिए गए हैं. अगर आप सैमसंग का एमवी 800 रोटेटिंग स्क्रीन कैमरा ख़रीदना चाहते हैं, तो यह 15,990 की अनुमानित क़ीमत पर बाज़ार में उपलब्ध है.

ओसीआर फीचर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीकगनिशन फीचर जिससे टेक्सट कैरेक्टर को एडिट कर बदला जा सकता है. इससे कैप्चर हुए डॉक्यूमेंट को किसी भी प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं. इसका प्रेजेंटर किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिये बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकता है. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन किसी भी ऑपरेशन या डेमो को रिकॉर्ड करते हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

अब रैंकिंग में गिरे

ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार से भारतीय क्रिकेटरों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग भी गिर गई है. बल्लेबाज़ों के शर्मनाक प्रदर्शन के कारण लगातार सातवीं हार झेल चुकी भारतीय टीम को जहां अब अपनी नंबर दो की कुर्सी दक्षिण अफ़्रीका के हाथों गंवानी पड़ेगी, वहीं विराट कोहली को छोड़कर शेष सभी बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है. विराट ने पर्थ टेस्ट की दोनों पारियों में अपने प्रदर्शन की बदौलत 39 स्थानों की छलांग लगाई है. निराशाजनक दौर से गुजर रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जहां चार स्थानों का नुक़सान उठाना पड़ा है, वहीं पिछली 24 पारियों से अपने अंतरराष्ट्रीय शतकों के महाशतक का इंतज़ार कर रहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी तीन स्थानों का नुक़सान झेलकर नवें स्थान पर खिसक गए हैं. सचिन के अब टॉप 10 से बाहर होने का ख़तरा पैदा हो गया है. इसी तरह टीम के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग जहां दो स्थान गिरकर 24वें नंबर पर आ गए हैं, वहीं उनके जोड़ीदार गौतम गंभीर एक स्थान लुढ़क कर 32वें पायदान पर. इसी तरह वीवीएस लक्ष्मण भी तीन स्थान नीचे फिसल कर 21वें पायदान पर आ गए हैं.

स्पोर्ट्स ऑफ द वीक

अंडर वॉटर हॉकी

राजेश एस कुमार

भारत में स्पोर्ट्स का जिक्र अमूमन क्रिकेट पर ही आकर ख़त्म हो जाता है. नाम के लिए भले ही हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी देश को इसी खेल में उठानी पड़ती है. रही बात फुटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, टेनिस और शतरंज जैसे खेलों की, तो इनकी बात सिर्फ़ ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों तक सीमित रहती है. बाक़ी पूरा देश तो सिर्फ़ क्रिकेट से ही टाइम पास करता है. जब भारत में पहली बार फॉर्मूला रेस हुई तो ज़्यादातर लोगों को इस खेल की तकनीकी जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि इसका टिकट महंगा है और इसमें कारें दौड़ती हैं. जब तक लोग इसे समझते, तब तक यह ख़त्म हो चुका था. स्पोर्ट्स ऑफ द वीक नामक इस कॉलम में हम हर हफ्ते दुनिया के कुछ प्रेरणादायक, अनोखे, रोचक और अजीबोग़रीब खेलों से रूबरू कराएंगे, जो भारतीय खेलप्रेमियों की नज़रों से अभी भी अछूते हैं. इस हफ्ते का स्पोर्ट्स ऑफ द वीक है अंडर वॉटर हॉकी यानी पानी के अंदर हॉकी. अंडर वॉटर हॉकी को ऑक्टोपुश भी कहा जाता है. पानी के अंदर खेला जाने वाला यह खेल दुनिया भर में लोकप्रिय और दिलचस्प है. इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में 1954 में हुई थी. स्वीमिंग पूल के भीतर खेला जाने वाला यह खेल सामान्य हॉकी से न केवल कई मायनों में दिलचस्प है, बल्कि इसकी रूपरेखा और नियम-क़ानून भी काफी अलग हैं. इसके ऑक्टोपुश नाम के संबोधन के पीछे की कहानी कुछ यूं है. यह ऑक्टोपुश शब्द दो शब्दों ऑक्टो यानी आठ और पुश यानी धक्का देना से मिलकर बना है. चूंकि पहले इस खेल में एक टीम में आठ खिलाड़ी भाग लेते थे और इसकी बॉल यानी पक को धक्का दिया जाता है. इसीलिए ऑक्टो और पुश को मिलाकर इसे ऑक्टोपुश या ऑक्टोपश नाम दिया गया. हालांकि अब इसमें दस-दस खिलाड़ियों की दो टीमें भाग लेती हैं. मैच में प्रत्येक टीम के छह खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. बाकी खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर रखा जाता है. खेल की शुरुआत से पहले पक यानी बॉल को पूल की सतह के बीचोबीच रख दिया जाता है. जैसे ही बजर (एक प्रकार का अलार्म साउंड) बजता है, खिलाड़ी अपनी-अपनी स्टिक के साथ पानी की सतह पर जाकर प्रतिद्वंद्वी टीम पर गोल दागना शुरू कर देते हैं. मजे की बात तो यह है कि इसमें रेफरी को भी पानी के अंदर जाकर खिलाड़ियों पर ध्यान देना पड़ता है. दोनों टीमों की तरफ़ की दीवारों को ही गोल प्वाइंट माना जाता है. एक बार पानी के अंदर जाने पर खिलाड़ी या तो तब बाहर आते है, जब सामने वाली टीम पर गोल हो जाए या रेफरी को लगे कि कहीं पर नियमों का उल्लंघन हुआ है. ज़रूरत पड़ने पर वह कई तरह की पेनाल्टियां भी देता है. पानी में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों को ड्राइविंग मास्क, स्विमफिन, ग्लोव्स आदि पहनने के लिए दिए जाते हैं. अंडर वॉटर हॉकी के लिए हॉकी स्टिक काफी छोटी होती है. ताजा नियमों के अनुसार, यह 350 मिमी से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. इसका रंग काला और सफेद होता है. वहीं पक का आकार आइस हॉकी की बॉल के आकार जितना होता है. यह बॉल लेड या इसी प्रकार के अन्य किसी मैटेरियल से तैयार की जाती है, जिस पर प्लास्टिक कवर रहता है. मैच शुरू करते समय इस गेंद को पूल की सतह पर बीच में रखा जाता है. हर दो साल में ऑक्टोपुश की वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होता है. चूंकि यह पानी के भीतर खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसके दर्शकों की संख्या कम ही रहती है. फिर भी इसे दुनिया के मजेदार और दिलचस्प खेलों में गिना जाता है. अगले सप्ताह बात होगी किसी और मजेदार खेल पर.

rajeshy@chauthiduniya.com

मैराथन टू ओलंपिक

भारत के लिए अच्छी ख़बर यह रही कि उसके लंबी दूरी के धावक राम सिंह यादव मुंबई मैराथन के माध्यम से लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहे. वह भारत की ओर से लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले एथलीट हैं. मुंबई मैराथन में केन्या और इथोपिया के धावकों का दबदबा रहा. पुरुषों की फुल मैराथन (42 किलोमीटर) वर्ग में केन्या के लाबान मोईबेन, जबकि महिला वर्ग में इथोपिया की नेटसानेट अबेयो चैंपियन रहे. अबेयो का यह तीसरा मैराथन खिताब है. पुरुषों में दूसरे स्थान पर इथोपिया के राजी असेफा और तीसरे स्थान पर केन्या के जॉन कयुई रहे. देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई में क़रीब 39,000 से अधिक प्रतियोगियों के साथ मुंबई मैराथन 2012 का नवां संस्करण संपन्न हुआ. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सीएसटी) से शुरू हुई इस दौड़ में बॉलीवुड स्टारों ने भी शिरकत की. मॉडल-अभिनेता मिलिंद सोमन, उद्योगपति अनिल अंबानी और सिद्धार्थ माल्या ने भी शिरकत की. दो स्पर्धाओं के ब्रैंड एंबेसडर एवं बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज ने भी हिस्सा लिया. मैराथन की कुल ईनामी राशि 3,40,000 डॉलर है. इस साल हर वर्ग की पुरस्कार राशि में 15,000 डॉलर की बढ़ोत्तरी की गई. मैराथन दौड़ सीएसटी से होकर बांद्रा, राजीव गांधी बांद्रा-वर्ली सी लिंक और कई विभिन्न रूटों से होकर सीएसटी वापस आई.

अब कोच की निगरानी

खेल मंत्रालय ने अब अनुबंधित विदेशी प्रशिक्षकों की कोचिंग की समीक्षा के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने टीमों के साथ जुड़े भारतीय प्रशिक्षकों का भी मूल्यांकन करने को कहा है. लंदन ओलंपिक तक उन्हीं खिलाड़ियों को विदेशी दौरे कराने को कहा गया है, जो लंदन का टिकट हासिल कर चुके हैं या फिर ओलंपिक क्वालीफाई करने का माद्दा रखते हैं. खेल सचिव सिंधुश्री खुल्लर ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उक्त निर्देश दिए. उन्होंने विदेशियों के साथ-साथ भारतीय प्रशिक्षकों का भी मूल्यांकन करने को कहा. इस काम से लंदन ओलंपिक की चल रही तैयारियों का सही ढंग से पता लग सकेगा. मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए एथलीटों के दौरे को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. डिसकस थ्रोअर हरवंत कौर अपने प्रशिक्षक प्रवीर सिंह के साथ ओलंपिक की तैयारियों के लिए दक्षिण अफ़्रीका जा रही हैं. इससे पहले कृष्णा पूनिया अमेरिका, मयूखा जॉनी जर्मनी, ओ पी सिंह हंगरी, प्रीजा श्रीधरन, कविता राउत, ओ पी जैशा और सुधा सिंह कीनिया में ट्रेनिंग के लिए जा चुकी हैं. जबकि डिसकस थ्रोअर विकास गौड़ा अमेरिका में ही अपने पिता के संरक्षण में ट्रेनिंग कर रहे हैं.

चोट पर सवाल नहीं

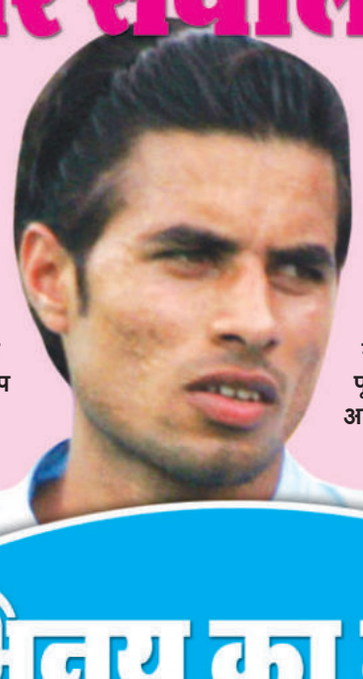

दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ शुरू होने से ठीक पहले हॉकी टीम के स्टार मिडफील्डर गुरबाज़ सिंह को नई दिल्ली में चल रहे कैंप से घर भेज दिया गया. टीम सूत्रों के अनुसार, वह अपने दाएं घुटने की चोट के साथ ही खेलते रहे. असल में उन्हें अपनी चोट की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था. उनके लंगड़ाने से टीम प्रबंधन को इसका पता लगा. गुरबाज़ को तीन हफ्ते तक अपने घर में रहकर आराम करने को कहा गया है. मौजूदा स्थितियों को देखते हुए फरवरी में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह बनाना गुरबाज़ के लिए आसान नहीं होगा. गुरबाज़ को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है. ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान टीम का डॉक्टर उनकी चोट पर निगाह रखेगा. टीम सूत्रों ने बताया कि गुरबाज़ के साथ सिर्फ़ चोट की समस्या नहीं है. उनका प्रदर्शन हैरान कर देने वाले स्तर के साथ गिरा है. ऐसे में मौजूदा स्थितियों में वह टीम के साथ तालमेल में पिछड़ रहे थे. इसलिए उन्हें आराम करने को कहा गया है. तीन हफ्ते बाद कैंप में दोबारा आने की स्थिति में उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. वर्ल्ड कप क्वालीफायर में उनका खेलना ऐसे टेस्ट के नतीजों पर निर्भर करेगा. हालांकि टीम प्रबंधन ने अभी से उनकी रिप्लेसमेंट पर काम करना शुरू कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, बिरेंद्र लाकड़ा गुरबाज़ की जगह लेने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं. पिछले छह महीनों में इस मिड फील्डर ने अपने खेल से काफी प्रभावित किया है. वैसे गुरबाज पिछले दो सालों के दौरान भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक होकर उभरे. उल्लेखनीय है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारियों के मद्देनज़र 45 संभावित खिलाड़ियों का कैंप चल रहा है.

अभिनय का कमाल

देर से ही सही, लेकिन अभिनव बिंद्रा ने किसी बड़े कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीतने के सूखे को ख़त्म कर दिया. बीजिंग ओलंपिक के बाद से अभिनव को इस प्रदर्शन की तलाश थी, जो दोहा (कतर) में शुरू हुई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पूरी हुई. अभिनव ने यहां अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी और 10 मीटर एयर राइफल में बीते वर्ष वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले चीन के झू क्विनान को परास्त किया. गगन नारंग चौथे स्थान पर रहे. चीन (कुल स्कोर 1793) ने विश्व रिकॉर्ड के साथ टीम गोल्ड जीता, जबकि भारत के हिस्से में रजत आया. वहीं 50 मीटर फ्री पिस्टल में भारत के ओलंपिक में खेलने की आशाएं धूमिल हो गईं. ओम प्रकाश, ओंकार सिंह एवं अमनप्रीत में से कोई भी टॉप टेन में स्थान नहीं बना सका. दो महीने पहले अभिनव की पुस्तक-ए शॉट एट हिस्ट्री के विमोचन के दौरान उनके फार्म और रणनीति पर किए गए सवाल पर उनकी ओर से कहा गया था कि पिछला प्रदर्शन चिंता की बात नहीं है, रणनीति लंदन ओलंपिक से पहले फॉर्म में वापसी करने की है. अब उन्होंने कमाल कर दिया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 30 जनवरी–05 फरवरी 2012

केट को गाड़ी ड्राइव करने से बहुत डर लगता है. अपने इस डर पर क़ाबू पाने के लिए उन्होंने अपने ख़ाली समय में गोल्फ कार को सीखने की कोशिश की.

हॉलीवुड से केट को ड्राइविंग का डर

क्या दर्शकों को इस बात पर विश्वास होगा कि परदे पर ऐसा रोमांचकारी एक्शन करने वाली अभिनेत्री को गाड़ी चलाना भी नहीं आता? लेकिन आप माने या न माने यह सच है. ब्रिटिश अभिनेत्री केट बेकिंसेल जिन्होंने सोनी पिक्चर्स की जल्दी ही रिलीज़ होने वाली लोकप्रिय एक्शन फिल्म ख़ूंख़ार दरिंदों की वापसी अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग (हिंदी में) में काम किया है. इस फिल्म से पहले बनी फिल्म अंडरवर्ल्ड की दो सीरीज़ में भी उन्होंने अभिनय किया है. फिल्मों में तो वह शानदार एक्शन करती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में केट पिछले कई सालों से कोशिश कर रही हैं कि जैसे-तैसे उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, लेकिन इसके लिए वह लिखित परीक्षा भी पास नहीं कर पाईं. केट को गाड़ी ड्राइव करने से बहुत डर लगता है. अपने इस डर पर क़ाबू पाने के लिए उन्होंने अपने ख़ाली समय में गोल्फ कार को सीखने की कोशिश की. ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में उनका कहना है कि अब तो कुछ समय बाद मेरी बेटी ही ड्राइविंग लाइसेंस ले लेगी, ऐसा लगता है. हर तीन साल के अंतराल में रिलीज़ हुई एक्शन व रोमांच से भरपूर हॉलीवुड फिल्म ख़ूंख़ार दरिंदों की वापसी अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग (हिंदी में) थ्री डी, लोकप्रिय फिल्म अंडरवर्ल्ड की कड़ी की चौथी फिल्म है. 89 मिनट की अवधि वाली यह फिल्म हिंदी भाषी दर्शकों के लिए हिंदी में डब की गई है. मारधाड़ वाली इस फिल्म में अभिनय किया है अभिनेत्री केट बेकिंसेल ने, जो पहले आई फिल्म अंडरवर्ल्ड की दो सीरीज़ में भी थीं. उनके अलावा इस फिल्म में स्टेफेन रिया, मिशेल एले, थिओ जेम्स, इंडिया एइस्ले और चार्ल्स डांस भी हैं. एक्शन दृश्यों से भरपूर सोनी पिक्चर्स की फिल्म ख़ूंख़ार दरिंदों की वापसी का निर्देशन किया है स्वीडन के दो निर्देशक मेंस मर्लिंड और ब्जोर्न स्टेन ने. फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी है इस फिल्म केनिर्माता लेन वाइजमैन और जॉन ह्राविन ने. मार-धाड़ की फिल्मों के शौक़ीनों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि यह फिल्म जल्दी ही रिलीज़ होने वाली थ्री डी फिल्म है. सोनी पिक्चर्स की फिल्म ख़ूंख़ार दरिंदों की वापसी में पिछली सभी फिल्मों से दोगुना मनोरंजन तो मिलेगा ही, साथ में बहुत सारा रोमांच भी होगा.

भौमिक की अदाकारी

फिल्म साडा अड्डा में भौमिक संपत की अदाकारी की ख़ूब तारीफ़ हुई, ज़्यादा बड़े स्टार नहीं हैं भौमिक. लेकिन फिल्म में उनके रोल की काफ़ी सराहना हुई. उनके किरदार को क्रिटिक्स ने बहुत प्राकृतिक कहा. शुरुआत तो भौमिक की अच्छी हुई है. उनके करियर में संभावनाएं नज़र आ रही हैं. वैसे भौमिक को जनता ने पहचाना रियलिटी शो इंडिया बेस्ट सिने स्टार की खोज के सीजन 2 से और इस सीजन में उनकी जीत ने उन्हें बॉलीवुड की गलियों तक पहुंचा दिया. फिर इंडस्ट्री में अपनी ख़ास जगह बनाने के लिए उन्होंने गणेश आचार्य से डांस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और ऐक्टिंग में महारथ हासिल करने के लिए किशोर नमित कपूर और केवल शर्मा ऐक्टिंग अकादमी गए. इसके बाद ही वह अपना जलवा बिखेरने सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आए. इससे पहले उन्होंने ऐड फिल्मों में भी काम किया और ख़ुद को नोटिस करवाया. भौमिक ब्रिटानिया, कैडबरी इकलेयर्स, रिलायंस, डाबर वाटिका जैसे कई विज्ञापनों में दिखाई दे चुके हैं. लेकिन उन पर ग्लैमर का भूत नहीं चढ़ा. फिल्म साडा अड्डा की शूटिंग के दौरान, फ़ुर्सत मिलने पर भौमिक और उनकी टीम ने मॉरिशस घूमने का प्लान बनाया. अन्य टीम मेम्बर्स के साथ भौमिक भी घूमने निकल गए, लेकिन प्रोडक्शन की टीम को तकलीफ़ न देकर उन्होंने ख़ुद ही टैक्सी ली और निकल पड़े. शॉपिंग करने के बाद पूरी टीम जब काउंटर पर बिल का पेमेंट करने गई, तब भौमिक ने वहां बैठी महिला से पूछा कि टैक्सी कहां मिलेगी. तब उस महिला ने बड़ी हैरानी से जवाब देते हुए बताया कि मॉरिशस में साढ़े आठ बजे के बाद टैक्सी नहीं मिलती. फिर अफरा-तफ़री में एक टैक्सी मुश्किल से मिली, जिसने उन्हें होटल तक पहुंचाया और दोगुना किराया वसूल किया.

शिल्पा ओडिसी नृत्य करेंगी

आगामी फिल्म द डिज़ायर में शिल्पा पारंपरिक शैली का ओडिसी नृत्य तो करेंगी, लेकिन ज़रा हॉट मूव्स के तड़के के साथ. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने लटकों-झटकों से पहले ही यूपी बिहार हिला चुकी हैं. कभी अक्षय का दिल चुरातीं, तो कभी जॉन को बाउंस करातीं शिल्पा एक बार फिर हॉट डांस नंबर्स लेकर आ रही हैं. यू तो वह बेहतरीन डांसर हैं, लेकिन इस फिल्म में ओडिसी नृत्य करने के लिए शिल्पा ने बाक़ायदा ट्रेनिंग भी ली है. वह पिछले काफ़ी समय से सिल्वर स्क्रीन से ग़ायब थीं, और लौटीं भी तो फिल्म दोस्ताना में आइटम नंबर के साथ. लेकिन इसके साथ ही वह सिल्वर स्क्रीन पर आने की कई योजनाओं को लेकर व्यस्त थीं. फिल्म द डिज़ायर पहले तो किसी और निर्माता ने शुरू की थी, लेकिन जब से उनकी मां ने इसे प्रोडयूस करने का फ़ैसला किया है तब से वह इस फिल्म को अपने घर की फिल्म कहती हैं. दरअसल, द डिज़ायर का कुछ काम बाक़ी था, तभी इसके पूर्व निर्माता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई. इस चक्कर में यह फिल्म क़रीब एक साल तक रुकी रही. उसके बाद प्रोड्यूसर का ज़िम्मा शिल्पा की मां ने ले लिया. इस फिल्म में चाइनीज एक्टर जिया यु हैं. असल में यह एक ओडिसी डांसर गौतमी और चीनी आर्टिस्ट जय ली की कहानी है, जिनकी मुलाक़ात मलेशिया में होती है. चूंकि जिया की मां भी इंडियन है, इसलिए वह ख़ुद को गौतमी के प्रति आकर्षित होने से रोक नहीं पाता. जय के रोल में जिया को लेने का फ़ैसला उनकी मां के प्रोड्यूसर बनने के पहले ही लिया जा चुका था. और बाद में इसे बदला नहीं गया, क्योंकि वह चीन के शाहरुख़ ख़ान हैं. यूनीक पटकथा वाली द डिज़ायर को लोग ड्रामैटिक के साथ-साथ हिंग्लिश फिल्म भी कह सकते हैं. इसमें आज के मिज़ाज के गाने नहीं हैं. लंबे अंतराल के बाद अपनी वापसी के बारे में कहते हुए शिल्पा अपने फैंस को यह बात ज़रूर बताना चाहती हैं कि अब उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं. अब अपने फिल्मी करियर या रोल पर ध्यान देने की बजाय वह ख़ुद पर, घूमने पर और बिजनेस पर ध्यान देना चाहती हैं. अगर इन सब के बीच मनपसंद काम दिखेगा, तभी फिल्में करेंगी. फ़िलहाल शिल्पा अपने आने वाले बच्चे पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं.

फिल्म प्रीव्यू

गली-गली चोर है

बॉलीवुड में रूमी जाफ़री की पहचान एक लेखक के रूप में है. कई हिट फिल्मों की कहानी, स्क्रीन प्ले और संवाद उन्होंने लिखे हैं. डेविड धवन के लिए उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में लेखन किया है. हीरो नं 1, घरवाली बाहरवाली, बड़े मियां छोटे मियां, दुल्हन हम ले जाएंगे, मैंने प्यार क्यों किया जैसी हिट फिल्मों से उनका नाम जुड़ा है. बतौर निर्देशक रूमी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत हैं. अमिताभ, सलमान और प्रियंका जैसे सितारों को लेकर उन्होंने गॉड तुस्सी ग्रेट हो (2008) बनाई, लेकिन फिल्म बुरी तरह पिट गई. लाइफ पार्टनर (2009) की भी चर्चा नहीं हुई. गली-गली चोर है बतौर निर्देशक उनका तीसरा प्रयास है. भोपाल में रहने वाला भारत एक आम आदमी है. स्कूटर पर घूमने वाला भारत पार्ट टाइम कैशियर और रामलीला में पार्ट टाइम हनुमान है. भारत अपने पिता शिवनारायण के साथ रहता है, जिनकी ख्वाहिश है कि अपना देश भ्रष्टाचार मुक्त हो. भारत की पत्नी निशा एक स्कूल टीचर है. भारत का निशा हर तरह से ध्यान रखती है, लेकिन स्वभाव से थोड़ी शक्की है. वह चाहती है कि भारत की तरक्क़ी हो. वह कैशियर से मैनेजर बने. इस छोटे और ख़ुशहाल परिवार में अमिता नामक एक मेहमान भी है. ख़ूबसूरत अमिता एक कॉल सेंटर पर काम करती है और चाहती है कि कभी-कभी भारत भी उसे अपने स्कूटर पर उसे ऑफिस छोड़ दिया करे. रामलीला में भारत अब राम का रोल करना चाहता है जो अब तक सत्तू त्रिपाठी निभाते आए हैं. सत्तू के बड़े भैया मंकू त्रिपाठी एमएलए हैं. दोनों भाइयों का भारत से छत्तीस का आंकड़ा है. सत्तू ख़राब एक्टर है और भारत से इस बात से नाराज़ है कि हनुमान के रूप में सारी तालियां वह बटोर ले जाता है. मंकू इसलिए नाराज़ है कि चुनाव प्रचार के लिए अपने घर का अतिरिक्त कमरा भारत ने उन्हें नहीं दिया. ऊपर से वह कमरा भारत ने उनके विरोधी उम्मीदवार मोहनलाल को दे दिया. मोहनलाल, भारत के पिता का अच्छा दोस्त है. भारत के घर का दरवाज़ा एक रात हवलदार परशुराम कुशवाहा खटखटाता है. वह भारत को उस टेबल, पंखे के बारे में बताता है, जो उसके घर से चोरी हुआ है. कुशवाहा का कहना है कि भारत कोर्ट आ जाए, जहां स्थानीय पान वाले बच्चू गुलकंद के सामने चोर चुन्नू फ़रिश्ता अपना जुर्म क़बूल लेगा और भारत को पंखा मिल जाएगा. घटनाक्रम कुछ ऐसे घटते हैं कि यह मामला उलझ जाता है और भारत को न चाहते हुए भी पुलिस, अपराधी, गवाह, वकील और जज को घूस देनी पड़ती है, तब जाकर उसे पंखा वापस मिलता है. यह घटना एक पार्ट टाइम कैशियर और हनुमान का रोल निभाने वाले कलाकार को नेशनल न्यूज़ का हिस्सा बना देती है. कैसे? इसका जवाब फिल्म में मिलेगा.

जेनेलिया हॉलीवुड जाना चाहती हैं

बॉलीवुड की एकमात्र एक्ट्रेस जिन्हें फिल्मों में कॉलेज गर्ल के रूप में एडजस्ट होने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह ख़ुद ही एक क्यूट सी कॉलेज गोइंग गर्ल ही लगती हैं. लेकिन जेनेलिया को परहेज़ है लिप लॉक से, क्योंकि वह कहती हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि आपकी हर फिल्म में कोई हॉट सा लिप लॉक हो. मुझे लगता है कि किस सीन सिर्फ़ आकर्षण के लिए ही होता है. इसके अलावा किस सीन में कुछ नहीं होता. इसके साथ ही वह कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में आइटम नंबर में डांस करना बहुत ज़रूरी है. अगर मुझे अपनी फिल्म के लिए ज़रूरी लगा तो मैं आइटम डांस कर सकती हूं.

बॉलीवुड में मेरी फिल्में कम आती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हिंदी फिल्में नहीं करना चाहती. मैं साउथ की फिल्में भी करना चाहती हूं. मेरे लिए भाषा नहीं, बल्कि फिल्म में मेरा रोल बहुत ज़रूरी है. मैं आज पांच अलग-अलग भाषाओं की फिल्में कर रही हूं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कम लोग ही करते हैं. जेनेलिया का सपना हॉलीवुड पहुंचने का है. वह कहती हैं कि मौक़ा मिलेगा तो वह हॉलीवुड में भी ट्राई कर सकती हैं. हालांकि वह इंडिया में ही कई भाषाओं की फिल्में करके काफ़ी ख़ुश हैं.

अभय ने अलग पहचान बनाई

अभय देओल भले ही देओल ख़ानदान से आते हैं, लेकिन उनकी पहचान चाचा धर्मेंद्र और उनके बेटों सनी और बॉबी से बिल्कुल अलग है. वह कहते हैं कि वह संयुक्त परिवार में पले-बढ़े हैं. परिवार में सात बच्चे थे. मैं भाई बॉबी के अधिक क़रीब रहा. बॉबी के बिना बचपन में मैं कुछ नहीं करता था. हम दोनों एक जान दो शरीर थे. मैं परिवार का सबसे शरारती बच्चा माना जाता था और सनी भैया से बहुत डरता था. उन्होंने दूसरे बच्चों की ही तरह पढ़ाई के लिए ख़ूब डांट खाई है, क्योंकि वह पढ़ने में औसत थे. उनका पसंदीदा विषय अंग्रेज़ी था. वह कहते हैं कि मम्मी-पापा चाहते थे कि मैं अपनी कक्षा का सबसे तेज़ छात्र बनूं. पढ़ाई के लिए मुझे मम्मी-पापा और टीचर से ख़ूब डांट पड़ती थी. मन खेलने में अधिक लगता था. अपने मन की बातें मम्मी से कहता था. मुझे कुछ चाहिए होता था या कोई शिकायत करनी होती थी तो मैं मम्मी से रात में सबके सोने के बाद कहता था. उन्होंने मुझे सही और ग़लत के बीच फ़र्क़ समझाया. वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं. उनकी परवरिश की ही देन है, जो मैं आज सही रास्ते पर चल रहा हूं. उन्हें नन्ही उम्र में बिग स्क्रीन से प्यार हुआ था. वह मानते हैं कि यह उनके परिवार के माहौल का असर था. धर्मेंद्र और सनी भैया की फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं. उन्हीं की तरह मैं ख़ुद को बड़े पर्दे पर देखना चाहता था. उनकी फिल्में अच्छी लगती थीं, लेकिन कभी उनके जैसा काम करने की इच्छा नहीं हुई. यही वजह है कि आज मैं अलग तरह की फिल्में कर रहा हूं. वह कहते हैं कि मैं बचपन में सोचता था कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं, ताकि मुझ पर किसी की बंदिश न रहे और मैं अपने मन का हर काम कर सकूं, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि जल्दी बड़ा नहीं होना चाहिए था. मैं बच्चों से कहूंगा कि वह मेरी तरह जल्दी बड़े होने की कोशिश न करें. अपने मम्मी-पापा की बातें सुनें, दिल से पढ़ाई करें और ख़ूब सपने देखें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 30 जनवरी-05 फरवरी 2012

www.chauthiduniya.com

मंत्रियों की लापरवाही से विकास कार्य ठप

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

हमारे मंत्री-संतरी कई बार सीना तान कर दावा करते हैं कि महाराष्ट्र विकास में सबसे आगे हैं. उनके कपोल-कल्पित दावों की हवा सरकारी आंकड़े ही निकाल देते हैं. अब सवाल यह उठता है कि बजट में आवंटित रक़म जब समय पर ख़र्च नहीं की जाती है और मंत्री हमेशा निधि के अभाव का रोना रोते रहते हैं तो बची हुई करोड़ों की निधि जाती कहां है?

प्रवीण महाजन

राज्य के अधिकतर मंत्री अपने विभाग को पर्याप्त निधि का आवंटन बजट में न किए जाने का रोना रोते रहते हैं. निधि के अभाव में विकास कार्य न हो पाने का बहाना बनाते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां करती है. वास्तविक तस्वीर यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों में विकास कार्यों को समय पर पूरा करके प्रगति के पथ पर महाराष्ट्र को ले जाने के लिए न तो नियोजन है और न ही इच्छाशक्ति . उनमें राज्य में रचनात्मक विकास करने की दृष्टि का अभाव है. यही कारण है कि विविध विभागों के लिए वर्ष 2011-12 के लिए आवंटित निधि का मंत्रियों द्वारा विकास कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है. इसके बाद भी हमारे मंत्री-संतरी कई बार सीना तान कर दावा करते है कि महाराष्ट्र विकास में सबसे आगे हैं. उनके कपोल-कल्पित दावों की हवा सरकारी आंकड़े ही निकाल देते हैं. अब सवाल यह उठता है कि बजट में आवंटित रक़म जब समय पर ख़र्च नहीं की जाती है और मंत्री हमेशा निधि के अभाव का रोना रोते रहते हैं तो बची हुई करोड़ों की निधि जाती कहां है? हाल ही में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में किसानों को राहत प्रदान करने के नाम पर 2000 करोड़ का पैकेज घोषित करने के दरम्यान मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री ने पैकेज पर अमल करने के लिए विकास कार्यों की निधियों में कटौती करने की बात कही थी, जबकि वर्ष 2011-12 के 48,983 करोड़ के कुल बजट में से सरकार ने 23333.033 करोड़ रुपये ख़र्च ही नहीं किया है. होना तो यह चाहिए था कि जनवरी 2012 तक बजट की 80 प्रतिशत राशि विकास कार्यों पर ख़र्च हो जाती, लेकिन मंत्रियों की उदासीनता से राज्य के कई विकास कार्य अधर में अटके पड़े हैं और अब महानगर पालिका और ज़िला परिषद चुनाव के मद्देनज़र चुनावी आचार संहिता लागू है. इसका मतलब है कि वर्ष 2011-12 के बजट की करीब आधी रक़म बाकी बचे 40 दिन में ख़र्च करने का उपक्रम करेगी जो असंभव ही लगता है. दरअसल राज्य में मनपा व ज़िला परिषद चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है. मुद्दा यह है कि साल भर सरकार क्या करती रही? जब पहले से आवंटित रक़म विकास कार्यों में विविध मंत्रालय नहीं कर पाते हैं तो राज्य के मंत्री हमेशा विकास के लिए निधि के अभाव का रोना क्यों रोते रहते हैं? इससे तो यही पता चलता है कि उन्हें जो मंत्रालय दिया गया है उसके तहत आने वाले विकास कार्यों को सही व समयबद्ध तरीके से चलाने में वे सक्षम नहीं हैं. वे अपने मातहत कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान नहीं कर पा रहे है. यदि यह कारण नहीं है तो वे बेहद ही आलसी हैं और उनमें राज्य के विकास कार्यों को गति देने की दिलचस्पी नहीं है. सारे मंत्रालयों की आर्थिक तस्वीर तो उनके इसी चरित्र को उजागर करती है. इनमें कोई एक मंत्री शामिल नहीं है, सभी के एक जैसे ही हाल हैं. उनकी सक्रियता राजनीतिक उठापटक में अधिक दिखती है पर विकास कार्यों के मामले वे आलसी ही साबित होते हैं. इनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

विकास निधि का उपयोग समयबद्ध न करने में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सबसे आगे नज़र आते हैं. मुख्यमंत्री के अधीन नगर विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2011-12 के बजट में 3728.990 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे पर जनवरी 2012 तक उनमें से मात्र 521.552 करोड़ रुपये ही ख़र्च किया गया है. होना यह चाहिए था कि बजट में आवंटित राशि का 80 प्रतिशत यानि 2706 करोड़ रुपये ख़र्च हो जाना चाहिए था. इसका तो यही अर्थ निकलता है कि बाकी बचे 3197.438 करोड़ रुपये को बचे 40 दिन (19 फरवरी से 31 मार्च तक) में ख़र्च किए जाएंगे. इसी तरह गृहनिर्माण विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन है जिसके लिए बजट में प्रस्तावित राशि 1750.156 करोड़ रुपये है पर उसमें से मात्र 228.644 करोड़ रुपये ही ख़र्च हुए हैं. मुख्यमंत्री के पास ही मराठी भाषा विकास विभाग भी है. वे मराठी के विकास-विस्तार के प्रति कितने प्रयासरत हैं यह इस बात से पता चलता है कि मराठी भाषा के कल्याण के लिए आवंटित 1.5 करोड़ में से सिर्फ 48 लाख रुपये ही ख़र्च हुए हैं. बाकी कब ख़र्च किए जाएंगे भगवान ही जाने. अब जब राज्य सरकार के मुखिया में नियोजन का पूरी तरह अभाव है तो अन्य विभागों की बात कौन कहे.

राज्य के मंत्रिमंडल के सबसे सक्रिय सदस्यों में गिने जाने वाले उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और नारायण राणे के विभागों का भी यही हाल है. अजीत पवार के पास जहां ऊर्जा विभाग है, वहीं नारायण राणे के पास उद्योग मंत्रालय है. इन दोनों विभागों के लिए बजट में 2240.882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन जनवरी 2012 तक मात्र 484.495 करोड़ रुपये ही ख़र्च किए जा सके हैं. निधि के अभाव का सबसे अधिक रोना रोने वाले छगन भुजबल के सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के लिए चालू वर्ष के बजट में 3978.948 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था पर उनमें से अब तक मात्र 1722.036 करोड़ रुपये ही विकास कार्यों पर व्यय किए जा सके हैं. उनके विभाग के खाते में अभी 2256.912 करोड़ की निधि इस इंतज़ार में पड़ी है कि उसका उपयोग कब जनहित में किया जाएगा. हालांकि इसके बाद भी भुजबल साहब का निधि के लिए रोना कहां तक उचित है. गृह मंत्री आर.आर. पाटिल भी अक्सर राज्य की पुलिस के आधुनिकीकरण के सवाल पर निधि उपलब्ध न होने की बात कह कर अपना बचाव करते देखे जाते हैं, जबकि बजट में उनके मंत्रालय के लिए आवंटित 659.611 करोड़ की निधि को ही वे अब तक पूरी तरह ख़र्च नहीं कर पाये हैं. उन्होंने अपने विभाग के लिए आवंटित निधि में से मात्र 334.700 करोड़ ही उपयोग ला सके हैं बाकी की 322.672 करोड़ रुपये अभी भी उनके एकाउंट में पड़े हुए हैं. ऐसा लगता है कि उक्त मंत्री पूरी निधि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर ख़र्च करना ही नहीं चाहते हैं.

आदिवासियों व अल्पसंख्यकों को चुनाव में अपने प्रति रिझाने का प्रयास राज्य के सत्तारूढ़ व विपक्षी दल के सभी नेता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके वोट की दरकार है. उनके उद्धार-कल्याण के प्रति राज्य सरकार कितनी तत्पर व प्रयासरत है इसका खुलासा करते हैं सरकारी आंकड़े. वर्ष 2011-12 के बजट में आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी विकास मंत्रालय के नाम पर 3952.979 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसमें से अब तक 1638.080 करोड़ ही ख़र्च किया गया है. इसी तरह अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर चिंतित सरकार के बजट में अल्पसंख्यक विभाग को मिले थे 263.280 करोड़ रुपये पर अब तक व्यय किए जा सके मात्र 87.465 करोड़ रुपये. आखिर सरकार इतनी राशि बचा कर करती क्या है? जिस कार्य के लिए बजट में जितनी राशि का प्रावधान किया गया है उसका उपयोग करने में उसे क्या परेशानी होती है? राज्य में सामाजिक असामनता एक बड़ी समस्या है. इसके लिए हर साल राज्य के बजट में अच्छी खासी रक़म का आवंटन किया जाता है. उसके बाद भी समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जाती है. इसका कारण इससे पता चलता है कि चालू साल के बजट में सामाजिक न्याय विभाग को दिए गए थे 4312.903 करोड़ रुपये की राशि पर अब तक मात्र 1965.985 करोड़ रुपये ही उपयोग किए गए हैं. उसके खाते में अब भी 2346.918 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं. उनका उपयोग कब होगा यह तो मंत्री ही जाने पर उनके पास इतनी बड़ी रक़म से विविध वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ 40 दिन का समय बचा है. इतने कम समय में हमारी राज्य सरकार के नुमाइंदे कितना गुल खिला सकेंगे. संभवतः उक्त निधि में से कुछ प्रशासनिक कार्यों में ख़र्च हो जाए, लेकिन मार्च अंत तक विविध मंत्रालयों में बची रक़म का ख़र्च हो पाना असंभव ही लगता है. इस बात का समर्थन वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी करते हैं. यदि सरकार बची हुई रक़म का उपयोग चालू वर्ष के शेष 40 दिनों में करने के लिए युद्ध स्तर पर विकास कार्य करने का उपक्रम करती है तो सोचिए कि वह कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से कैसा होगा? सरकार ने समयबद्ध नियोजन का कलेंडर विकासकार्यों के लिए प्रारंभ में ही बना लिया होता तो आज यह स्थिति न पैदा होती, न नामुमकिन होता. जैसे विदर्भ में नहरों के निर्माण के लिए पिछले कुछ साल करोड़ों रुपये आए जिससे काम भी किए गए, लेकिन निर्माण हुए कार्य की हालत खस्ता है. इसके पीछे का कारण यही है कि सिर्फ आया हुआ पैसा ख़र्चा करना ही मक़सद रहा है. गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया. कुछ वैसा ही हाल 40 दिन में किए जाने वाले विकास कार्यों का हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी. इसलिए नियोजनहीन निष्क्रिय सरकार आज सवालों के घेरे में खड़ी नज़र आ रही है.

feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2011-12 के बजट में विविध विभागों को आवंटित निधि व ख़र्च (करोड़ों में)

विभाग	आवंटित राशि	ख़र्च राशि	बची हुई राशि
नगर विकास	3728.990	521.552	3197.438
गह निर्माण	1750.156	228.644	1521.512
गृह	657.372	334.700	322.672
महसूल व वन	659.611	64.459	595.16
स्कूल शिक्षा	2422.701	936.745	1485.956
सार्वजनिक निर्माण कार्य	3978.948	1722.036	2256.912
जलसंपदा	7613.094	4183.523	3429.571
उद्योग व ऊर्जा	2240.882	484.495	1756.387
ग्रामविकास	1667.025	674.498	992.527
अन्न व नागरी आपूर्ति	55.660	9.556	46.104
सार्वजनिक स्वास्थ्य	983.014	681.182	301.832
चिकित्सकीय शिक्षा	86.310	18.325	67.985
तकनीकी शिक्षा	253.313	93.608	159.705
आदिवासी विकास	3952.179	1638.080	2314.099
सामाजिक न्याय	4312.903	1965.985	2346.918
महिला व बालविकास	1908.031	1068.315	839.716
जलापूर्ति	590.884	225.613	365.271
अल्पसंख्यक विकास	263.280	87.465	175.815
मराठी भाषा	1.5	00.48	1.02
पर्यटन	297.918	92.771	205.147
सहकार	408.885	104.456	304.429
पशुसंवर्धन दुग्धविकास	1338.250	691.393	646.857

खून की कमी होने से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उसमें भी खास कर किशोरवयीन युवतियों को. डॉ. मिलिंद माने ने बताया कि लड़कियों को मासिक धर्म के समय कमजोरी रहती है.

अगर ऑन ड्यूटी होमगार्ड की मौत हो जाए तो तीन लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं उसके परिजनों को. क्या इन जवानों की सेवा का यही मोल है?

महाराष्ट्र हलचल

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से दादर में आयोजित केंद्र व राज्य योजना सनियंत्रण समिति के जनसेवकों की बैठक में सूचना पुस्तक का विमोचन करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, समिति के अध्यक्ष विनायक देशमुख और स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी.

कोथरूड में आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय पुणे फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता अमिताभ बच्चन का सत्कार किया गया. इस मौके पर गायिका आशा भोंसले, अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्री संजय देवतले, अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू व अध्यक्ष जब्बार पटेल भी मौजूद रहे.

मकर संक्रांति के मौके पर ईशान्य मुंबई ज़िले के कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को शुभकामनाएं देते पूर्व ज़िलाध्यक्ष वेल्लुस्वामी नायडू, विधायक अलका देसाई, बालासाहब थोरात और जयप्रकाश सिंह.

जिप चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु ज़िला निहाय बैठक में राकांपा प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़, मंत्री छगन भुजबल, गृहमंत्री आर.आर. पाटिल, पूर्व मंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल और महिला प्रदेशाध्यक्ष विद्या चव्हाण.

अकोला में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी व व्याख्यानमाला को संबोधित करते प्रो. रवींद्र भास्कर व उपस्थित श्रोतागण.

अमरावती के जोग क्रीड़ांगण में ग्रामीण पुलिस जवान आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास करते हुए.

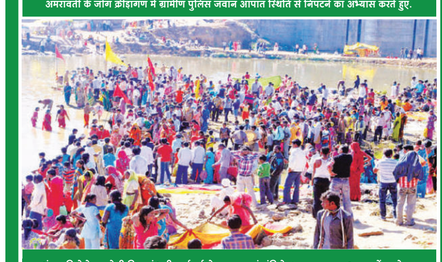

भंडारा ज़िले के साकोली स्थित कुंभली दुर्गाबाई डोह पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगा श्रद्धालुओं का मेला.

आश्रमशाला दस लाख में बेच दी

राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज ने वर्ष 1958 में सबसे पहले आश्रमशाला का महत्व समझा और उसकी स्थापना गढ़चिरोली ज़िले की अहेरी तहसील के कमलापुर में की थी. उस समय आदिवासी आश्रमशाला के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं थी. उसी आश्रमशाला को 10 लाख में बेच दिया गया है. आश्रमशाला को संचालित करने वाली अमरावती ज़िले की गुरुदेव सेवा मंडल गुरुकुंज मोझरी ने वर्ष 2003 को पूर्व राज्यमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम को यह आश्रमशाला बेच दी थी. हालांकि चैरिटी कमिश्नर ने अपने पत्र में कहा है कि सरकारी नियम के तहत किसी भी आश्रमशाला को इस तरह से बेचा नहीं जा सकता. इसके बावजूद यह पूरा मामला हुआ और अब तक किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई.

नागपुर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर गढ़चिरोली ज़िले की अहेरी तहसील के कमलापुर में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज ने वर्ष 1958 में आदिवासी बच्चों के लिए आश्रमशाला शुरू की थी. ग़ौरतलब है कि आदिवासी बच्चों के विकास के लिए उस समय राज्य या केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं थी. राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज ने पहले ही आश्रमशाला के महत्व को समझ लिया था. इस आश्रमशाला का संचालन अमरावती ज़िले के गुरुकुंज मोझरी गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से किया जाता था, लेकिन अमरावती से गढ़चिरोली दूर होने और व्यवस्थापन में कठिनाई होने का कारण बताकर वर्ष 2003 में मंडल ने आश्रमशाला को पूर्व राज्यमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम को बेच दिया. बताया जाता है कि यह सौदा 10 लाख में हुआ. हैरत की बात यह है कि चैरिटी कमिश्नर के अनुसार नियम से आश्रमशाला नहीं बेची जा सकती और जिस समय आश्रमशाला को बेचा गया उस समय आत्राम खुद राकांपा कोटे से राज्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया. 8 दिसंबर 2005 में तुकारामदादा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्य विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मोर्चा निकाला था. उस समय के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटिल ने स्वयं मोर्चा स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था. तुकारामदादा ने मांग की थी कि आश्रमशाला की बिक्री प्रक्रिया को रद्द कर इसे पुनः मंडल को सौंपा जाए. उन्होंने दोषियों पर भी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटिल ने 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक अपना आश्वासन पूरा नहीं किया. आरोप है कि आत्राम राकांपा के नेता होने से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को जानबूझकर रोका जा रहा है. कहा जाता है कि तुकारामदादा की मृत्यु के बाद सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध ली है.

कैसे शुरू हुई फ़र्ज़ी आश्रमशालाएं

आदिवासी विकास मंत्रालय के तत्कालीन मुख्य सचिव उत्तम खोब्रागड़े ने कहा था कि राज्य में पूरी आश्रमशालाएं बोगस हैं. ये आश्रमशालाएं भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई हैं. उनके इस बयान के बाद राज्य सरकार ने कुल 553 आदिवासी आश्रमशालाओं की जांच की थी, जिसमें 279 बोगस पाई गई थीं. इसके बाद भी केवल 61 आदिवासी आश्रमशालाओं के व्यवस्थापकीय मंडल पर ही पुलिस में मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में आदिवासी विकास मंत्रालय ने इन आश्रमशालाओं को शुरू करने की इज़ाज़त दे दी. ग़ौरतलब है कि इस मंत्रालय का जिम्मा बबनराव पाचपुते के पास है. वरिष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे ने कहा कि जब जांच में 279 आदिवासी आश्रमशालाएं बोगस पाई गई थीं, तो राज्य सरकार ने सभी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन 61 आश्रमशालाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई उसे भी वापस क्यों ले लिया गया? उन्होंने इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दाख़िल की है. इस संबंध में उच्च न्यायालय ने आदिवासी विभाग के प्रधान सचिव, मंत्री बबनराव पाचपुते, विभाग के आयुक्त, अपर आयुक्त को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

मंत्री पाचपुते भी चुप

वर्ष 2010 में विधान मंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान आदिवासी कल्याण मंत्री बबनराव पाचपुते ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी. बताया जाता है कि इसमें आश्रमशाला को पुनः मंडल को सौंप कर दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का निर्णय लिया गया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया है. आख़िर क्यों मंत्री पाचपुते इस मामले में चुप है? डॉ. ए.बी. कुंभारे ने बताया कि गुरुदेव भक्त इस आश्रमशाला को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की अस्मिता के रूप में देखते हैं. वे इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि धर्मरावबाबा आत्राम भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटिल द्वारा ली गई बैठक में उन्होंने आश्रमशाला वापस करने की बात कही थी, लेकिन आज तक यह नहीं हुआ है. इससे गुरुदेव भक्तों में खासी नाराज़गी है. उन्होंने जल्द से जल्द इस संबंध में कार्यवाही पूरी करने की मांग की है.

सेवा नहीं स्वार्थ हो रहा पूरा

राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज ने जिस सेवाभाव से कमलापुर आश्रमशाला की शुरूआत की थी, आज वहां स्वार्थ पूरा किया जा रहा है. यह मामला तब उजागर हुआ, जब वरिष्ठ समाजसेवी उमेश चौबे ने वहां का दौरा किया. उस समय वहां जो अव्यवस्था पाई गई, उससे साफ होता है कि इस आश्रमशाला को महज रुपये ऐंठने की मशीन बना लिया गया. वरिष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे ने बताया कि उन्हें जब इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि आदिवासी युवकों ने आखिर बंदूक क्यों थामी, लेकिन कमलापुर आश्रमशाला का दौरा कर उन्हें इसका जवाब मिल गया. उन्होंने बताया कि इस आश्रमशाला का व्यवस्थापन 350 बच्चों पर सरकारी अनुदान हासिल करता है, लेकिन जब वे और अन्य समाजसेवी वहां पहुंचे तो आश्रमशाला में केवल 45 बच्चे उपस्थित थे. उनकी जिम्मेदारी एक बुजुर्ग महिला के जिम्मे दी गई है, जिसे व्यवस्थापन की ओर से केवल 350 रुपये महीना वेतन दिया जाता है. बच्चों के खाने की व्यवस्था के लिए नियम के अनुसार यहां 6 रसोइए हैं, जिन्हें 15-15 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है, लेकिन जब पूरी जांच की गई, तो पाया गया कि यहां केवल दो लोग खुले आसमान के नीचे चूल्हे पर बच्चों के लिए खाना बनाते हैं. बच्चों को रोज दाल-चावल के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता. खुले आसमान में ही बच्चे खाना खाते हैं. यहीं नहीं जिस कक्षा में उन्हें पढ़ाया जाता है, वहीं उनके सोने की व्यवस्था की गई है. इतनी ठंड में उन्हें ज़मीन पर ही सोना पड़ता है. जिस अधिकारी को यहां निरीक्षण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उसे यह सब नहीं दिखता? एक पूर्व राज्यमंत्री जिस आश्रमशाला की देख-रेख करता है, उसमें इतनी अनियमितता है, तो बाकी आश्रमशालाओं का क्या हाल होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

होमगार्ड के जवान उपेक्षा के शिकार हैं

अंजता भौमिक

होमगार्ड अस्तित्व में तब आया जब आज़ादी के वक्त दंगे बढ़ने लगे. इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई. होमगार्ड एक्ट 1948 में लागू हुआ. उस समय इसमें देशसेवा की भावना मन में लिए लोग शामिल होते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. मौजूदा समय में होमगार्ड का दामन मज़बूर लोगों ने थाम रखा है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, पांडेचरी आदि राज्यों में होमगार्ड को नियमित मानदेय दिया जाता है. इसका यहां के होमगार्ड गर्व महसूस करते हैं, लेकिन बात महाराष्ट्र राज्य के होमगार्ड जवानों की करें, तो उनकी सबसे ज़्यादा दयनीय हालत है.

महाराष्ट्र में युवा शिक्षित होने के बावजूद नौकरी न मिल पाने के कारण होमगार्ड के ज़रिए अपना भविष्य संवारने के उद्देश्य से देशसेवा का रास्ता स्वीकार करता है. यहां युवा मन में सरकारी नौकरी का अरमान लिये आते हैं, लेकिन शायद ही उनका यह स्वप्न पूरा हो सके और वे इसी तरह देशसेवा करते रहते हैं. सरकार इनसे केवल दो माह काम लेती है, जिसमें 200 रु. प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाती है. वहीं ग्रामीण इलाके में काम करने वाले होमगार्ड को 175 रु. प्रतिदिन दिया जाता है. क्या इन्हें जो मानधन दिया जा रहा है उससे आज के महंगाई के ज़माने में अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाना किसी नेता या अफ़सर के लिए मुमकिन है? सरकार के उपेक्षित रवैये से होमगार्ड के जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. कई ने इस अस्थायी नौकरी के कारण अपना छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर रखा है. जैसे पानठेला, चाय दुकान, नास्ता, भाजीपाला बेचना, पंक्चर बनाना, आटोरिक्शा चलाना, चप्पल-जूते सिलना आदि. उक्त काम कर अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं. वरना दो माह की होमगार्ड की नौकरी से साल भर परिवार का गुजारा करना असंभव है. नागपुर के होमगार्ड अधिकारी एम.एच. अहमद का कहना है कि हम तो लोगों को ये साफ-साफ बोल देते हैं नियमित रहना है तो जो काम दिया जाता है, उसे देशसेवा के भाव से बिना लालच के करना है. तीन साल प्रतिदिन उपस्थित रहने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है. तब कहीं जाकर उन्हें 5 प्रतिशत नौकरी के आरक्षण में भेजा जाता है. ज़रूरत पड़ने पर होमगार्ड जवानों को गढ़चिरोली भी भेजा जाता है. अगर ऑन ड्यूटी होमगार्ड की मौत हो जाए तो तीन लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, उसके परिवार को. क्या इन जवानों की सेवा का यही मोल है?

अन्य राज्य की तरह महाराष्ट्र के होमगार्डों को कब सम्मानजनक अधिकार व सुविधाएं मिलेंगी? यहां महिला होमगार्ड के लिए भी वही नियम लागू है, जो पुरुषों के लिए हैं. उन्हें कोई अलग से सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं जिससे उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. महाराष्ट्र के 36 ज़िलों में महिला व पुरूष मिलाकर 56 हज़ार होमगार्ड हैं. नागपुर ज़िले में 3 हज़ार होमगार्ड होना चाहिए, लेकिन अब तक नौ सौ ही भर्ती हुए है. प्रशासकीय अधिकारी व शासनकर्ता ही होमगार्ड को न्याय दिला सकते हैं. आज भी इनके काम को ग़लत निगाह से देखा जाता है. पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है. होमगार्ड जब अपने अधिकारों के लिए गुहार लगाता है तो उसकी जगह नये जवानों की भर्ती कर ली जाती है. इस प्रकार उनका वर्षों से शोषण किया जा रहा है. ऐसे वे करें तो आख़िर क्या करें ?

वर्ष 2010 में विधानमंडल के शीतसत्र के दौरान गृहमंत्री आर.आर. पाटिल ने पंजाब व आंध्रप्रदेश के होमगार्डों की तर्ज पर राज्य के होमगार्डों को सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि 11 महीने नियमित सेवा, मानधन में दोगुनी वृद्धि, हर महीने की 5 तारीख़ को मानधन देने के साथ साल में 2 यूनिफार्म आदि, सुविधाएं दी जाएंगी. उनकी इस घोषणा से होमगार्डों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन वह आश्वासन मात्र आश्वासन ही साबित हुआ. गृहमंत्री की घोषित सुविधाओं के मिलने की राह राज्य के होमगार्ड अब तक ताक रहा है कि सरकार को कब उनकी दयनीय दशा पर रहम आता है.

पिछले वर्ष 2011 में हुए शीतसत्र में लोकलेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में होमगार्ड की समस्या पर नज़र डालते हुए यह प्रस्ताव रखा कि होमगार्ड को दंगे, मोर्चा, आंदोलन अथवा किसी भी प्रकार की नैसर्गिक आपदा या अचानक हुई दुर्घटना से निपटने के लिए इन्हें संपूर्ण प्रशिक्षण देकर सभी सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें पूरी तरह से जबावदारी दे देना चाहिए. सिर्फ इन होमगार्डो से गणपति उत्सव, दशहरा के समय काम ना लेकर उन्हें अपनी जबावदारी संभालने तथा स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करना चाहिए. इन्हें भी सरकारी नौकरी में लेना चाहिए और इनके नामों पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए. समिति ने उक्त सभी सिफारिश राज्य सरकार से की है. सवाल यह है कि क्या अब सरकार जागेगी? अब देखना यह है कि सरकार लोकलेखा समिति की सिफारिशों को मानकर राज्य के होमगार्डों के साथ न्याय कब तक करती है.

feedback@chauthiduniya.com

चिंताजनक

पचास फ़ीसदी लड़कियां एनीमिया की शिकार

आज राज्य में आबादी का आधा हिस्सा (महिलाएं) बीमार हैं. ये हम नहीं, बल्कि राज्य सरकार ख़ुद कह रही है. इसका ताजा मामला चंद्रपुर शहर में पांचवीं से 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियों के खून की जांच में सामने आया है. यहां 50 फ़ीसदी से अधिक लड़कियों में खून की कमी पाई गई हैं. गढ़चिरोली में यह 72 फ़ीसदी से अधिक है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के जर्नल में प्रकाशित एक लेख में देश की 80 फ़ीसदी महाविद्यालयीन और कामकाजी महिलाओं में खून तथा कैल्शियम की कमी होने का दावा किया गया था. इन दोनों बातों से यह साबित हो जाता है कि राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समस्या में है. इसमें भी महिलाओं की एक बड़ी आबादी उन गांव-देहातों में बसती हैं, जहां सुविधाओं के नाम पर नेताओं द्वारा उद्घाटित बड़े-बड़े नाम फलकों के अलावा कुछ नहीं है. ऐसे में स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. राज्य के नागपुर में हुए विधान मंडल के शीतकालीन अधिवेशन में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार, विधायक डॉ. नामदेव उसेंडी और विधायक निर्मला गावित ने विधानसभा में ध्यानार्षण प्रस्ताव पेश किया जिस पर बहस भी हुई. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नागरी स्वास्थ्य अभियान के प्रजनन व बाल स्वास्थ्य उपक्रम के अंतर्गत चंद्रपुर शहर की 74 स्कूलों में पांचवीं से 12 वीं में पढ़ने वाली व अन्य ऐसी कुल 18 हज़ार 137 लड़कियों के खून की जांच की गई. इनमें से लगभग 9 हज़ार 271 यानी (50 फ़ीसदी) लड़कियों में खून की कमी पाई गई. उनका हिमोग्लोबिन 10 फ़ीसदी से कम था. इसमें भी हिमोग्लोबिन 7 फ़ीसदी से कम पाए जाने वाली लड़कियों की संख्या 193 थीं. गढ़चिरोली ज़िले में 1 लाख 20 हज़ार 241 लड़कियों की खून की जांच की गई. इनमें से 11 हज़ार 183 लड़कियों (9.30 फीसदी) का हिमोग्लोबिन 7 फ़ीसदी से कम था. वहीं 87 हज़ार 199 लड़कियों (72.52 फ़ीसदी) का हिमोग्लोबिन 7 से 10 फ़ीसदी के बीच था. एक स्वस्थ लड़की में हिमोग्लोबिन का प्रतिशत 13 रहता है. राज्य के अन्य ज़िलों में भी यह जांच अभियान शुरू किया जाना है. इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्कूल से कनिष्ठ महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाली लड़कियों में से एक बड़ा हिस्सा बीमार है. हालांकि राज्य सरकार ने उनका उचित उपचार कराने का दावा किया, लेकिन संबंधित विधायकों ने उनके इस दावे को सही नहीं माना.

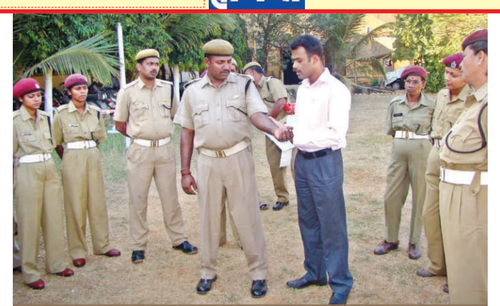

अनियमित खानपान

राज्य सरकार का कहना है कि जिन-जिन क्षेत्रों में खानपान की कमी और मलेरिया जैसी बीमारियां होने की बात सामने आई है, वहां महिलाओं में खून की कमी होने के मामले देखे गए हैं. खून की कमी होने से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उसमें भी ख़ास कर किशोरवयीन युवतियों को. डॉ. मिलिंद माने ने बताया कि लड़कियों को मासिक धर्म के समय कमजोरी रहती है. यदि उनका हिमोग्लोबिन अच्छा है, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि हिमोग्लोबिन कम है, तो वह समय उनके लिए काफी तकलीफदेह होता है. मासिक धर्म के समय कम से कम 200 एमएल खून शरीर से निकल जाता है. यदि इसका समय बढ़ जाए, तो भी शरीर में खून की कमी होती है. डिलेवरी के समय भी कम से कम 1 लीटर खून बह जाता है. पोषक आहार नहीं लेने या साफ-सुथरा भोजन नहीं करने से भी शरीर में खून की कमी होती है. पेट में कृमी होने से वे खून चूसते हैं. शहरों में महिलाओं के लिए अच्छे शौचालय नहीं होने से वे इससे बचने के लिए काफी कम पानी पीती हैं. इससे भी खून की कमी और पथरी जैसे रोग महिलाओं में होते हैं. इसके अलावा खून की कमी होने से लड़कियां स्वयं को चुस्त-दुरुस्त महसूस नहीं करती हैं. उन्हें चक्कर आना, पढ़ाई में मन न लगना, सांस फूलना, कांपना जैसी समस्याएं होती है. साथ ही आत्मविश्वास में भी कमी आती है.

स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं

राज्य में 23 ज़िला अस्पताल, 79 उप ज़िला अस्पताल, 365 ग्रामीण अस्पताल, 1806 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10 हज़ार 580 उपकेंद्र हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर रामभरोसे हैं. ख़ासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों के हाल सबसे ख़राब हैं. ये अस्पताल गांवों-देहातों में रहते हैं. यहां डॉक्टर कम और कम्पाउंडर अधिक इलाज़ करते हैं. राज्य में लगभग 4600 नर्स और डेढ़ हज़ार डॉक्टरों के पद रिक्त हैं. ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा कितनी मजबूत है. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हो जाती है, लेकिन वे नहीं रहते. ऐसे में किसी की बीमारी का योग्य निदान नहीं निकल पाता और उसे उचित उपचार नहीं मिलता.

नहीं होंगे डॉक्टरों के तबादले

विधायकों ने बताया कि चंद्रपुर और गढ़चिरोली जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देते. वे यहां आना नहीं चाहते और जो डॉक्टर यहां आना चाहता है, उन्हें प्रशासन नहीं आने देता. इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके बाद चंद्रपुर, गढ़चिरोली और मेलघाट जैसे क्षेत्रों से तीन वर्षों के पहले डॉक्टरों के तबादले नहीं किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर नक्सलग्रस्त क्षेत्र में नियुक्ति हेतु इच्छुक रहेगा, उसे चयन परीक्षा के दौरान 20 अंक अधिक देने का निर्णय सरकार ने लिया है. साथ ही राज्य में नर्सों के 4600 और डॉक्टरों के 1500 पद जल्दी भरे जाने की भी जानकारी उन्होंने दी. उन्होंने बताया कि चंद्रपुर और गढ़चिरोली के बाद अब राज्य की 62 लाख किशोरवयीन लड़कियों के खून की जांच करने की योजना सरकार ने बनाई है.

व्यापक जनजागृति ज़रूरी

डॉ. मिलिंद माने ने बताया कि महिलाओं की अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामाजिक हैं. जैसे पति के पहले भोजन नहीं करना. यदि इस संबंध में व्यापक तौर पर महिलाओं और विशेष कर पुरुषों में जनजागृति की जाए, तो स्थिति में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही लड़कियों और महिलाओं की नियमित जांच होनी चाहिए. यदि उनमें खून की कमी पाई जाती है, तो उन्हें लौह और कैल्शियम युक्त गोलियां दी जानी चाहिए. गांवों-देहातों में रहने वाली महिलाओं को ये दवाइयां नहीं मिलतीं. ऐसे में सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें ये गोलियां आसानी से उपलब्ध कराए. देखा गया है कि ग़रीबी के कारण महिलाओं को पोषक आहार नहीं मिलता. ऐसे में सरकार जिस तरह स्कूली बच्चों के लिए खिचड़ी की योजना चलाती है, उसी तर्ज पर ग़रीब महिलाओं को भी पोषक आहार मिले, इसके लिए योजना चलाई जानी चाहिए. इसके साथ ही महिलाओं को दूध अधिक पीना चाहिए, बादाम, सूखे मेवे, राजगीर के लड्डू खाने चाहिए.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा हैं...

समाज की दशा और दिशा

क्या समाज में संवेदना शून्यता आ गई है? क्या हम असंवेदनशीलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं? मानव समाज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? जितना आज की युवा पीढ़ी पढ़-लिख कर शिक्षित हो रही है उतनी ही अशिष्टता उनमें समाती जा रही है. सब कुछ दिशाहीन सा दिखाई दे रहा है. मानवीयता का यह क्षरण सामाजिक संकट के रूप में हमारे सामने आ रहा है. राज्य में पिछले सप्ताह तीन ऐसी घटनाएं सामने आयीं जो सामाजिक क्षरण के साथ वैचारिक स्खलन को दर्शाता है. पहली घटना है सातारा ज़िले की, जहां ऊंची जाति के दंभ में एक महिला को निवर्स्त्र कर उसका जुलूस निकाला गया. इसकी वजह यह थी की उसका बेटा किसी ऊंची जाति की लड़की को लेकर भाग गया था. बेटे की करतूत का बदला मां के कपड़े उतार कर लिया गया. अब भला बताइए कि दुशासन और महिला के कपड़े उतारने वालों में क्या अंतर रह गया? दुराचारी तो दुराचारी होता है, भले वह किसी जाति, समुदाय का क्यों न हो. दूसरी घटना घटी हमारे पढ़े-लिखे उन बाबूओं की जो दफ्तर में विराजित होकर शासन से वेतन के रूप में अच्छी-खासी रक़म पाते हैं. उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज हित को ध्यान में रख कर पढ़ने-लिखने के प्रति समाज में जागृति लाने का काम करेंगे, लेकिन नांदेड़ में जब शिक्षा विभाग के कर्मचारी ही बच्चों को वितरित की जाने वाली पुस्तकों का अलाव जलाकर हाथ सेंकने लगें तो राज्य में शिक्षा की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. हमारे सरकारी कार्यालयों में बैठने वाले बाबू-कर्मचारी भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के प्रति कितने संवेदनशील हैं. तीसरी घटना है नागपुर की, यहां एक युवती से जिसको जब अवसर मिला दुष्कर्म करता रहा. उसके कुंठाग्रस्त होने का कारण घर के माहौल को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह कुंठा क्यों उसमें पैदा हुई? आखिर समाज में यह हो क्या रहा है? इन तीनों ही घटनाओं का विश्लेषण करने पर तीन बातें सामने आती हैं- पहला जाति का दंभ, दूसरा सामाजिक दायित्व के प्रति शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की घोर उदासीनता और तीसरे मामले में हमारी युवा पीढ़ी की संवेदनहीनता सामने आती है. यदि हम तीनों को एक वाक्य में व्यक्त करना चाहें तो यही कहा जा सकता है लोगों में तेज़ी से वैचारिक दिवालियापन बढ़ता जा रहा है. इसलिए सब कुछ चलता है कि तर्ज पर हर घटना को पढ़ने के बाद भुला दिया जाता है. इसी के साथ बढ़ता जा रहा है मानवीय गुणों का क्षरण. यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है. ऊंच-नीच की बात को कौन बढ़ावा दे रहा है? इसमें वे ही आगे हैं, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं. जब हमारी नीति अगड़ा-पिछड़ा की होगी, हर बात में जाति को महत्व देने वाली नीति को संवैधानिक चोला पहनाया जाएगा तो ऊंच-नीच की खाई को कैसे भरा जा सकेगा? भ्रष्ट शासन व्यवस्था में उच्च पदों पर बैठे लोग खुद कार्य की गति व दिशा की ओर ध्यान देने की बजाय बाबूओं द्वारा तैयार रिपोर्ट पर आवलंबित रहते हैं तो उसमें सुधार कैसे कर सकेंगे? सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि यह देखा जाए कि जिस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, उस पर कार्य कैसे चल रहा है? जब तक इस पर अमल नहीं किया जाता तो नांदेड़ जैसी नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा?

तीसरी घटना सबसे अधिक परेशान करने वाली है. आज टीवी के जरिये दुनिया के दर्शन कमरे में बैठे हो जाते हैं. उसमे जो परोसा जा रहा है उसकी चकाचौंध में हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है. इसलिए आज के लड़के-लड़कियों का नज़रिया उपभोक्तावादी हो गया है. उपभोग के संसाधनों को हासिल करने के लिए वह अपने माता-पिता व बुजुर्गों की बातों को दकियानुसी मानकर नज़रअंदाज करता है और अंततः मुसीबत को गले लगा लेता है. यह वैचारिक दिवालियापन समाज को कौन-सी दिशा में ले जा रहा है, यह चिंतनीय सवाल है?

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

बुलढाना ज़िले स्थित हिवरा आश्रम में स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं ने संत शुकदास महाराज के दर्शन किए व महाप्रसाद ग्रहण किया.

चंद्रपुर शहर में मकर संक्रांति के अवसर पर दक्षिण भारतीय समाज द्वारा निकाली गई पोंगल रैली में शामिल महिलाएं.

डिस्ट्रिक एमैच्योर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित गढ़चिरोली प्रीमियर लीग का उद्घाटन करते हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट सुरेंद्र कुमार मेहरा. इस मौके पर संघ के पदाधिकारी व खिलाड़ी भी मौजूद रहे.

यवतमाल ज़िले की वणी तहसील में कोलवॉश कंपनी के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए.

नागपुर मनपा के कांग्रेस के नगरसेवक देवेंद्र मेहेर व निर्दलीय नगरसेवक योगेश गोन्नाडे द्वारा भाजपा में प्रवेश करने पर उनका सत्कार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी.

नागपुर मनपा चुनाव की तैयारी के संबंध में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल. उनके साथ हैं मंत्री अनिल देशमुख, पूर्व मंत्री रमेश बंग, विधायक राजेंद्र जैन, गिरीश गांधी, शहर अध्यक्ष अजय पाटिल आदि.

वर्धा ज़िले के अकोली गांव में सामाजिक वनीकरण विभाग के सहयोग से दिनकर विद्या मंदिर व दिनकर विद्यालय के विद्यार्थियों ने वनराई बांध का निर्माण किया.

बगावत करने वालों को वे भी अधिक महत्व देना नहीं चाहते. देशमुख ने बताया कि विदर्भ में कांग्रेस के लिए केवल नागपुर और अकोला ज़िला परिषद टफ जाएगी.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

महाराष्ट्र में नौकरशाह भ्रष्ट हैं

युधिष्ठिर जोशी

आघाड़ी सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों की शिकायत है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते. लाल बत्ती की गाड़ी, मंत्रालय में सभी सुविधाओं से युक्त केबिन, सेवा में लगे कई नौकर, भव्य निवासस्थान, वहां भी कई नौकर-चाकर, कुछ भी झेलने वाले सरकारी सेवक, चमचागिरी करने वालों की फौज़, कदम-कदम पर सलाम करने वाले पुलिस. ऐसा रुतबा रखने वाला मंत्री जब कभी निजी चर्चा या फिर पार्टी की बैठक में खुले रूप से शिकायत करता है कि सरकारी बाबू उनकी नहीं सुनते. उन्हें कोई काम बताया जाए तो वे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं. एक ही काम के लिए सरकारी बाबू को कई बार बताना पड़ता है. यह कई मंत्रियों की शिकायत है जो सही भी है.

इस तरह की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं. इसके अलावा एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. हांगकांग की एक कंसल्टंसी फर्म ने हाल ही में एशिया के देशों की नौकरशाही की जांच कर एक निष्कर्ष निकाला है कि भारत की नौकरशाही सबसे खराब है. भारत, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर देशों की नौकरशाही का तुलनात्मक अध्ययन किया गया. उसमें भारत की नौकरशाही को सबसे खराब 9.21 अंक मिले. सिंगापुर की नौकरशाही को 2.25 अंक यानी सबसे कम अंक मिले. चीन को 7.11, जापान को 5.77 अंक दिए गए. निजी कंपनियों को अलग-अलग देशों में उद्योग शुरू करने के लिए सरकारी नौकरशाही के पास जाना पड़ता है. उस दौरान आए अनुभवों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया हैं. इसके अलावा रिपोर्ट में भारतीय नौकरशाही पर ढांचागत सुविधा मुहैया नहीं कराने, भ्रष्टाचार, टेबल के नीचे से अवैध रूप से पैसे स्वीकार करने आदि कई आरोप लगाए गए हैं.

नौकरशाही कैसी मुंहजोर और क़ानून को अपने जेब में रखकर काम करती है यह मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी प्रकरण से देखने को मिलता है. आदर्श हाउसिंग प्रकरण में राज्य की नौकरशाही ने सेना की ज़मीन हथियाकर कारगिल शहीदों के रिश्तेदारों के नाम पर जो गंदा खेल खेला है, वह सभी के सामने है. जांच आयोग के सामने इससे जुड़े नए-नए तथ्य रोज़ सामने आ रहे हैं. आदर्श प्रकरण हाल ही की बात है, लेकिन इससे पहले भी कई जमीन घोटाले राज्य की नौकरशाही ने किए हैं. उन प्रकरणों में न्यायालय के निर्णय के कारण नौकरशाही को सफलता नहीं मिली. पूर्व शिक्षा मंत्री मधुकरराव चौधरी की बालकल्याणी नाम की शिक्षण संस्था है. 1980 के दशक में वे सत्ता में क्या साधारण विधायक भी नहीं थे, उस समय राजस्व विभाग के सचिव ने अंगारिका को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्थापित की. उसमें आई.ए.एस. अधिकारी सदस्य थे. बालकल्याणी संस्था को राज्य सरकार ने मलबारहिल परिसर का सरकारी प्लॉट बंगले के साथ दिया था. उसे ही हथियाने का दाव अंगारिका की ओर से सत्तापक्ष के एक मंत्री की मदद से खेला जा रहा था. इस संबंध में जानकारी मिलते ही मधुकरराव चौधरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार सहित संबंधित सभी मंत्रियों के पास शिकायत की, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. थक-हारकर वे न्यायालय में गए. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया. न्यायालय ने अंगारिका हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों को आड़े हाथों लिया और राज्य सरकार पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोंका. उस जुर्माने की भारपाई भाजपा-शिवसेना सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने की थी. कुछ दिनों पहले तक शिकायत की जाती थी कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात जा रहे हैं. उद्योग क्षेत्र में गुजराती व्यक्ति होने, गुजरात राज्य मुंबई से लगकर होने से महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में जाने की बात कही जा रही थी. अब तो पश्चिम और दक्षिण महाराष्ट्र के उद्योग कर्नाटक में जा रहे हैं. यह एकदम नई और तकलीफदेह जानकारी है. कोल्हापुर के पास स्थित इचलकरंजी वस्त्रोद्योग में आगे है. इसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर भी कहा जाता है. बताया जाता है कि यहां के कई उद्योग कर्नाटक में स्थानांतरित हो गए हैं. इसके पीछे कारण यह है कि कर्नाटक सरकार ढांचागत सुविधा के साथ-साथ कई प्रकार की अन्य सुविधाएं उद्योगों को दे रही है.

गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार है. उन्होंने देशी-विदेशी सभी उद्योग घरानों को बड़े पैमाने में सुविधाएं दी हैं. टाटा की नैनो कार का कारखाना गुजरात में. फोर्ड कंपनी जैसी अंतरराष्ट्रीय उद्योग समूह ने छोटी कारों के निर्माण का कारखाना महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में शुरू करने का निर्णय लिया है. चीन के कई उद्योग गुजरात में शुरू हो रहे हैं. चीनी उद्योगपतियों की सुविधा के लिए गुजरात के कामगारों को चीनी भाषा में आनी चाहिए इसलिए गुजरात सरकार स्कूल-स्कूल में चीनी भाषा सिखाने की तैयारी कर रही है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हाल ही में एक मुलाकात में बताया कि एक औद्योगिक घराना मंत्रालय में आया. उनकी योजना राज्य में एक बड़ा उद्योग शुरू करने की थी. उस उद्योगपति ने वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात की. शुरुआत से ही उस अधिकारी ने नहीं का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया. तंग आकर उस उद्योगपति ने महाराष्ट्र को छोड़ तमिलनाडु का रास्ता पकड़ा. उसका कारखाना वहां शुरू हो गया है.

महाराष्ट्र की नौकरशाही केवल धूर्त, स्वार्थी ही नहीं, बल्कि आलसी भी है. उनका पेट भर गया, भव्य आलीशान फ्लैट मिल गया, ऊपरी कमाई के करोड़ों रुपये मिल गए. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी प्रकरण को प्रमोट किसने किया? गिडवानी नाम के व्यापारी नेता ने. फ्लैट्स किसे मिले विधायक, मंत्री, विरोधी पक्ष के नेता, उनके रिश्तेदारों को, अधिकारियों के बच्चों को. आखिर इन्हीं लोगों को फ्लैट्स कैसे मिल जाते हैं? देखा जाए तो इसमें कुछ नया नहीं है. सब कुछ एक-दूसरे की साठगांठ से चल रहा है. बड़े अधिकारियों के पेट इस तरह से भरे हुए हैं कि वे मंत्रियों की भी नहीं सुनते. देश की नौकरशाही भ्रष्ट होने की बात विश्व की कंपनियों द्वारा किए सर्वेक्षण में सिद्ध हुई, फिर उसमें महाराष्ट्र कैसे पीछे रहे. राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई आंकड़े से दोषी अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा ही बचाने की बात सामने आई है. एक प्रकरण 23 वर्ष पुराना है. क्लास 2 के एक अधिकारी को 1988 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. नियम के अनुसार उक्त अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई. 28 वर्ष होने के बाद भी सरकार ने अभी तक विभाग को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है. डॉ. विजय कुमार गावित, ज़िलाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, अशोक लाल, करुण श्रीवास्तव, वैजनाथ लटके, डॉ. लक्ष्मीकांत कलंत्री, विधायक रामप्रसाद बोर्डीकर, इकबाल तड़वी ऐसे बड़े ओहदे पर रहने वाले 228 प्रकरणों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है. ऐसे में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग क्या करे? वह नियम के अनुसार हर वर्ष सरकार के पास स्मरणपत्र भेज रहा है. सरकार के कार्यालय में पत्रों के गट्ठे जमा हो रहे हैं. राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने की भाषा मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री और विजय कुमार गावित भी कहते हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य है. शरद पवार की पार्टी में गावित हैं. पवार भी चुप हैं. यदि गावित के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुमति दे दी तो आदिवासियों के वोट चले जाएंगे, यह डर उन्हें है. वोट के लिए गावित जैसे लोग सरकार में भ्रष्टाचार करते रहे तो फर्क नहीं पड़ता. ऐसे में नौकरशाही को मस्ती नहीं आएगी तो क्या?

feedback@chauthiduniya.com

ज़िला परिषद चुनाव

बस हफ़्ते भर का इंतज़ार

मयूर रंगारी

हर चुनाव में अपनी पार्टी को सबसे स्ट्रांग बताने वाले नेता ज़िला परिषद चुनाव को इस बार टफ बता रहे हैं. बात कांग्रेस की हो या भाजपा की. शिवसेना या राकांपा की. रिपब्लिकन या फिर मनसे, सभी पार्टियों के नेता इन दिनों ज़ोरदार प्रचार अभियान में लगे हैं. सक्षम महिला उम्मीदवारों की कमी को नेता पत्नियों से दूर करने की कोशिश सभी पार्टियों में की गई है. शुरुआत में टिकट बंटवारे के समय सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी ज़रूर थी. कुछ ने बगावत की, लेकिन इसे पीछे छोड़ सभी कत्ल की रात की तैयारी के लिए जुट गए हैं. बस एक सप्ताह और, उसके बाद महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र पर आखिर कौन सी पार्टी राज करेगी यह तय हो जाएगा.

नागपुर ज़िला परिषद की बात करें, तो दिग्गज नेताओं की इस नगरी में किसी नेता के पास समय नहीं है. ज़िला परिषद के चुनाव का समय 7 फरवरी नज़दीक आने से सभी का ध्यान उसी ओर लगा है. पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा ने जिप पर ढाई वर्ष राज किया, लेकिन कांग्रेस के एक वार ने ढाई वर्ष बाद उससे सत्ता छीन ली. अब भाजपा पूर्ण बहुमत चाहती है. ताकि फिर कोई वार न कर सके. उधर, कांग्रेस भी 59 में से 35-40 सीटें जीतने का दावा कर रही है. पिछले चुनाव में कांग्रेस महज 17 सीटें ही जीत पाई थीं, जबकि भाजपा के पास 20 सीटें थीं. हालांकि पिछले दिनों हुए नपा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है. कामठी, खापा, उमरेड आदि क्षेत्रों में अच्छी खासी सीटें हासिल की, लेकिन फिर भी 30 के ऊपर संख्या को बढ़ाना टेढ़ी खीर लगती है. उमरेड में कांग्रेस नेता और राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक ने नपा में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन जिप चुनाव में उन्हें उमरेड से भाजपा के विधायक सुधीर पारवे अच्छी टक्कर दे रहे हैं. भाजपा के लिए भी पूर्ण बहुमत हासिल करना टफ है. खास कर नपा चुनाव में प्रदर्शन की बात करें, तो कहना कठिन है कि वह पूर्ण बहुमत लायक सीटें हासिल कर पाएगी. हालांकि पार्टी ने कलमेश्वर, मोहपा में अच्छा प्रदर्शन किया है. राकांपा की चुनावी प्रचार मुहिम भी तेजी से चल रही है. नपा चुनाव में राकांपा के नेता व मंत्री अनिल देशमुख को उनके गृहक्षेत्र में ही काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेऊ की तर्ज पर वे और रमेश बंग चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं. ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष व राकांपा के नेता नितिन राठी भी केलवद से राकांपा प्रत्याशी के लिए जोर लगा रहे हैं. नपा चुनाव में काटोल से अच्छा प्रदर्शन करने वाले राहुल देशमुख ने ज़िला परिषद चुनाव में अपना स्वतंत्र पैनल खड़ा कर दिया है. इससे राकांपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. शिवसेना ने रामटेक-मौदा में अच्छा प्रदर्शन किया था. वहां से पार्टी के विधायक आशीष जैस्वाल अच्छी स्थिति में है, लेकिन पिछले जिप चुनाव में 4 सीटें हासिल करने वाली शिवसेना इससे आगे बढ़ पाएगी कहना मुश्किल है. सावनेर में अलग समीकरण देखे गए हैं. नपा चुनाव में लोधी समाज के संगमयुग पैनल ने सत्ता हासिल कर सभी को चौका दिया है. यह क्षेत्र कांग्रेस के विधायक सुनील केदार का गढ़ है. पारशिवनी में भी उनकी काफी पकड़ है. जिप चुनाव में क्या संगमयुग पैनल अपना असर दिखा पाएगा, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हैं. कामठी में सुलेखा कुंभारे के बहुजन रिपब्लिकन मंच, भाजपा के विधायक व ज़िलाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और ज़िला परिषद अध्यक्ष व कांग्रेस के नेता सुरेश भोयर में काटे की टक्कर है. नपा चुनाव के नतीज़ों को देखा जाए, तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी मानी जा रही है. सुरेखा कुंभारे की आखिर समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उन्हें नुक़सान होने का अनुमान है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि जिप में फिर किसी न किसी गठबंधन की ही सत्ता आएगी, लेकिन यह गठबंधन किसका-किससे होगा, यह बताना मुश्किल है. सत्ता स्वार्थ के लिए कौन-सी पार्टी किस पार्टी को नज़दीक करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

सत्ता हमारी होगी: जैस्वाल

शिवसेना के रामटेक से विधायक आशीष जैस्वाल ने कहा कि इस बार ज़िला परिषद चुनाव काफी कड़ा है, लेकिन फिर भी भाजपा-शिवसेना की सत्ता में वापसी होगी. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. इससे कहा जा सकता है कि इस बार शिवसेना की सीटें बढ़ेगी. उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे शिवसेना-भाजपा की ताकत कम होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे ही सच्चाई सामने लाएंगे.

गठबंधन की ताक़त बढ़ी: आष्टनकर

कांग्रेस द्वारा भाजपा-शिवसेना युति की ताकत को कम आंके जाने के आरोप को वरिष्ठ नेता आष्टनकर ने सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत कामठी, पारशिवनी, कलमेश्वर, नागपुर ग्रामीण, उमरेड और शिवसेना की ताकत रामटेक, मौदा, हिंगणा आदि क्षेत्रों में बढ़ी है. इस चुनाव में युति की सीटों की संख्या निश्चित बढ़ेगी. भाजपा 24 सीटों के ऊपर और शिवसेना 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी. उन्होंने जिप में पुन: युति की सत्ता आने का भी दावा किया है.

नपा से आगे निकल गए हैं: अनिल देशमुख

राकांपा के नेता और मंत्री अनिल देशमुख हार-जीत को जीवन का एक हिस्सा मानते हैं. उनका मानना है कि पार्टी नपा चुनाव से काफी आगे निकल गई है. उन्होंने कहा कि नपा चुनाव में निश्चित ही पार्टी को थोड़ा नुक़सान हुआ है, लेकिन अब वह पुरानी बात हो गई है. अब हमारा ध्यान पूरी तरह से ज़िला परिषद और मनपा चुनाव पर है और निश्चित ही पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी. ग़ौरतलब है कि राकांपा ने पिछले ज़िला परिषद चुनाव में 12 सीटें हासिल की थीं, जबकि कांग्रेस ने 17. यानी कांग्रेस से राकांपा केवल 5 सीटें पीछे थीं. देशमुख ने दावा किया है कि दोनों चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और वे सत्ता में आएंगे.

कांटे की टक्कर: रणजीत देशमुख

कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता रणजीत देशमुख मानते हैं कि नागपुर ज़िला परिषद में टक्कर कांटे की है, लेकिन वे यह भी कहना नहीं भूलते कि कांग्रेस बहुमत के करीब-करीब ज़रूर पहुंचेगी. उनकी मानें, तो चुनाव के बाद कांग्रेस-राकांपा में गठबंधन हो सकता है. बगावत करने वालों को वे भी अधिक महत्व देना नहीं चाहते. देशमुख ने बताया कि विदर्भ में कांग्रेस के लिए केवल नागपुर और अकोला ज़िला परिषद टफ जाएगी. बाकी स्थानों पर पार्टी की स्थिति अच्छी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विदर्भ के संबंध में नीतियां स्पष्ट नहीं हैं. इसी का नुकसान पार्टी को हो सकता है.

राकांपा होगी सबसे बड़ी पार्टी : राठी

ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष नितिन राठी का दावा है कि ज़िला परिषद चुनाव के नतीजे विरोधी पार्टियों के सभी दावों की पोल खोल देंगे. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में राकांपा की 12 सीटें थीं, इस बार यह 20 से ऊपर पहुंचाने का मकसद है. चुनाव के बाद राकांपा ज़िला परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी. राठी ने कहा कि काटोल, नरखेड़, हिंगणा, नागपुर ग्रामीण, सावनेर, पारशिवनी में राकांपा की ताकत बढ़ी है. उन्होंने ज़िला परिषद में राकांपा की सत्ता होने का भी दावा किया है.

करोड़ों के विकास कार्य किए: सुरेश भोयर

ज़िला परिषद के अध्यक्ष सुरेश भोयर ने कहा कि कांग्रेस-राकांपा ने मिलकर ढाई वर्ष में करोड़ों रुपये के विकास कार्य किए हैं. रास्ते के विकास पर 50 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. जलापूर्ति पर लगभग 350 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. पहली बार पानदान रास्तों को पक्के रास्तों में बदला गया. ग्राम पंचायत भवन बनाए गए. श्मशान भूमि के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं. उन्होंने कहा कि अन्ना के आंदोलन का नुकसान कांग्रेस को नहीं, बल्कि भाजपा को ही होगा. उन्होंने 35 सीटें जीतने का दावा भी किया. उन्होंने कहा कि टक्कर कांटे की है. भोयर ने भाजपा-शिवसेना-रिपब्लिकन पार्टी की महायुति से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने की भी बात कही.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

दिल्ली, 30 जनवरी-05 फरवरी 2012 www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Our on going projects

Sanjeevani Dynasty-I PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC Booty More

Future City (BIT) PLOT-4 LAC, BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom) PLOT-4 LAC, BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria) PLOT-4 LAC, BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC Hazaribagh

नीतीश जी

शिक्षक सूची में फ़र्ज़ीवाड़ा EXCLUSIVE

34540 शिक्षकों की यह सूची फ़र्ज़ी है

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

शिक्षक सूची में फ़र्ज़ीवाड़ा

कहते हैं देर आए, दुरुस्त आए. लेकिन बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया देर से आई, दुरुस्त नहीं आई. सालों का समय लगा. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला सालों तक चला. कई-कई बार सूची तैयार की गई. कहा गया कि अब जो सूची बनी है, वो फाइनल है. इसी आधार पर नियुक्तियां होगी. लेकिन इस सूची की पड़ताल करने पर चौथी दुनिया को जो तथ्य मिले, उससे इस सूची पर कई सवाल खड़े होते हैं. चौथी दुनिया की पड़ताल बताती है कि इस सूची में, जिसमें 34540 शिक्षकों को ज़िला आवंटित किया गया है, भारी गड़बड़ी हैं. अनियमितताएं हैं. फ़र्ज़ीवाड़ा है.

चौथी दुनिया की एक्सक्लुसिव रिपोर्ट :

शशि शेखर

क्रम संख्या-27167. अप्लिकेशन आईडी है ओपी 201006057. नाम-वैद्यनाथ रजक. पिता का नाम-देवनारायण रजक. जन्म तिथि 15/5/1971. पता-मुरलीगंज, गोल बाज़ार, वॉर्ड नंबर 9, पीओ+पीएस मुरलीगंज, मधेपुरा. सत्र है 1989-91 का, एससी कोटे से है और इन्हें मधेपुरा ज़िला अलॉट किया गया है. अब ज़रा इस नाम पर भी ग़ौर करें. क्रम संख्या-27168. अप्लिकेशन आईडी है ओपी 2010104669. इनका भी नाम वैद्यनाथ रजक है. पिता का नाम भी देवनारायण रजक है. इनकी जन्मतिथि भी 15/5/1971 है. इनका भी पता-मुरलीगंज, गोल बाजार, वॉर्ड नंबर 9, पीओ+पीएस मुरलीगंज, मधेपुरा है. सत्र समान है, 1989-91 का. ये भी एससी कोटे से हैं और इन्हें भी मधेपुरा ज़िला अलॉट किया गया है. सिवाए क्रम संख्या और अप्लिकेशन आईडी के सब कुछ समान है. यानी, इन्होंने दो आवेदन जमा किए थे और बिहार सरकार को शायद कुछ विशेष लगा हो, जिसकी वजह से वैद्यनाथ रजक को दो ज़िले में एक साथ नियुक्त करने जा रही है. ये जनाब एक साथ दो स्कूल में बच्चों को पढाएंगे. इसी तरह, बांका के मोरामा क्षेत्र के पिपराडीह गांव के पवन कुमार भी हैं. इनके क्रम संख्या 31260 और 31261 पर गौर करें. सिवाए दो आवेदन संख्या के इन दो नामों में, पते में, पिता के नाम में, सत्र में, जन्मतिथि में, कोटे में और आवंटित ज़िले में कोई अंतर नहीं है. यानी, एक ही पवन कुमार ने दो आवेदन पत्र जमा किए और इन्हें भी बिहार सरकार दो जगह नियुक्त करने जा रही है.

एक और उदाहरण देखते हैं. क्रम संख्या-23693 पर ग़ौर करें. अप्लिकेशन आईडी है ओपी 201000775. नाम-वकील पासवान. पिता का नाम-रामायण पासवान. जन्म तिथि 19/5/1962. गांव रोपी, पोस्ट अकोढा, दिनारा, रोहतास. सत्र है 1986-87 का, एससी कोटे से हैं और इन्हें रोहतास ज़िला अलॉट किया गया है. अब ज़रा इस नाम पर भी गौर करें. क्रम संख्या-25788. अप्लिकेशन आईडी है ओपी 201047481. नाम-वकील पासवान. पिता का नाम-रामायण पासवान. जन्म तिथि 8/5/1962. गांव खापी, पोस्ट अकोघा, दिनारा, रोहतास, इनका भी सत्र 1987 है और एससी कोटे से हैं. और इन्हें भी रोहतास ज़िले में नियुक्त किया जाएगा. सिवाए जन्मतिथि के इस दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है. गांवों के दो नाम रोपी और खापी में से किसी एक के अस्तित्व पर भी संदेह है.

इस तरह के कुछ और नाम भी है जो इस ख़बर के साथ लगाए गए हैं. लेकिन ये नाम सिर्फ़ चावल से भरी हांडी के कुछ दाने भर हैं. चौथी दुनिया ने सिर्फ़ चंद नामों को सामने लाकर इस सूची की विश्वसनियता पर सवाल उठाने की कोशिश की है. सरकार यदि सचमुच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर गंभीर होती तो इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आती. हो सकता है कि सरकार ये दलील दे कि हम जिन शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, उन्हें एक साल के भीतर नियमित किया जाएगा और इस बीच में कोई ग़लत तथ्य सामने आया तो उक्त नियुक्त शिक्षक के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल यहां ये है कि सालों की मेहनत के बाद भी आख़िर इस दोषपूर्ण सूची को बनाने के लिए ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? सवाल सूची बनाने वालों की क़ाबिलियत और नीयत पर भी उठता है. अगर मानवीय भूल की वजह से ये ग़लती हुई हो तब भी सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार 34 हज़ार शिक्षकों की सही लिस्ट तक नहीं बना सकती? क्या उसके पास स्टाफ की कमी है? क्या उसके पास काबिल लोग नहीं हैं? और अगर ये ग़लतियां जानबूझ कर की गई हैं तो सीधे-सीधे सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. कारवाई तो दोनों ही स्थितियों में होनी चाहिए. और अब भी सरकार के पास मौक़ा है कि वो अपनी साख बचा ले. इस सूची को फिर से बनवाए और पूरी ईमानदारी से बनवाए, अपनी निगरानी में बनवाए ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके जो इस फ़र्ज़ीवाड़े की वजह से अन्याय के शिकार हुए हैं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

सूची में फ़र्ज़ीवाड़ा

Sr No.	App Id	Name	father's name	dob	Address	Training Session	Category	Alloted District
4640	OP2010112559	BIBHA KUMARI	BALESHWAR PRASAD BISHUNPURI	05/06/1963	C/O-PASHUPATI NARAYAN PRASAD VILL-SHITAL PUR KAMALPUR PO-BIDUPUR BAZAR (VAISHALI)PIN-844503	1980-1982	UR	VAISHALI
4672	OP201014078	BIBHA KUMARI	SRI BALESHWAR PRASAD BISHNUPURI	05/01/1963	HARISHANDRA NAGAR PO-DHELWA DIST-PATNA	1980-1982	UR	PATNA
4673	OP201040720	RENU KUMARI	RANJIT PD. MEHTA	05/10/1963	C/O-RAN BIJAY KR. SINGH, AT+PO-KHARAGPUR-TARA PUR ROAD,MUNGER,PIN-81121 3	1980-1982	UR	MUNGER

Sr No.	App Id	Name	father's name	dob	Address	Training Session	Category	Alloted District
31260	OP201016841	PAWAN KUMAR	SHAYAM MANDAL	25/01/1980	VILL PIPRADIH PO MORAMA PS RAJOON DIST BANKA	1996-1998	BC-I	BANKA
31261	OP201003997	PAWAN KUMAR	SHYAM MANDAL	25/01/1980	VILL - PIPRADIH PO-MORAMA PS- RAJOUN DIST- BANKA	1996-1998	BC-I	BANKA
31262	OP201023066	KUMARI REENA	SHREE RAJDEV	10/07/1976	VILL-MUSHEHARI PO-MUSHEHARI VIA BHORE DIST- GOPALGANJ BIHAR PIN CODE-841426	1996-1998	BC-I	GOPALGANJ

Sr No.	App Id	Name	father's name	dob	Address	Training Session	Category	Alloted District
27166	OP201023592	MANORMA KUMARI	DIPNATH RAJAK	01/01/1971	VILL-PATKHAULI,P.O-BASO URI,VIA-PIRO,DIST-BHOJP UR,	1989-1991	SC	BHOJPUR
27167	OP201006057	BAIDYANATH RAJAK	SRI DEVNARAYAN RAJAK	15/05/1971	AT MURLIGANJ (GOLBAZAR)WARD NO 09 PO PS MURLIGANJ DIST MADHEPURA (BIHAR) PIN 852122	1989-1991	SC	MADHEPURA
27168	OP2010104669	BAIDYANATH RAJAK	SRI DEV NARAYAN RAJAK	15/05/1971	AT-MURLIGANJ(GOL BAZAR) WARD NO.-09 P.O+P.S-MURLIGANJ DT-MADHEPURA PIN-852122	1989-1991	SC	MADHEPURA

Sr No.	App Id	Name	father's name	dob	Address	Training Session	Category	Alloted District
23693	OP201000775	WAKIL PASWAN	RAMAYAN PASWAN	19/05/1962	WAKIL PASWAN VILL-ROPI PO-ACODHA P.S-DINARA DIST-ROHTAS (BIHAR)	1986-1987	SC	ROHTAS
25788	OP201047481	WAKIL PASWAN	RAMAYAN PASWAN	08/05/1962	KHAPI PO-AKOGHA PS-DINARA DIST ROHTAS/SASARAM	1987	SC	ROHTAS
25789	OP2010083579	SHYAM SUNDER KEWAT	LT. SITARAM KEWAT	05/09/1965	VILL - GHORA KATORA PO.- GIRIAK DIS.- NALANDA BIHAR 803109	1987	BC-I	NALANDA

इस लिस्ट को बनाने में व्यापक रूप से धांधली हुई है. पहले वाली लिस्ट को फ़र्ज़ी करार दिया गया था. उस लिस्ट में से भी कई नाम, इस नई लिस्ट में शामिल हैं. 213 ट्रेनिंग कॉलेज के कई सत्र को फ़र्ज़ी बताया गया था, 68 कॉलेज तो ऐसे थे, जिसके एक सत्र को भी मान्यता नहीं मिली थी. फिर भी उसमें से पास आउट हुए कई उम्मीदवारों को 34540 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में शामिल किया गया है. नाम दोहराव की भी घटनाएं सामने आई हैं. हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटीशन दिया है.

एन के ओझा, *अध्यक्ष, नवनियुक्त शिक्षक संघ.*

कुशवाहा बिरादरी के लोग चाहते हैं कि उनके समाज के लोग सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठें.

यहां के छात्रों को मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करने तथा देसी चिकित्सा को विकसित करने का दंभ भरने वाली सुशासन सरकार की कलई बक्सर में उजागर हो जाती है.

सोच सही हो तो राह बन जाती है: अखिलेश पांडे

अखिलेश पांडे, सीएमडी

झारखंड के एक ऐसे समाज सेवी जिन्होंने कम उम्र में काफी नाम कमाया, जिस काम को पूरा करने का निश्चय किया, उसे पूरा किया और इसी का प्रतिफल है कि इन्हें वर्ष 2004 में राजीव गांधी एकता एवार्ड से नवाजा गया. अखिलेश पांडे ने इस धारणा को और भी मज़बूत कर दिया है. विदेश से इंजीनियरिंग करने के बाद अखिलेश पांडे ने सामाजिक कार्य के साथ रियल इस्टेट में कदम रखा. अपनी सोच और विश्वास की बदौलत हर चुनौतियों का सामना करते हुए त्रिवेणी इन्फ्राटेक को कार्य के स्तर पर इतना सुदृढ़ किया कि वह अपनी बात स्वयं कह रहा है. यह कंपनी सभी को समृद्ध एवं खुशहाल देखना चाहती है. त्रिवेणी इन्फ्राटेक उपभोक्ता के हृदय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसके मूल्य या गुणवत्ता के मामले में उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल किया है. अखिलेश पांडे कहते हैं कि मैंने बचपन से कठिन परिश्रम करना सीखा और यही कारण है कि मैंने अपने सपनों को हर दिन अधिक परिश्रम को शामिल किया है. सच्चाई की राह पर चलने वाले व ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखने वाले अखिलेश पांडे चाहते हैं कि वे लोगों के हर सुख-दुख में साथ रहें और इसी का परिणाम है कि वो हर समय किसी न किसी कार्य में शामिल रहते हैं. इन्हें 2007 में महात्मा गांधी बेस्ट इंटरप्रेनियर का अवार्ड झारखंड के स्पीकर आलमगीर द्वारा दिया गया. अखिलेश पांडे का कहना है कि वह अपने सपनों का मात्र पांच प्रतिशत ही प्राप्त कर पाये हैं और संदेश देना चाहते हैं कि दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों की हर प्रकार से मदद करें. वह बताते हैं कि उनके कर्मचारी भी उनके परिवार के सदस्य हैं और वे चाहते हैं कि वे खुशहाल और संतुष्ट रहें. वर्तमान में अखिलेश जी सीएमडी एवं चेयरमैन डिवाइन ग्रुप ऑफ कम्पनी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जीरादेई पर बस आंसू बहाइए

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गांव जीरादेई और गृह ज़िला सीवान आज भी पिछड़ेपन से अभिशप्त है. आज़ादी के छह दशकों के बाद भी यह ज़िला अपेक्षित विकास का सिर्फ सपना ही संजोए है. [illegible]

[illegible] के लिए आज भी मयस्सर नहीं की गई है. 1990 में बंद की गई जीरादेई में प्रतिदिन आने वाली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की दो बसों की यातायात सेवा आजतक बहाल नहीं की गई है. यद्यपि सीवान-मैरवा मुख्य पथ से निकली जीरादेई जाने वाली पतली पक्की सड़क अनेक जगह टूटी-उजड़ी है. जिस पर जीप, टाटा-407 आदि वाहन चलते हैं. 1953 में लगे बिजली के तार और पुराने खंभों को अभी तक बदला नहीं गया है. [illegible] आन्दोलनों की सख्ती से दमित ही कर दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नवादा: बेलगाम हुई पुलिस

अरुण साथी

मनोज यादव को गत 30 सितम्बर 2011 को हुए संजय वर्मा हत्याकांड के मामले की तफ़्तीश को लेकर नवादा पुलिस हिरासत में लेती है और लगातार चार दिनों तक इसका कोई अता-पता नहीं रहता और फिर एकाएक उसका शव खेतों में फेंका हुआ पाया जाता है. मनोज यादव के परिजन नवादा पुलिस से उसे जेल भेजने या फिर उसको छोड़े जाने की फ़रियाद करते हैं पर नवादा पुलिस इसकी कोई जानकारी नहीं देती है. फिर शव को देख जहां परिजन चीत्कार करते हैं, वहीं आम लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटने लगता है. शव की सूचना मिलने पर दो जवान शव फेंकने के स्थल पर जाते हैं, उन्हें खदेड़ दिया जाता है और फिर एसआई चन्दन कुमार जब वहां जाते हैं तो उसे पकड़ कर उसकी पिटाई की जाती है और साथ ही सर्विस रिवाल्वर छीन लिया जाता है. देखते देखते यह चिंगारी आग का रूप ले लेती है और फिर पुलिस की एक मोटरसाइकिल को जला दिया जाता है. फिर बिना महिला पुलिस की मदद के ही बड़ी संख्या में आई नवादा पुलिस भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटती है. यहां तक कि मृतक युवक की दादी को, जिनके पति रघुनाथ यादव का निधन तेरह दिन पहले ही हुआ था, पुलिस बेरहमी से पीट देती है. वहीं कई अन्य महिलाओं पर पुलिस कहर टूट पड़ता है और अन्ततः पुलिस को तीन चक्र गोलियां भी चलानी पड़ती है.

नवादा की घटना महज़ एक बानगी भर है. और फारबिसगंज से प्रारंभ हुआ यह जनाक्रोश आरा, सिवान, नालान्दा, शेखपुरा, गया सहित बिहार के कई ज़िलों में फैल चुका है, जहां पुलिस को अपनी ही जान बचानी मुश्किल पड़ रही है. यह जनाक्रोश बिहार में व्यापक रूप लेता जा रहा है और इसकी सतही वजह को देख जन प्रदर्शन को ग़ैरज़मानती धारा बना कर इतीश्री कर लिया गया पर यह जनाक्रोश थमने का नाम ही नहीं लेता. इसी जनाक्रोश का सामना सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को सेवा यात्रा के क्रम में शेखपुरा ज़िला मुख्यालय के सर्किट हाउस में ठहरने के क्रम में करना पड़ा. यहां भी गुस्सा पुलिस के रवैए को लेकर था, जिसमें दिनदहाड़े धर्मेंद्र कुमार नामक युवक की हत्या कर दी जाती है और अपराधी भाग निकलता है. इस प्रकरण में भले अपराधी गुडडू मियां आज तक गिरफ्त में नहीं आया है पर मृतक युवक के भाई को प्रदर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

इस जनाक्रोश की ज़मीन पिछले कई सालों से बन रही है, जिसको समझ कर ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है. बिहार के सुशासन की ज़बरदस्त ब्रांडिंग की गई है और किसी सौंदर्य सशाधान से भी अधिक इसका विज्ञापन जब आम लोग देखते हैं तो उनको भी इसका भ्रम होने लगता है और ज़मीन पर जब यह भ्रम टूटता है तो यह दबी हुई चिंगारी जनाक्रोश का रूप लेती है. इसी सुशासनी ब्रांडिंग के तहत नेता और कार्यकर्ताओं की प्रशासनिक पकड़ कम कर दी गई, इससे पैजामा छापों की दलाली तो ख़त्म हो गई पर इसका उलटा यह हुआ कि प्रशासन और पुलिस निरंकुश हो गई. इस प्रयोगधर्मिता में जनसरोकारी नेताओं को भी दलालों के साथ घुन की तरह पीस दिया गया. आम आदमी बेचारा हो गया. अब जब किसी को भी पुलिस पकड़ती है तो आम आदमी इसकी फ़रियाद लेकर किसी नेता के पास नहीं जाना चाहता. जाए भी क्यों जब कोई सुनता नहीं है. इतना ही नहीं आम लोगों की एकमात्र उम्मीद जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से भी लोगों को नाउम्मीदी ही हाथ लगी है. जनता दरबार में एक दर्जन बार जाकर कई सालों से गुहार लगाने वाले एक नहीं कई लोग मिल जाएंगे. और तो और जिन अधिकारियों की शिकायत की जाती है, उन्हीं को इसकी जांच का ज़िम्मा देकर जनता दरबार को हास्यास्पद बना दिया गया है. जनता दरबार में एक दर्जन बार जाने वाली शेखपुरा ज़िले के शेखोपुर सराय निवासी मंजू देवी, जिसके घर का रास्ता दबंगों ने रोक कर उसे घर में कैद कर दिया है, कहती है कि अब वहां जा-जा कर थक चुके हैं सर. इससे कोई फ़ायदा नहीं होता. अब तो भगवान से ही न्याय की उम्मीद है.

बिहार का आम आदमी त्रस्त है. पुलिस और प्रशासनिक संवेदनहीनता से और जब इसकी फरियाद लेकर वह जनप्रतिनिधियों से लेकर सूबे के मुखीया नीतीश कुमार तक गुहार लगा कर थक जाते हैं तो उनकी निराशा और बढ़ जाती है और फिर किसी भी घटना पर उनका गुस्सा फूट पड़ता है. नतीजतन, फारबिसगंज, नूरसराय से लेकर नवादा तक आम आदमी गुस्से में पथराव और आगजनी करते हैं. पुलिस आम आदमी पर गोली से लेकर लाठी चलाते देखी जाती है. इस जलते बिहार में सेवा यात्री मुख्यमंत्री विकल्पहीनता के बीच जनता की नब्ज पकड़ने के भले ही दावे करते हों पर सच इससे काफी इतर है. जनाक्रोश इसी की परिणति है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

निशुल्क पौधा वितरण समारोह

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) के मुख्य द्वार के निकट स्थानीय महंत हनुमान शरण कॉलेज राजापुर, मैनपुरा, पटना-1 के सौजन्य से निःशुल्क पौधा वितरण समारोह का आयोजन किया गया, [illegible]

सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप

[illegible]

श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान महायज्ञ का समापन

[illegible]

पंचायत सचिवालय निर्माण में अनियमितता का आरोप

[illegible]

खगड़िया में निकला कैंडिल जुलूस

[illegible]

महेशखूंट में दंगल प्रतियोगिता

महेशखूंट (खगड़िया) मदारपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पीडब्लू डी महेशखूंट जमालपुर सड़क के किनारे [illegible] विराट दंगल [illegible] दंगल [illegible] दंगल [illegible] बताया [illegible] गयी. [illegible] धनखे[illegible] यादव [illegible] यादव [illegible] पहल[illegible] लेकर [illegible]

- चौथी दुनिया ब्यूरो

परवत्ता में सोलर लाइट बेकार

[illegible] ग्रामी[illegible] जांच [illegible]

- गीता यादव

मिड डे मील में अनियमितता का आरोप

हंटरगंज प्रखंड के [illegible] पनारी [illegible] संबंध [illegible] कि स[illegible] अनि[illegible] 50 [illegible] दिखा[illegible] बाबत [illegible] दुनिया [illegible]

- अमरेंद्र प्रताप सिंह

हेपेटाइटिस से बचने के लिए व्यायाम करें: तबरेज़

डॉ. तबरेज अजीज

हेपेटाइटिस समेत अन्य जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए सफ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. इन्फेक्शन के कारण हेपेटाइटिस ए, बी, सी जैसी बीमारियां होती हैं और लीवर सूख जाता है. साफ़ सब्जी व मौसमी फल भी प्रतिदिन खाना चाहिए. मोतिहारी ज़िले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. तबरेज अजीज ने उक्त सलाह दी है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्वस्थ्य व्यक्ति को वेक्सीन लेनी चाहिए और समय-समय पर चिकित्सकों का परामर्श भी लेना चाहिए. पूर्वी चम्पारण ज़िले में कुल आबादी के पंद्रह से बीस प्रतिशत लोग हेपेटाइटिस बीमारी से परेशान हैं. उन्होंने बताया कि जिस कदर आबादी बढ़ रही है और एक ही सुई का प्रयोग लोग करते हैं, इससे काफी नुकसान होता है. उन्होंने बताया कि समाज को जागरूक करने की आवश्यकता आ गयी है और इसके लिए समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति को आगे आना होगा. प्राथमिक उपचार पर भी उन्होंने जोर दिया. पूछे गये एक सवाल पर उन्होंने लैपरोस्कोपिक सर्जरी से ऑपरेशन कराने की सलाह मरीजों को दी और बताया कि इस पद्धति से हर तरह का ऑपरेशन आसानी से होता है और मरीज जल्द ही ठीक हो जाते हैं.

इंतेजारूल हक
feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ASRFEN-P
Aceclofenac + paracetamol Serratiopeptidase Tab.
ECTALOPAM
Escitalopram Oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo-XT
Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium Chloride Cough Syp.
MENSOSET
Her Tonic With Ashoka 1800mg.
MUSTAL
Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University, Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree
In the following Subjects :
• Fire Safety Management • Industrial Safety Management • Occupational Safety & Health Management • Environmental Safety & Health Management
FREE
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-3297011, Mob. : 9334107607, 9234929075

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

कुशवाहा को गोलबंद करने में जुटे नागमणि

सरोज सिंह

बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए नागमणि ने एक बार फिर कमर कस ली है. लेकिन इस बार वह संभल-संभल कर अपने पत्ते खोल रहे हैं. इन्होंने तय किया है कि फ़िलहाल छह महीने इनका सारा ज़ोर संगठन की मज़बूती पर होगा. पूरे बिहार में घूम घूम कर नागमणि ब्लॉक स्तर पर 51 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रहे हैं. इसमें 70 फीसदी भागीदारी कुशवाहा बिरादरी की और शेष अन्य समान विचार रखने वाले कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी. अपनी इस नई कवायद पर नागमणि कहते हैं कि बिहार की जनता विकल्प खोज रही है. हम चाहते हैं कि शहीद जगदेव सेना का संगठन पूरे बिहार व झारखंड के स्तर पर मजबूती से बने. वह चाहते हैं कि शहीद जगदेव सेना ऐसी ताक़त बनकर उभरे कि वह इन दोनों राज्यों की राजनीति की दिशा व दशा तय कर सके. नागमणि ने बताया कि वह ज़मीनी सच्चाई को पहचानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं. कुशवाहा बिरादरी के लोग चाहते हैं कि उनके समाज के लोग सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठें. उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को जहानाबाद के कुरहारी गांव से शहीद जगदेव सेना के अभियान की शुरुआत होने जा रही है. इसी दिन शहीद जगदेव बाबू की मूर्ति का अनावरण भी होगा. नागमणि ने बताया कि पूरे बिहार में वह अपनी मौजूदगी में संगठन बनवाएंगे तथा संघर्ष का शंखनाद करेंगे. उन्होंने कहा कि अभी मेरा पूरा ज़ोर संगठन पर ही होगा. सभी तरह के अत्याचार का विरोध शहीद जगदेव सेना के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे. उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज को सभी ने ठगने का काम किया है. लेकिन अब वह पूरे बिहार में घूम-घूम कर समाज को संगठित करेंगे और अत्याचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे. छोटे ज़िलों में दो दिन और बड़े ज़िले में चार दिन का प्रवास होगा और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नागमणि किसी नेता के सामने न झुका है और न झुकेगा. जनता मालिक है और उसी का आदेश मैं मानता हूं. उन्होंने कहा कि शहीद जगदेव सेना के प्रति पूरे बिहार में ज़बरदस्त उत्साह है और बहुत जल्द यह एक बड़ी ताक़त के तौर पर उभरेगी. जून 2012 के बाद पटना में राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों राज्य की जनता शहीद जगदेव सेना की तरफ आशा की निगाह से देख रही है.

feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस की सभी किसान भाईयों को हार्दिक बधाई
संकर मक्का
एनके-6607
NK syngenta
दो धारी ज्यादा अधिक उपज का वादा
हर भुट्टे में १६ से २० धारियाँ मतलब अन्य किस्म से २ से ४ ज्यादा धारियाँ
शानदार उपज क्षमता

राजेंद्र सरोवर बना पशुओं का चारागाह

खगड़िया ज़िले का हृयस्थल माने जाने वाले राजेंद्र सरोवर उद्यान बदहाली की कगार पर है. शहर के बच्चों, नौजवानों एवं बुजुर्गों के लिए 1995 में तत्कालीन ज़िलाधिकारी अजीत कुमार एवं उसके बाद सुधीर त्रिपाठी तथा ज़िले के तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी संतोष मैथ्यु के अथक प्रयास के बाद उक्त सरोवर का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ था तथा लाखों की राशि से सीढ़ी, बेंच, चाहरदिवारी एवं सड़क का निर्माण हुआ था. भ्रमण के लिए एक नाव की व्यवस्था की गई थी. लेकिन उक्त पदाधिकारी के जाने के बाद पुनः स्थिति जस की तस हो गई. उधर वर्तमान एनडीए सरकार के द्वारा भी इस उद्यान की सुध लेने वाला कोई नहीं है. वर्तमान में इस उद्यान में पशुओं का चारागाह बना हुआ है बल्कि वोट, सड़क तथा सीढ़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है. वहीं सन्हौली पंचायत के द्वारा पंचायत भवन का भी निर्माण किया गया था, ताकि इस सरोवर की रक्षा हो सके लेकिन दिन-प्रतिदिन स्थिति में सुधार के बदले बर्बाद ही हो रहा है. इस सरोवर के उत्थान के लिए कई बार समाजसेवी के द्वारा ज़िला पदाधिकारी सहित स्थानीय जन प्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ठ कराया गया था. एक वर्ष पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा सौन्दर्यीकरण का पुनः शिलान्यास किया गया था जो मरम्मति का कार्य भी हुआ लेकिन चन्द ही दिनों के बाद कार्य बन्द हो गया. सुशासन की सरकार की बात की जाय तो यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जीर्णोद्धार के लिए प्रयास ही नहीं किए गए. वहीं नगर परिषद क्षेत्र में न रहने के कारण इस क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा ध्यान देना भी बेमुनासिब होगा. उक्त क्षेत्र सदर प्रखंड के सन्हौली पंचायत के अन्तर्गत आते हैं. उक्त पंचायत की मुखिया शोभा देवी का कहना है कि पंचायत में समुचित मात्रा में विकास राशि न मिलने के कारण सरोवर का सौन्दर्यीकरण करना संभव नहीं है. इसलिए समुचित विकास के लिए ज़िला योजना की राशि से करनी चाहिए. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जदयू द्वारा हरित अभियान के तहत पेड़-पौधा लगाया जाता है लेकिन राजेंद्र सरोवर को हरा-भरा करने का तनिक भी प्रयास नही किया जा रहा है. यदि इसका सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय तो जिले के सर्वोत्तम मनोरंजन का केंद्र बनेगा ही, बल्कि सबसे बड़ी उपलब्धि भी होगी. उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री भरत सिंह जोशी का कहना है कि राजेंद्र सरोवर के जीर्णोद्धार को लेकर ज़िलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन आज तक इसके विकास के प्रति पदाधिकारी द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है. भाजपा ज़िलाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद का कहना है कि राजेंद्र सरोवर के सौन्दर्यीकरण को लेकर प्रभारी मंत्री बीससूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को अवगत कराया है, जल्द ही इस समस्या का निदान हो जाएगा. वहीं महिला महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉ. अरविन्द कुमार सिंह का कहना है कि शहर का विकास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ राजेंद्र सरोवर का उत्थान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मवेशियों का चारागाह बनता जा रहा है. इधर सन्हौली निवासी मंजय कुमार मंडल का कहना है कि मुख्यमंत्री सेवा यात्रा को लेकर ज़िले को रंग-रोगन किया जा रहा है. लेकिन राजेंद्र सरोवर उद्यान के सौन्दर्यीकरण की कौन कहे, बल्कि साफ़-सफ़ाई भी नही की जाती है. जिस कारण पशुओं का स्नानागार बन गया हैं. जबकि पहले सन्हौली वासियों के द्वारा उक्त सरोवर में स्नान किया जाता था.

मनेन्द्र कुमार
feedback@chauthiduniya.com

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों बदहाल

बक्सर में आबाद किया गया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल अब सुशासन की सरकार में बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है. भवन ध्वस्त हो गये तो कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया. परिणाम स्वरूप सीसीआईएम ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी. अब सौ बेड वाला अस्पताल भी आख़िरी सांस गिन रहा है. यहां के छात्रों को मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करने तथा देसी चिकित्सा को विकसित करने का दंभ भरने वाली सुशासन सरकार की कलई बक्सर में उजागर हो जाती है. राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय, अहिरौली (बक्सर) में सरकारी अव्यवस्था का ग्रहण लग गया. अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चलाने की घोषणा के विपरीत बंदी की आशंका व्यक्त की जाने लगी है.

शासी निकाय द्वारा अपने संसाधनों से 1972 में आयुर्वेदिक महाविद्यालय सह चिकित्सालय को स्थापित किया गया. जिसे राज्य सरकार ने जून, 1986 में अधिग्रहण कर लिया. इसमें कुल 14 विभाग थे और रोगियों के लिए सौ बेड थे. इसमें पढ़ने वाले छात्र बीएएमएस की डिग्री लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते थे और प्रतिदिन लगभग दो ढाई सौ लोग इलाज के लिए आते थे. जिन्हें दवा भी दी जाती थी. लेकिन इसमें धांधली तथा घोटालों को लेकर लंबी लड़ाई हुई और फिर एक प्राचार्य सहित दर्जनों कर्मचारी बर्ख़ास्त कर दिये गए. जर्जर तथा ध्वस्त भवन, उपस्कर तथा कर्मचारी की कमी बताकर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) दिल्ली ने कॉलेज की मान्यता वर्ष 2003 में समाप्त कर दी. तभी से मेडिकल की पढ़ाई बंद हो गयी. प्राचार्य डॉ. तेजनारायण चौबे बताते हैं कि यदि भवन बन जाये तथा प्रर्याप्त कर्मचारी हो जाएं तो सीसीआईएम द्वारा फिर से मान्यता प्रदान कर जाएगी. लेकिन सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती दिखती है. बल्कि एक-डेढ़ साल के अंदर दर्जनों डॉक्टरों तथा कर्मचारियों का तबादला पटना तथा बेगूसराय कर दिया गया. प्राचार्य डॉ. चौबे यह भी बताते हैं कि भवन निर्माण विभाग द्वारा नए भवन के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए का प्राक्कलन बनाकर सरकार के पास भेजा गया है. पर सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है. मेडिकल के बाद अब अस्पताल भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है.

अस्पताल के सारे उपस्कर जंग खा गये तथा बेड टूट-फूट कर बेकार हो गए. महिला डॉक्टर तथा कम्पाउंडर एक भी नहीं है. दुर्भाग्य तो यह है कि अधिग्रहण के बाद सरकार ने कर्मचारियों को केवल वेतन दिया. लेकिन भवन, मशीन, उपस्कर बेड आदि मद में आज तक एक रुपया भी ख़र्च नहीं किया. खंडहर बने इस अस्पताल में आज भी प्रतिदिन 50-60 लोग इलाज के लिए आते हैं और उन्हें आयुर्वेदिक दवा दी जाती है. भवन तथा बेड के अभाव में मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है. देसी चिकित्सा का गुण बताते हुए प्राचार्य चौबे कहते हैं कि यहां हेपेटाइटिस-बी से ग्रस्त रोगी को भी ठीक किया गया है. सरकार की उपेक्षा के कारण ही पांच बीघे में लगे औषधीय पौधे भी समाप्त हो गए. सरकार तथा जनप्रतिनिधियों की नीति में खोट नहीं होती तो शायद बक्सर का आबाद संस्थान आज मरणासन्न नहीं होता. इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की बदहाली सुशासन सरकार की कथनी तथा करनी की मूक दास्तान सुना रही है.

जयमंगल पाण्डेय
feedback@chauthiduniya.com

सारण एक नज़र

विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा श्रोत-रूढ़ी

छपरा एकता भवन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा दिवस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि विवेकानन्द युवाओं के प्रेरणास्त्रोत हैं. नेशनल यूथ कोर के विश्वजीत कुमार चंदेल एवं जूली ने कोर के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए सांसद से संसद में प्रश्न उठाने का आग्रह किया. इस अवसर पर विधायक संजय सिंह टाइगर, सोनपुर विधायक विनय सिंह, अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटु, गडखा विधायम ज्ञानचन्द्र मांझी, तरैया विधायक जनक सिंह तथा शिक्षाविद डा. लालबाबू यादव, जगदम कॉलेज के विद्वान प्रचार्य डॉ. प्रमेन्द्र रंजन, प्रचार्य डॉ. आरएस राय, डॉ. विएन पांडेय, एनएसएस समन्वयक वीवी त्रिपाठी, डॉ. जयराम सिंह, सवर्ण आयोग के सदस्य संजय मयूख, नीरज कुमार सिंह, धनंजय कुमार, लालू सिंह, रविरंजन प्रताप, आदि ने संबोधित किया.

नवग्रह शांती हवन महायज्ञ सम्पन्न

सदर प्रखंड के मुसेपुर पंचायत अंतर्गत नागा बाबा के आश्रम में 51 कुंडीय शनि शांती चन्दी हवन महायज्ञ का आयोजन किया गया. जिसमें 51 हवनकुंड बनाये गये. जिसमें यजमान शामिल हुए. मुख्य यजमान मुसेपुर पंचायत के मुखिया मुन्ना कुमार के साथ साथ सरपंच सर्वा नन्द राय पूर्व मुखिया हेमन राय आदि शामिल हुए.

एनसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन

एनसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट की टी-20 प्रतियोगिता का उदघाटन तरैया के प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह, उसुआपुर के प्रखंड प्रमुख बेबी सिंह, पानापुर के प्रखंड प्रमुख नीलम देवी नाथ मढौरा प्रखंड प्रमुख मधुसूदन प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया. उदघाटन मैच कुमार क्रिकेट क्लब एवं सनराइज क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया. इसमें कुमार क्रिकेट क्लब को 63 रनों से विजयी घोषित किया गया. इस मौके पर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार, जिला पार्षद ब्रजेश सिंह, पप्पू सिंह, डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह, धनंजय सिंह, शिवभूषण सिंह, मनोज सिंह, विकास कुमार सिह, वृजकिशोर सिंह, मनोज सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

जितेन्द्र ही रहेंगे अध्यक्ष

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. विनोद शर्मा ने बताया कि विजयशंकर मिश्र अध्यक्ष फ्लैगशिप मॉनीटरिंग कमेटी के निर्देशानुसार जितेन्द्र कुमार सिंह अध्यक्ष छपरा जिला फ्लैगशिप मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे. इस निर्णय से सारण प्रमंडल के कांग्रेस कर्मियों ने ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए प्रदेश अध्यक्ष व प्रवक्ता को कोटि कोटि बधाई दी.

कम्प्यूटर शिक्षा आवश्यक

फैक्ट ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अपने बढ़ते हुए कदम में एक और कदम मशरक में अल शाहिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी नामक संस्था खोलकर बढ़ाया. संस्था का उद्घाटन आर.एन. यादव प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मशरक ने फीता काटकर किया. इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उदघाटनकर्ता आर.एन यादव ने अपने संबोधन के द्वारा कम्प्यूटर के महत्व और इसकी इपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कम्प्यूटर आज के परिवेश में शिक्षा की कुंजी है और इसके माध्यम से दुनिया की ताज़ा तरीन घटनाओं और जातिविधियों की ख़बर रखी जा सकती है.

छह चिकित्सा कर्मियों पर गिरी गाज

ज़िलाधिकारी विनय कुमार ने जलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आधा दर्जन चिकित्सा कर्मियों द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, अनाधिकृत ढंग से अनुपस्थित रहने तथा अनुशासनहीनता के आरोप के अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक लगाने एवं दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दिये जाने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई सदर एसडीओ के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की गयी है. डीएम ने आदेश दिया है कि एसडीओ जब निरीक्षण करने पहुंचे, तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एसबी राय समेत आधा दर्जन चिकित्साकर्मी अनुपस्थित पाये गये. प्रभारी चिकित्सकर्मी अनुपस्थित पाये गये.

जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ ने किया वृक्षारोपण

जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ छपरा सारण एवं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ छपरा सारण के संयुक्त तत्वाधान में हरित बिहार अभियान के अन्तर्गत साधु लाल पृथ्वी चन्द्र उच्च विलय में जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल तथा जदयू अप्लसंख्यक प्रकोष्ठ के ज़िला सचिव जैद अहमद के संयुक्त नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया. अशोक, आम, ग्रीन सेमल आदि का पौधा लगाया. इस अवसर पर वार्ड पार्षद अमिताजी सोनी, राजेश नाथ, असलम परवेज, अधिवक्ता जफर आलम, अधिवक्ता अर्जुन कुमार शाही, राकेश कुमार, राजेश फैशन, अनूप कुमार, राजेश शुभम, मनोज सिंह, राजेश जायसवाल,सुधिर कुमार पासवान आदि उपस्थित हुए. वृक्षारोपण का अभियान जदयू के व्यवसायी शाखा, अतिपिछड़ा शाखा, महादलित शाखा व सेवादल जदयू की तरफ काफ़ी मजबूती से चलाया जा रहा है. वहीं कई नेताओं द्वारा खानापूर्ति की जा रही है. ऐसे देखें तो यदि वृक्षारोपण का यह अभियान अपने आधे लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है तो बिहार हरियाली के मामले में देश में अग्रणी हो जाएगा.

हर व्यक्ति के साथ हो समान व्यवहार

भारत का संविधान हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार अपनाने की बात कहता है. ऐसे में लिंगातीत व्यक्तियों (किन्नरों) के साथ किसी भी तरह का भेदभाव कानून का उल्लंघन है. हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना ही मनुष्य का सबसे उत्तम गुण होना चाहिए. उक्त बातें गोपालगंज में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान में आयोजित लिंगातीत व्यक्तियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए सबजज विश्वनाथ ने कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है. ऐसे में कहीं अगर लिंगातीत व्यक्तियों के साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो वह क़ानून का उल्लंघन है. हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार अपनाना चाहिए. इस मौके पर प्रभारी न्यायाधीश एससी द्विवेदी ने कहा कि संवधिान में जो अधिकार आम नागरिक को मिला है वही अधिकार लिंगातीत नागरिको को भी मिला है. इस मौके पर राजेश कुमार पाठक विपिन बिहारी श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी एडीबी दुबे , इन्द्रजीत सिंह, आर के त्रिपाठी जितेन्द्र कुमार के अलावा मुन्ना किन्नर, सुमन किन्नर, चांदनी, ज्योति किन्नर, मधु किन्नर, तथा खुशबू सहित कई लोग उपस्थित थे.

गोपालगंज में योगगुरू के समर्थन में प्रदर्षन

गोपालगंज के हथुआ में योग गुरू बाबा रामदेव पर दिल्ली में स्याही फेंकने की घटना से नाराज लोगों ने बाबा के समर्थन में धरना दिया. मीरगंज विद्युत पावर स्टेशन के समीप नगरपंचायत के वार्ड पार्षद गुड्डू मालाकार के नेतृत्व में पिछले दिनों धरने पर बैठे लोगों ने योग गुरू पर स्याही फेंके जाने की घटना की जमकर निंदा की . पंतजलि योग पीठ के संत मोहन दास ने कहा कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाकर इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग योग गुरू बाबा रामदेव लंबे समय से करते आ रहे हैं. इस मांग से भयभीत लोगों ने ही साजिश कर योग गुरू पर स्याही फिंकवाई है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे कुछ राजनेता नहीं चाहते कि विदेश में जमा काला धन इस देश के विकास में लगे. इसलिए उनके द्वारा योग गुरू पर तरह-तरह का आरोप लगाया जाता रहा है. इसके बाद भी जब बाबा ने अपना अभियान नहीं रोका तो उन पर स्याही फेंकने की घिनौनी हरकत की गयी. इस मौके पर बजरंगी सिंह, संतोष शर्मा, दीपक यादव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे.

प्रस्तुति- शुभम रानी चौहान, मनीष कुमार कश्यप

संयुक्त बिहार में जहां नक्सलियों की कथित राजधानी माने जाने वाले कुंदा थाना क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में इंदिरा आवास काग़ज़ों पर ही सम्पादित कर दिये गए.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

गन्ना की खेती कर पछता रहे किसान

मोतिहारी

इन्तेजारूल हक

पूर्वी चम्पारण के गन्ना उत्पादक इन दिनों काफी चिन्तित हैं और इनके द्वारा हज़ारों हेक्टेयर भूमि पर उपजाये गए गन्ना की ख़रीददारी मिल प्रबंधकों व अन्य क्रय केंद्रों द्वारा न किये जाने के कारण इनकी मेहनत पर पानी फिरता नज़र आ रहा है. ज़िले के कोटवा, केसरिया, चकिया समेत कुछ प्रखंडों में क्रय केंद्रों पर गन्ना की ख़रीददारी अगर हो भी रही है तो वहां दलालों की चांदी कट रही है. मोतिहारी सुगर मिल का चालू न होना व सुगौली चीनी मिल का चालू होकर बन्द हो जाना, अनेक सवालों को खड़ा कर रहा है. मोतिहारी चीनी मिल के प्रबंधन के यहां किसानों का जहां पूर्व से क़रीब छह करोड़ रुपये का बकाया है, वहीं वहां काम करने वाले मज़दूर भी हाशिये पर हैं. प्रत्येक वर्ष गन्ना की पेराई के मौके पर किसानों को मिल प्रबंधन द्वारा मिल चलाने का आश्वासन दिया जाता है और इसे चालू भी किया जाता है, किन्तु ब्वायलर खराब होने की समस्या बताकर फिर बन्द कर दिया जाता है. हालांकि मोतिहारी मिल के प्रबंधन द्वारा आगामी सात फरवरी तक हर हाल में मिल चालू कराने का आश्वासन दिया गया है. यहां काम करने वाले मजदूर मिल मालिक की नीयत में खोट बताते हैं तो दूसरी तरफ ज़िले के किसान इस मिल में गन्ना देना मुनासिब नही समझते. मज़े की बात यह है कि बिहार सरकार के गन्ना मंत्री भी इसी ज़िले के विधायक हैं और वे भी उक्त मिल को चालू कराने में अभी तक नाकाम दिख रहे हैं. यही हाल सुगौली मिल का है. वर्षों से बन्द सुगौली मिल को काफी मेहनत के बाद एचपीसीएल कम्पनी ने इसे चालू कराया और धुआं निकलने के बाद फिर बन्द हो गई. अब ज़िले के किसानों के लिए गोपालगंज के अलावा दूसरा कोई चारा नही दिख रहा है. ज़िला मुख्यालय से गोपालगंज की दूरी जहां सत्तर किलोमीटर है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से सौ किलोमीटर की दूरी पर गोपालगंज मिल स्थित है. ऐसी स्थिति में ज़िले के गन्ना उत्पादक असमंजस की स्थिति में हैं. अगर ये किसान गन्ना की जगह पर गेहूं व मसूर की खेती करते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती. मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मनोज पासवान ने बताया कि अगर मोतिहारी चीनी मिल सात फरवरी तक चालू नहीं होती तो मिल के सभी अधिकारियों के कार्यालय में ताला लगाया जायेगा. दूसरी तरफ गन्ना उत्पादकों की इस समस्या के लिए राजद ने बिहार की नीतीश सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है. युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मोतिहारी विधान सभा के पूर्व प्रत्याशी राजेश गुप्ता

बबलू गुप्ता अवधेश कुशवाहा

उर्फ़ बब्लू गुप्ता, ज़िलाध्यक्ष बच्चा यादव ने बताया कि गन्ना उत्पादकों के लिए सरकार केवल घोषणाएं करती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती. ज़िले के किसान भी सरकार की इस नीति से परेशान हैं और आन्दोलन करने का मन बना रहे हैं. पिछले दिसम्बर माह में समाहरणालय पर आहूत राजद के धरना में उमड़ी किसानों की भीड़ ने यह साबित कर दिया था कि अबतक सरकार द्वारा की गई तमाम कार्रवाई केवल घोषणाओं में ही सिमट कर रह गयी हैं. कुल मिलाकर ज़िले के गन्ना उत्पादक गन्ना उपजाकर पछता रहे हैं और इसे औने–पौने भाव पर बेचने का मन बना रहे हैं. यहां यह भी बताते चले कि पूर्वी चम्पारण ज़िले के करीब साढ़े तीन सौ पंचायतों में गन्ने की खेती किसान खूब करते हैं और वहां की मिट्टी भी गन्ना के लिए बेहतर है. इस बीच किसान संघर्ष समिति के नेता हरिदयाल कुशवाहा ने बताया कि मिल प्रबंधन की मनमानी व सरकार की वादा ख़िलाफ़ी के विरोध में शीघ्र ज़िले के किसान सड़क पर उतरेंगे और इसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं. दूसरी तरफ स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने बताया कि ज़िले के किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसका परिणाम भी दिखेगा.

feedback@chauthiduniya.com

ग़रीबों का इंदिरा आवास किसकी जेब में?

अपूर्ण इंदिरा आवास

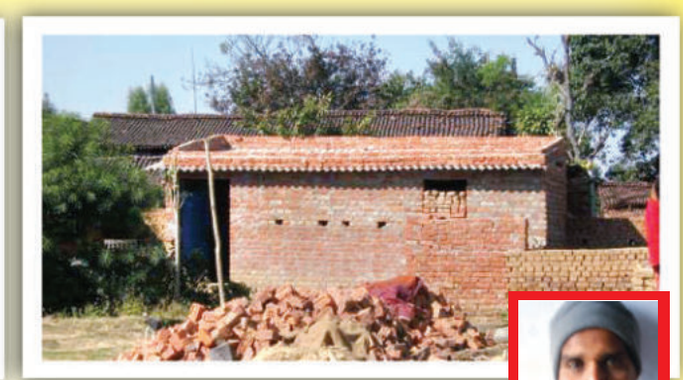

चंद्रेश शर्मा

आनंदी सिंह

संयुक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने चतरा को सर्वाधिक उग्रवाद क्षेत्र घोषित करते हुए ज़िला का दर्जा दिया था, तब से लेकर अबतक क्षेत्र में विकास के नाम पर जमकर लूट मची. संयुक्त बिहार में जहां नक्सलियों की कथित राजधानी माने जाने वाले कुंदा थाना क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में इंदिरा आवास कागजों पर ही सम्पादित कर दिये गये, वहीं आज चतरा ज़िले के लगभग प्रखंडों का यही हाल है. चतरा ज़िले का सबसे बड़ा प्रखंड है हंटरगंज. यहां पिछले तीन वर्षों में ख़ासकर वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 में 2812 इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था. जिसमें से मात्र 1023 ही पूर्ण हो पाये तथा 1781 अभी भी अपूर्ण हैं. कहने को तो 1023 पूर्ण हैं परन्तु इसमें अभी भी 100 इंदिरा आवास धरातल पर कहीं भी दिखायी नहीं देते. अभी पिछले दिनों ज़िला योजना समिति की बैठक में अध्यक्ष के तौर से शामिल होने आए राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चतरा को आर्दश ज़िला बनाने के लिए गोद लेने की घोषणा की, लोगों में उम्मीद की नयी किरण जगी. लेकिन क्या वाकई इस घोषणा में दम है, इसका तार्किक जबाव सरकार के पास भी नहीं है. सरकार कहती है कि योजनाओं में पारदर्शिता बरती जायेगी, परन्तु होता क्या है वही ढाक के तीन पात! यहां सक्रिय नक्सली कहतें हैं कि क्षेत्र में हमारा राज है और प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं. तो आख़िर क्षेत्र में विकास का ग्राफ इतना नीचे क्यों है, जनता को यह कौन बताएगा. चतरा ज़िला झारखंड का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, यहां के प्रशासनिक अधिकारी आज भी दुरूह क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं. जिसके कारण बिचौलियों की ख़ूब चांदी कटती है. बिचौलियों द्वारा सरकारी काया में जमकर दिलचस्पी ली जाती है, क्षेत्र में बिना गए ही सरकारी अधिकारी बिचौलियों के कहने पर योजनाओं का सम्पादन कर देते हैं. बाद में जब मामला फंसता है तो भ्रष्टाचार के इस युग में मामला टांय टांय फिस्स होकर रह जाता है. हां अगर कहीं मामला बढ़ गया तो अधिकारी तो बच जाते हैं परन्तु बलि का बकरा निचले स्तर के कर्मचारी बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला हंटरगंज प्रखंड में भी देखने को मिला, हंटरगंज के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अगस्टीन प्रफुल्ल बेग के कार्यकाल में इंदिरा आवासों में जमकर गड़बड़ी की गयी. काफी शिकायतों एवं जांच के बाद भी बीडीओ पर काफी दिनों तक कार्रवाई नहीं की गयी, चतरा के सांसद इंदरसिंह नामधारी तक ने अनुश्रवण समिति की बैठक में मामला उठाया, लेकिन ज़िला प्रशासन ने मानो कसम खा ली थी कि कार्रवाई नहीं करनी है. सांसद के द्वारा राजधानी में राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में मामला उठाने के बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद बीडीओ का चतरा से तबादला किया गया. इस पूरे प्रकरण में चतरा के उपविकास आयुक्त अनिल पांडेय की भूमिका काफी संदिग्ध रही. सांसद नामधारी की मानें तो उपविकास आयुक्त ने बीडीओ को बचाने का पूरा प्रयास किया. आश्चर्य तो तब और होता है जब चतरा के उपायुक्त मनोज कुमार के इस पत्र पर अभी जांच नहीं प्रारभ हुई है, जिसमें चतरा के उपविकास आयुक्त को गोपनीय शाखा ज्ञापांक–984 दिनांक 25/10/11 के माध्यम से हंटरगंज के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी ए पी बेक द्वारा चयनित किये गये 183 इंदिरा आवासों के लाभुकों का चयन रद्द करते हुए आरोपी बीडीओ एवं संबंधित पंचायत सेवकों पुनीत दास, अर्जुन पासवान, वीरेंद्र राम, ब्रजेश चौबे एवं ईश्वर राणा के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा गया था. इस संबंध में ज़िला जदयू प्रवक्ता आनन्दी सिंह ने चौथी दुनिया को बताया कि संबधित आरोपियों के ख़िलाफ़ कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है इसके बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ पाया है. प्रवक्ता आनन्दी सिंह कहते हैं कि भ्रष्ट व्यवस्था में पूरा प्रशासन तंत्र आरोपियों को बचाने में लगा है.

feedback@chauthiduniya.com

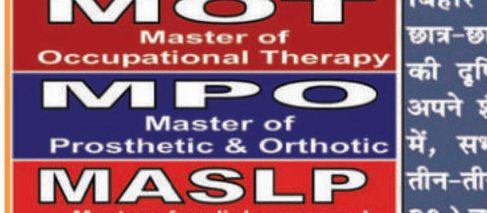

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना–२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-
POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of audiology speech & Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology Speech & Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology

मेधावी छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क शिक्षा
बिहार प्रदेश के मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्थान प्रबंधन ने अपने शैक्षणिक सत्र–२०१२–१३ में, सभी डिग्री पाठ्यक्रमों के तीन–तीन स्थानों के लिए (कुल २१) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पॉच–पॉच स्थानों कुल ३० पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस हेतु आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तारीख ३१ जनवरी २०१२ तथा मेघा परीक्षा की तिथि १२ फरवरी निर्धारित की गई है।
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि ३१ जनवरी २०१२
मेधा परीक्षा १२ फरवरी २०१२
1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab.
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theather Assistant
DECG Diploma in E.C.G.
certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-and DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same, 10+2 with science for under Grtaduate & diploma Courses For B.Ed. Degree in any Subjecty.

डा.अनिल सुलभ
निदेशक–प्रमुख

Registration for Admission into Academic session 2012-2013 going on.
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email.iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

Triveni Infratech
Triveni Infratech Developing India...
A COMPLETE TOWNSHIP.......
0.5 km From Booty More, Ranchi
READY TO SHIFT

ON GOING PROJECTS

Triveni Enclave (Dhanbad)

Upcoming Projects
- Arunoday-Argora Ashok Ashram Road, Ranchi
- Triveni Spring-Namkum, Khijri, Ranchi
- Triveni Sun City - Sidrol, Ranchi - Tata Road, Ranchi
- Triveni Twin City - Bokaro - Dhanbad Road, Bokaro

READY TO SHIFT
Our Accomplishments

OM SHANTI TOWER	- Residential	- Old commissioner Compound
SHANTI NIKETAN	- Residential	- Burdhwan Copound, Lalpur
SUSHILA ENCLAVE	- Residential	- Harmu, Ranchi
ANAND BHAWAN	- Residential	- Bariatu Ranchi
BANWARI COMPLEX	- Res.&Commercial	- Upper Bazar, Ranchi
SRI KAUSHAL TOWERS	- Commercial	- Bariatu Ranchi
BRINDAVAN	- Residential	- Morabadi, Ranchi
BADSHAH PALACE	- Res.&Commercial	- Main Road, Ranchi
MADHUKAR REGENCY	- Res.&Commercial	- Shrahanand Road, Ranchi
SHANTI ENCLAVE	- Residential	- Ashok Nagar, Ranchi

EXCITING FACILITIES : * Playgound * Marriage Hall * Dispensary * Jogging Track * Modern Shopping* Garden
* 24 HRS. POWER & WATER FACILITY * ROUND-O-CLOCK SECURITIES * CHARMING ATMOSPHERE

Keshri Heights (Jamshedpur)

Triveni Infratech Pvt. Ltd.
"Divine House" Club Road, Ranchi-01 (jharkhand)
Contact : 91 - 9386852819, 9334714082,9835569900, 9386852791, 0651-2331860
Email : sritriveni@gmail.com, Website : www.triveniinfratech.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 30 जनवरी–05 फरवरी 2012

www.chauthiduniya.com

नेताओं को जनता की चिंता नहीं

जिन मुद्दों को लेकर नेतागण पांच साल तक सड़क पर घूमते रहे उन्हें चुनाव के मौक़े पर कोई उठाना नहीं चाहता. चुनाव आयोग तीस करोड़ का काला धन 15-20 दिनों में बरामद कर चुका है. इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में काले धन की आमद कितनी तेजी से हो रही है. शराब की गाड़िया पकड़ी जा रही हैं. राजनीतिक पार्टियों ने अपने विचारधारा को ताक़ पर रख दिया गया है. सपा लगातार मायावती और केंद्र के कुशासन के ख़िलाफ़ संघर्ष करती रही, लेकिन चुनावी बेला में उसके नेताओं को जीत के लिए शॉर्टकट तरीक़ा मुस्लिम आरक्षण ही नज़र आया. उसे डर है कि उसके मुस्लिम वोट बैंक में कोई सेंध न लगा दे. कोई मुसलमानों को लुभाने के लिए टोपी पहन रहा है तो कोई उनकी चौखट पर नाक रगड़ रहा है.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अजय कुमार

विधानसभा चुनाव में नेताओं ने जनता से जुड़े बिजली–पानी रोटी मंहगाई, बिगड़ी क़ानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लोकपाल, स्वास्थ्य घोटाला, महिलाओं के उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दों को पीछे ढकेल कर उन मुद्दों को आगे बढ़ा दिया है जिससे प्रदेश का कम उनका ज़्यादा भला हो सकता है. एक तरफ़ हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर टिका हुआ है तो दूसरी तरफ़ राजनीतिक पार्टियां धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा देने में लगी हैं. जिन मुद्दों को लेकर नेतागण पांच साल तक सड़क पर घूमते रहे उन्हें चुनाव के मौक़े पर कोई उठाना नहीं चाहता. चुनाव आयोग तीस करोड़ का काला धन 15–20 दिनों में बरामद कर चुका है. इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में काले धन की आमद कितनी तेजी से हो रही है. शराब की तो गाड़ियों की गाड़िया पकड़ी जा रही हैं. राजनीतिक पार्टियों ने अपने विचारधारा को ताक़ पर रख दिया गया है.

समाजवादी पार्टी लगातार मायावती और केंद्र के कुशासन के ख़िलाफ़ संघर्ष करती रही, लेकिन चुनावी बेला में उसके नेताओं को जीत के लिए शॉर्टकट तरीक़ा मुस्लिम आरक्षण ही नज़र आया. उसे डर है कि उसके मुस्लिम वोट बैंक में कोई सेंध न लगा दे. कोई मुसलमानों को लुभाने के लिए टोपी पहन रहा है तो कोई उनकी चौखट पर नाक रगड़ रहा है. जुलाई 2011 तक के आकड़ों के अनुसार प्रदेश में क़रीब साढ़े चार हज़ार मदरसे हैं, जिनमें 14028 अध्यापक हैं जो विज्ञान, गणित, भूगोल और उर्दू पढ़ाते हैं. पिछले दो वर्षों से उन्हें आंशिक तौर पर ही वेतन का भुगतान मिल रहा है. साढ़े चार हज़ार मदरसों में से पांच सौ मदरसों को सरकारी मतदान की सूची में रखे जाने के बाद भी कई सालों से कोई मदद नहीं मिली है. ग़रीब मुस्लिम लड़कियां वजीफे के लिए भटक रही हैं, लेकिन यह सब बाते मुद्दा नहीं बन पाईं. मुद्दा बना तो आरक्षण. बटला का जिन्न भी कुछ नेताओं ने बोतल से बाहर कर दिया है. एक तरफ़ कांग्रेसी बटला हाउस मुठभेड़ के फ़र्ज़ी होने या न होने पर लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ़ भाजपा जानना चाहती है कि बटला एनकाउंटर केस जिसमें पुलिस का एक अधिकारी भी मारा गया था क्या फ़र्ज़ी था. बटला का मुद्दा दिग्गी राजा ने अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए चला था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया. कांग्रेस ने उनके बयान को निजी बता कर पल्ला झाड़ लिया. कांग्रेस की काट के लिए 4.5 की जगह मुलायम मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण की बात करने लगे. भाजपा का सुशासन का नारा भी चुनावी बयार में उड़ गया. अब उसे केंद्र और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और जनलोकपाल से अधिक पिछड़ों को लुभाने की चिंता है. पिछडों को लुभाने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे बाबू सिंह कुशवाहा से भी उसे हाथ मिलाने में परहेज नहीं हुआ. यूपी के चुनावी समर में भाजपा एक मात्र ऐसी पार्टी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रही है. राहुल गांधी की तो बात ही निराली, वह पिछले दो–तीन सालों से दलितों–पिछड़ों के यहां खाना खाते रहे और उनके ही आरक्षण कोटे में सेंध लगा दी. चुनावी जंग में इनके मुंह से बस एक ही शब्द फुट रहा है, वह है मुसलमानों को आरक्षण की बात.

तमाम मुद्दों के अलावा एक मुद्दा सबसे अहम है जिसे अब कोई पार्टी नहीं पूछती. वह है देश की निरंकुश रूप से बढ़ती आबादी की समस्या. एक तरफ़ गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, कृषि योग्य ज़मीन कम होती जा रही है तो दूसरी तरफ़ जनसंख्या की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है. बढ़ती आबादी के कारण सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता. इसी कारण मंहगाई बढ़ रही है. युवा बेरोजगार घूम रहे हैं. कुछ दशक पूर्व तक बढ़ती आबादी चुनाव का मुद्दा हुआ करता था, लेकिन देश पर भारी धर्म ने इस मुद्दे पर नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया. बड़े परिवार का नुक़सान बताने के बजाए, उन्हें वोट बैंक के रूप में पहचाना जाता है. नेताओं को पता है कि बढ़ती आबादी देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट चाहने वालों के लिए तो देश से बड़ी सत्ता है.

माना जा रहा था कि इस बार काला धन, भ्रष्टाचार जनलोकपाल, मंहगाई, क़ानून व्यवस्था, टूटी सड़कें, बिजली–पानी का रोना, किसानों की भूमि अधिग्रहण की नाराज़गी, खाद की कालाबाज़ारी, बेरोजगारी मायावती की तानाशाही मुख्य चुनावी मुद्दे होंगे. लेकिन नेताओं ने ऐसी चक्कर घिन्नी घुमाई कि सब अपने धर्म को बचाने में लग गए. सत्तारूढ़ बसपा अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मुसलमानों की बदहाली का ठीकरा केंद्र पर फोड़ती रही. भले ही वह मदरसा शिक्षकों को वेतन तक न मुहैया करा पाई हो. पांच साल तक राज करने के बाद भी उसकी हिम्मत विकास के नाम पर वोट मांगने की नहीं पड़ी. जनता को लुभाने के लिए उसने प्रदेश को चार टुकड़ों में बांटने की आग लगाई. बुंदेलखंड की दशा सुधारने के बजाए मायावती सरकार बदहाली का रोना रोती रही, जबकि यहां से बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी सीटें मिली थीं. किसानों की समस्याओं को उन्होंने कभी समझा नहीं. उनकी ज़मीन चहेते बिल्डरों को दे दी गई. पांच साल तक यमुना एक्सप्रेस वे भी अधर में है, जिनके कंधों पर मायावती ने यह ज़िम्मेदारी डाली थी, उसने अपनी बैंक गारंटी वापस ले ली है. भ्रष्टाचार का दाग़ मायावती सरकार पर शुरू से ही लगता रहा है. स्वास्थ्य घोटाले ने तो सभी सीमाएं पार कर दीं, लेकिन मायावती अपने मंत्रियों को तब तक संरक्षण देती रहीं जब तक कि चुनाव का झुनझुना नहीं बज गया. मायावती सरकार ने विकास की अनदेखी कर मूर्तियों पर पैसा पानी की तरह बहाया. मायावती को जनता ने कुर्सी सौंप दी इसके बाद उनके स्वभाव में ऐसा बदलाव आया कि वह चुनावी मौसम में भी जनता से दूरी बनाए हुए हैं. उनकी न कोई सभा हो रही है, न बैठकें. अंत में उन्हें मीडिया की याद सताने लगी है. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती सरकार को लगातार तानाशाह और भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन उनके पास भी इस बात का जवाब नही था कि उनकी सरकार क्या मायावती सरकार से बेहतर थी. पहले भी समाजवादी पार्टी के पास भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई फार्मूला नहीं था और आज भी नहीं हैं. जनलोकपाल के बारे में तो उनके नेताजी का यहां तक कहना है कि यह बिल पास हो गया तो दरोगा भी इन लोगों(सांसदों)को जेल में डाल देगा. समाजवादी पार्टी के नेता स्वच्छ सरकार देने की बात कहते हैं, उन्हें इस बात का अहसास है कि पिछली बार उनके शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर थी, लेकिन एक डीपी यादव को पार्टी में लेने के फ़ैसले को छोड़कर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि वह प्रदेश के विकास के प्रति सजग हैं. बस कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाने की चिंता है. समाजवाद के नाम पर मुलायम अपने पूरे परिवार को चुनावी मैदान में ले आए हैं. कांग्रेस तो शुरू से ही झुनझुने से ही काम चला रही है. वह मुसलमानों को बता रही है कि मुसलमान भाईयों को आरक्षण का फ़ायदा मिलते ही उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी. यह बात बताने के लिए कांग्रेस के युवराज लखनऊ में नदवां तक पहुंच गए, राहुल की बातों का सार तलाशा जाएं तो यही लगता है कि अल्पसंख्यकों को भले ही बत्ती–पानी और बीमार पड़ने पर इलाज की सुविधा न मिले, उनके घर के बाहर कचरा जमा रहे, पेट भर खाना, शिक्षा मुहैया न हो, इससे राहुल और उनकी पार्टी को कुछ लेना–देना नहीं क्योंकि इस पर तो लगाम लगाई नहीं जा सकती है. मिलावटखोरों को पकड़ा जाएगा, कालाबाज़ारियों को घेरा जाएगा तो फिर पार्टी के लिए चंदा कहा से आएगा. वह सपा पर हमला बोलते हैं, बसपा पर वार करते हैं, भाजपा को उसकी औकात बताते हैं लेकिन ख़ुद वह और उनकी पार्टी क्या कर रही है, इसे छिपा जाते हैं. वह जनता को यह नहीं बताते कि क्यों उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने लोकपाल को लेकर सदन में जनता से किए वायदे को पूरा नहीं किया. राज्य सभा में लोकपाल पर बहस के दौरान कांग्रेस ने जो ड्रामा खेला वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन राहुल ने अपनी पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने की बजाए सारा कसूर विपक्ष के गले मढ़ दिया. राहुल के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि उनकी सरकार ने पिछड़ों का हक़ मारकर धर्म के आधार पर दूसरों को क्यों बांट दिया. राहुल अपनी बात रखते हैं, दूसरों की सुनना उन्हें मंजूर नहीं. यही वजह है कि वह यह घोषणा करने में हिचकिचा रहे हैं कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद सपा से हाथ मिलाकर सरकार नहीं बनाएगी. क्यों वह चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध नूराकुश्ती के रूप में कर रहे है? यह सवाल भी अहम है. बाबू सिंह कुशवाहा के मामले में भाजपा को कटघरे में खड़ा करते समय वह यह कैसे भूल गए कि कुशवाहा ने इसी बसपा सरकार में रहते हुए इतना बड़ा घोटाला किया था जिसका समर्थन कांग्रेस केंद्र की अपनी सरकार को बचाने के लिए हासिल किए हुए है. राहुल चाहते हैं कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, ताकि उनके 2014 में प्रधामनंत्री की कुर्सी पर बैठने में कोई रूकावट नहीं आए. पांच साल में प्रदेश की काया कल्प कर देने का दावा करने वाले राहुल से पूछा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश पर वर्षों तक राज करने वाले कांग्रेसी नाकार थे, जो काम वह चालीस साल में नहीं कर पाए वह पांच साल में कैसे करेंगे.

बड़े दलों की देखा–देखी छोटे दल भी पूरी तरह से जातीय खेल में उतर आए हैं. आज कोई भी पार्टी पूरे प्रदेश की जनता का नेता बनने को तैयार नहीं है. किसी को हिंदू प्यारा है, तो किसी को दलित और पिछड़ा, किसी की नज़र मुसलमानों पर है, लेकिन प्रदेश की जनता की जनता की चिंता किसी को नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

जनता को लुभाने के लिए मायावती ने प्रदेश को चार टुकड़ों में बांटने की आग लगाई. बुंदेलखंड की दशा सुधारने के बजाए मायावती सरकार बदहाली का रोना रोती रही, जबकि यहां से बसपा को काफ़ी सीटें मिली थीं. किसानों की समस्याओं को उन्होंने कभी समझा नहीं. उनकी जमीन चहेते बिल्डरों को दे दी गई. पांच साल तक यमुना एक्सप्रेस वे भी अधर में हैं, जिनके कंधों पर मायावती ने यह ज़िम्मेदारी डाली थी, उसने अपनी बैंक गारंटी वापस ले ली है. भ्रष्टचार का दाग़ मायावती सरकार पर शुरू से ही लगता रहा. स्वास्थ्य घोटाले ने तो सभी सीमाएं पार कर दीं, लेकिन मायावती अपने मंत्रियों को तब तक संरक्षण देती रहीं जब तक कि चुनाव का झुनझुना नहीं बज गया. मायावती सरकार ने विकास की अनदेखी कर मूर्तियों पर पैसा पानी की तरह बहाया.

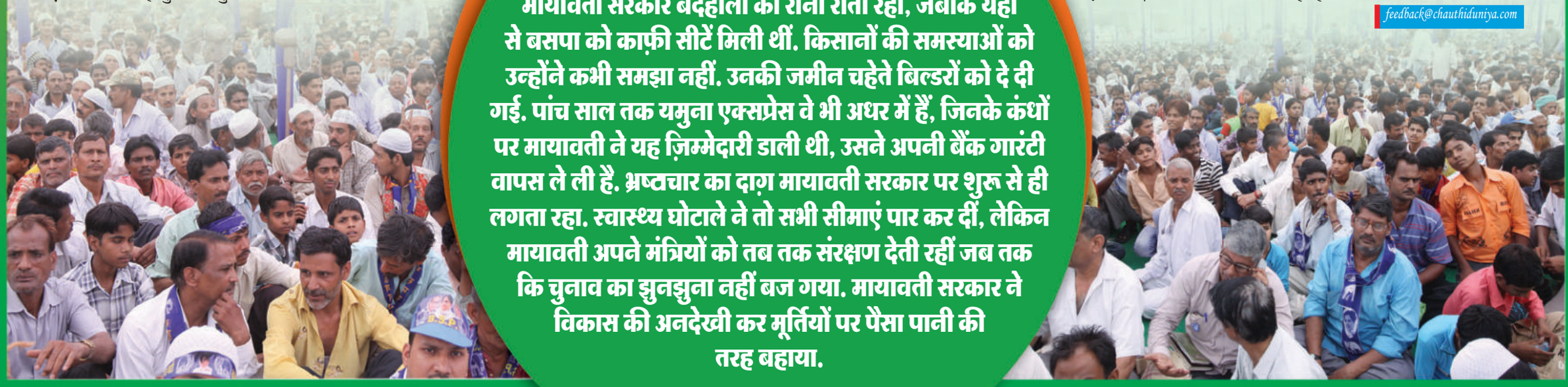

यादवों के साथ अपने प्रभाव से वोट हासिल करके वे हार-जीत के लिए छुपे रूस्तम साबित हो सकते हैं. लेकिन वे मुख्य संघर्ष में फिलहाल नहीं हैं.

चुनावी हलचल

जातीय गणित बिगड़ा

उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों में नए परिसीमन ने इस बार जातीय समीकरण बिगाड़ कर रख दिया हैं. इसे लेकर प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में आ गए हैं. विधानसभा की 126 सीटों में से 85 सीटें सुरक्षित हो गई हैं, इसमें तीस सामान्य सीटें सुरक्षित हो गई हैं. यहां कई दिग्गजों को न केवल अपनी पुरानी सीटों से हटना पड़ रहा है बल्कि कई दलों को इन बदले हालात के कारण नई ज़मीन तलाशनी पड़ रही है. कई दल इसी वजह से टिकट देने में देरी करते रहे. कहते हैं कि अस्तित्व में आई सीटों के कारण राजनीतिक दलों के बीच ऊहा पोह की स्थिति बन चुकी है. प्रत्याशी अपरिचित क्षेत्रों से मुखातिब हो रहे हैं. नए क्षेत्र हो जाने से कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है. इतनी जल्दबाज़ी में कार्यकर्ताओं में घुला मिला नहीं जा सकता. सब कुछ पहले से नक्शे के मुताबिक तैयार रहता था. लेकिन इस बार नए सिरे से सब कुछ करना पड़ रहा है. हालांकि हर दस साल में परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है. 1952, 1963, 1973 से लेकर अब तक चरणबद्ध तरीक़े से 2011 का परिसीमन हुआ है. जिसमें राज्य की 126 ऐसी सीटें है जिनका चुनाव परिणाम प्रदेश की राजनीति और सत्ता का रूख़ बदल सकती हैं. परिसीमन के बाद राज्य में ये नई सीटें बनी हैं. इतनी ही पुरानी सीटें ख़त्म कर दी गई है. राज्य के अधिकतर जिलों में परिसीमन के बाद स्थिति बदल गई हैं. कुछ पुरानी विधानसभा सीटें ख़त्म कर दी गई हैं, तो नई सीटे सामने आई है. बदली हुई सीटों पर प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है. विधानसभा की 403 सीटों में सूबे की 75 में से 59 ज़िलों की सीटे प्रभावित हुई हैं, सबसे ज़्यादा असर हरदोई ज़िले पर पड़ा है. जहां नौ विधानसभा सीटों में छह परिसीमन के दायरे में आई. गोरखपुर और जौनपुर में क्रमश: पांच-पांच विधानसभा सीटें परिसीमन के बाद बनीं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और मुजफ्फर नगर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और बाराबंकी में चार-चार सीटों की संख्या तीन से बढ़कर पांच हो गई है. बहरहाल नए परिसीमन ने सभी दलों को मुश्किल में डाल दिया है. बदली हुई सीटों पर कई दलों के प्रत्याशियों को नए सिरे से जातीय समीकरण समझने पड़ रहे हैं. वहीं क्षेत्र विशेष के लोगों से नया रिश्ता जोड़ना पड़ा है. मतदाताओं में इस बात की बड़ी उत्सुकता है कि इन नए क्षेत्रों के कारण ही नए मतदाताओं को नए विधायक का दीदार होगा.

– चौथी दुनिया ब्यूरो

बाराबंकी में मुस्लिम का बसपा से मोहभंग

बहुजन समाज पार्टी ने बाराबंकी में किसी भी मुस्लिम को अपने दल का प्रत्याशी कुबूल नहीं किया. पिछले चुनाव में फरीद महफुज किदवई ज़रूर बसपा का टिकट पाने में सफ़ल रहे थे, लेकिन इस बार वह बसपा प्रत्याशी की दौड़ में पिछड़ गए. पूर्व एमएलसी गयासुद्दीन किदवई का पार्टी छोड़ने को भी कहीं न कहीं मुस्लिमों का बसपा से मोहभंग माना जा रहा हैं. बाराबंकी में लगभग 20 लाख मतदाता है, जिनमें 40 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता है. सपा ने फरीद महफुज किदवई को कुर्सी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने इसी सीट से निजामुद्दीन निजाम को अपना प्रत्याशी बनाया हैं . पिछली बार की तरह भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का सिरदर्द मोल नहीं लिया है. आश्चर्य की बात तो यह है कि बसपा ने मुस्लिमों की बड़ी रैलियां कराने के बाद उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है. इससे बसपा में मुस्लिम प्रत्याशी न होने के पीछे कारण यह बताए जा रहे हैं कि बहिन जी का मुस्लिम प्रत्याशी से मोहभंग हो गया है. बसपा ने ज़िले की हैदरगढ़, दरियाबाद, कुर्सी, जैदपुर, रामनगर, बाराबंकी नवाबगंज यानी सभी सीटों पर बसपा को मुस्लिम प्रत्याशी न उतारने की मुखालफत देखने को मिल रही है. इससे लगने लगा है कि बसपा के इस क़दम से मुस्लिम वर्ग नाराज़ है, वहीं सपाई खुश हैं.

नहीं कटेगा मुन्ना बजरंगी का टिकट

जौनपुर की मड़ियाहू सीट से अपना दल के उम्मीदवार मुन्ना बजरंगी के मुताबिक एसडीएम की रिपोर्ट आ गई है. जिससे उसकी उम्मीदवारी का रास्ता साफ़ हो गया है. वह तिहाड़ जेल में है. मालूम हो कि मड़ियाहूं के उप जिलाधिकारी की ओर से पिछले दिनों प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के आवास पर नोटिस चस्पा कराई गई थी. इसमें उसका और उसकी पत्नी सीमा सिंह का नाम मतदाता सूची में ग़लती से आ जाने का जिक्र किया गया था. इस बारे में मुन्ना बजरंगी और उसकी पत्नी को अपना पक्ष रखने के लिए समय निर्धारित किया गया था. नियत तिथि पर मुन्ना बजरंगी की तरफ़ से ज़िले के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं केडी सिंह और यूपी सिंह ने उप जिलाधिकारी की अदालत में ऐसी कई दलीलें देकर साफ़ कर दिया कि मतदाता सूची में दोनों का नाम होना विधि सम्मत है. बहरहाल माफ़िया डॉन मुन्ना बजरंगी का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ़ हो गया है. इस समय वह तिहाड़ जेल में है. वर्ष1998 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी. फिलहाल उसे अपनादल से टिकट मिल चुका है. उसका राजनीति में प्रवेश करने का रास्ता साफ़ हो गया है. कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी के मड़ियाहूं विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा ने प्रदेश एवं जनपद को सुर्खियों ला दिया है. चुनाव आचार संहिता लागू होने के कई माह पूर्व मुन्ना बजरंगी की मां ग़रीबों को कंबल बांट रही थीं, जिसे प्रशासन ने रोक दिया था. क्षेत्र में लगी हार्डिंग्स को प्रशासन ने उतरवा दिया था.

चुनाव आयोग की चाबुक

चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 55 क्षेत्रों में अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए. ये दूसरे राज्यों के वरिष्ठ आईपीएस हैं. आयोग ने पुलिस के कामकाज पर नज़र रखने के लिए दस पुलिस पर्यवेक्षक और चुनावी ख़र्चे पर नज़र रखने के लिए उतने ही आयकर विभाग के पर्यवेक्षकों को तैनात किया है. प्रदेश की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती अनीता मेश्राम के अनुसार पहली बार पुलिस के कामकाज व चुनावी ख़र्च पर नज़र रखने के लिए पुलिस पर्यवेक्षकों एवं आयकर अधिकारियों की तैनाती की गई है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अभी तक 1281 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसके अलावा 4.34 लाख बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग उतारे और मिटाए गए हैं . अभी तक 2058 अवैध असलहे बरामद हो चुके हैं तथा 6.76 लाख लोगों के ख़िलाफ़ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. 60 हजार लोगों के ख़िलाफ़ जमानती वारंट जारी हुए हैं तथा 1.14 लाख लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं. इसके अलावा 1.14 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई हैं. ग्वालियर से आ रही एक ट्रक से 850 पेटी विदेशी शराब पकड़ी गई है. जिसकी क़ीमत 45 लाख रूपये के आसपास है. अब तक 44 करोड़ रूपये पकड़े जा चुके हैं. फिलहाल पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया के तहत भाजपा, कांग्रेस एवं सपा सहित विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अब तक 30 नामांकन पत्र दाख़िल किए हैं.

– दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय लोक दल चुनावी समीकरण बिगाड़ेगी

राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राजनीतिक उभार से मुलायम सिंह यादव की पेशानी पर बल पड़ गया है. समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों दल पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकता है. समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि उसे पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं हैं.

अमिताभ आकाश

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव में आगरा मंडल, मेरठ मंडल और गाजियाबाद मंडल मे सियासी हलचले पूरे शबाब पर है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 ज़िलों में इक्का-दुक्का उम्मीदवारों को छोड़कर सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद मुख्य रूप से संघर्ष में हैं. बसपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा पूर्व में ही कर दी थी, इसलिए उनके उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर मिला है. जबकि, भाजपा और कांग्रेस योग्य प्रत्याशियों की तलाश में लगे रहे. विधानसभा चुनाव से पूर्व रालोद को चुका हुआ माना जा रहा था. लेकिन, जैसे ही मुख्यमंत्री मायावती ने पश्चिम प्रदेश बनाने की घोषणा की और विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करा दिया. इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रालोद को ही मिला. पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का आंदोलन रालोद द्वारा ही शुरू किया गया था. समय की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस और रालोद ने गंठबंधन कर के सभी प्रतिद्वंद्वियों को भौंचक्क कर दिया.

रालोद के राजनीतिक उभार से मुलायम सिंह यादव की पेशानी पर बल पड़ गया है. सपा और रालोद दोनों दल पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का वोट रालोद के खाते में जा सकता है. सपा को लगने लगा है कि उसे पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं हैं. दूसरी ओर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी मान रहा है कि प्रदेश में राहुल गांधी के प्रभाव से कांग्रेस की स्थिति तो मजबूत हो सकती है, लेकिन सत्ता तक का रास्ता अभी काफ़ी दूर है. राहुल गांधी और कांग्रेसी दिग्गजों ने सपा के प्रति नरमी बरतना शुरू कर दिया है, उनका सारा निशाना बसपा और भाजपा पर ही है. रालोद के मुखिया अजित सिंह भी इसी नीति पर चल रहे हैं. मुलायम सिंह यादव इस तथ्य को भली भांति समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस और रालोद के बगैर नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उन्होंने रालोद को अपना निशाना प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाया है. लेकिन, रालोद के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करना शुरू भी कर दिया है. इसी के तहत अजित सिंह के क़रीबी रहे राष्ट्रीय महासचिव अनुराधा सिंह का सपा में शामिल हुए.

यही नहीं रालोद के अनेकों महत्वपूर्ण दिग्गज एवं कार्यकर्ता सपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं. चुनाव नजदीक आते-आते यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल क्षेत्र है. ख़ासकर ग्रामीण इलाक़ों में जाट समुदाय के लोगों की संख्या तादाद में है. जबकि शेष प्रदेश में जाट मतदाताओं की संख्या बहुत कम है. कुछ ज़िलों में तो जाट समुदाय के लोग न के बराबर हैं. जाटों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में कम होने के कारण जातिप्रधान प्रदेश की राजनीति में अजित सिंह का जनाधार प्रदेश व्यापी नहीं बन पाया. दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव और मायावती के पास वोटबैंक होने का फ़ायदा मिला और सपा, बसपा ने धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बना ली. अजित सिंह द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन जाट वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही शुरू किया गया था. यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाता है तो अजित सिंह की पार्टी रालोद काफ़ी ताक़तवर हो जाएगी. इस स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन मायावती के पास दलित वोट होने के कारण और अजित सिंह के पास जाट वोट होने की वजह से रालोद और बसपा की अच्छी स्थिति होगी. मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने का खेल खेलकर चुनावी पासा इसलिए फेंका, क्योंकि बसपा का दलित वोट राज्य विभाजन के बाद भी चारों प्रस्तावित राज्यों में बहुतायत में बना रहेगा, जबकि सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर स्थिति में आ जाएगी. अजित सिंह का राजनीतिक चिंतन हमेशा से अवसरवादी रहा है. सरकार कोई भी हो उनका उद्देश्य केंद्र सरकार में मंत्री पद पाने तक ही रहा है. उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ताक़त बढ़ाने के लिए प्रयासरत कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही रालोद से गठबंधन करके अजित सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया. पश्चिमी प्रदेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास होते ही रालोद को राजनीतिक ताक़त भी मिली. कांग्रेस से गठबंधन कर वे अचानक लाइमलाइट में आ गए. मौक़े का फ़ायदा उठाकर अजित सिंह ने सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया. लेकिन इससे कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. उसने पहले ही रालोद मुखिया को केंद्र में मंत्री पद देकर दबाव बना लिया था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़ सहित अधिकांश ज़िले के ग्रामीण इलाक़े जाट बहुल क्षेत्र होने की वजह से अचानक रालोद के प्रभाव में आ गए. विधानसभा चुनाव में इस बार भी रालोद के उम्मीदवारों की ज़्यादा संख्या में जीत कर आने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन रालोद गठबंधन से कांग्रेस की जीत का आंकड़ा अवश्य बेहतर हो सकता है. साथ में रालोद, बहुजन समाजवादी पार्टी को नुक़सान पहुंचाने की स्थिति में तो नहीं दिखती, लेकिन यह तय है कि वो सपा और ख़ासतौर पर भाजपा प्रत्याशियों को हरवाने में पूरी तरह से सक्षम दिखाई देने लगी है. रालोद के उदय से सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह यादव और भाजपा नेताओं को चिंता सता रही है. दूसरी तरफ़ अनुभवी अजित सिंह ने सपा पर हमले ने करने की नीति बना ली है तो सपा ने रालोद के सवाल पर चुप्पी साध ली है, लेकिन भीतर ही भीतर सपा, रालोद को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है.

सपा मुखिया का सोचना है कि विधानसभा चुनाव मे यदि रालोद की सीटें बढ़ गई तो कांग्रेस इसे ज़्यादा भाव नहीं देगी. इस स्थिति में सपा की सरकार तो प्रदेश में बन सकती है लेकिन वे किसी भी प्रकार से बढ़त की स्थिति में नहीं होंगे. दूसरी तरफ़ कांग्रेस आलाकमान का सोचना है कि उत्तर प्रदेश में रालोद का इस्तेमाल कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने तक सीमित रखना है. कांग्रेस भी रालोद मुखिया को विश्वसनीय नहीं मानती है. मायावती का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के बढ़ने से सपा और कांग्रेस दोनों को नुक़सान ही होगा. चुनावी समीकरण के हिसाब से रालोद प्रत्येक स्थिति में फ़ायदे में दिख रही है. अजित सिंह अपने परंपरागत जाट वोट बैंक को अपनी पकड़ में रखने के लिए बसपा पर लगातार हमले कर रहे हैं.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

feedback@chauthiduniya.com

एत्मादपुर में होगा घमासान

समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में रहे पूर्व मंत्री किशनलाल बघेल के पुत्र प्रेम सिंह बघेल को टिकट दिया है. पीस पार्टी ने मोतीलाल यादव और वंचित समाज पार्टी से डॉ. राशिद चौधरी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. वहीं बहुजन समाज पार्टी ने डॉ. धर्मपाल सिंह को टिकट दिया है.

परिसीमन के बाद एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक बदलाव आ गया है. उससे पूर्व यह क्षेत्र जाति विशेष हुआ करता था. परिसीमन के बाद यमुना पार का इलाक़ा जो आगरा की दयालबाग़ सीट(अब आगरा ग्रामीण) के अंतर्गत आता था, अब एत्मादपुर विधानसभा से जुड़ गया है. जबकि एत्मादपुर क्षेत्र का बड़ा इलाक़ा टूंडला विधानसभा क्षेत्र से जुड़ गया है. पूर्व में स्वंतत्रता के बाद से यह सीट सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी. भारतीय क्रांतिदल का यहां अच्छा ख़ासा प्रभाव था. सत्तर के दशक में यहां से बीकेडी के चौधरी मुल्तान सिंह विजयी रहे थे, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी तिलक सिंह मिलिंद को मात्र सौ वोटों के अंतर से हराया था. इसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित सीट घोषित कर दिया गया था. इस बार परिसीमन के बाद एत्मादपुर को दुबारा सामान्य सीट में तब्दील कर दिया गया है. परिसीमन से पूर्व यहां बघेल और ठाकुर मतदाताओं की बहुलता थी. ठाकुरों के 22 गांव में अधिक मतदाता होने के कारण इस क्षेत्र को ठाकुरों की बाइसी भी कहा जाता है, जबकि बघेल जाति के 60 गांव होने के कारण एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र को बघेलों की राजधानी भी कहा जाता है.

एत्मादपुर विधानसभा सीट पर इस बार सत्ताधारी बसपा से विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह को टिकट दिया गया है. इससे पूर्व वे दयालबाग़ सीट से चुने गए थे. यमुनापार आगरा का उनका चुनाव क्षेत्र एत्मादपुर सीट से जुड़ जाने से इस क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है. भाजपा से रामप्रताप चौहान पर दांव खेला गया है. जबकि रालोद ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हरदेव सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है. समाजवादी पार्टी ने बसपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री किशनलाल बघेल के पुत्र प्रेम सिंह बघेल को टिकट दिया है. पीस पार्टी की ओर से मोतीलाल यादव और वंचित समाज पार्टी से डॉ. राशिद चौधरी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. बसपा प्रत्याशी डॉ. धर्मपाल सिंह जाटव और ठाकुर वोट के कारण मजबूत दिखाई पड़ते हैं. लेकिन, वास्तविकता यह है कि क्षत्रियों का बड़ा हिस्सा भाजपा का वोट बैंक है. दूसरी ओर रालोद के उम्मीदवार हरदेव सिंह की छवि तो अच्छी है. उन्हें जाट के अलावा ठाकुरों का भी वोट मिलना तय है. साफ़तौर पर वो जीतने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा और बसपा प्रत्याशी को काफ़ी नुक़सान पहुंचा सकते हैं, इसका फ़ायदा सपा प्रत्याशी प्रेम सिंह बघेल को मिलने की ज़्यादा संभावना है. बसपा, रालोद और भाजपा से ठाकुर प्रत्याशी खड़े होने के कारण ठाकुरों का वोट बंट रहा है, जबकि एकमात्र बघेल प्रत्याशी होने का लाभ सपा प्रत्याशी को मिल गया तो वे जीत के प्रबल दावेदार होंगे. पीस पार्टी के मोती लाल यादव उन्हें नुक़सान पहुंचा सकते हैं.

यादवों के साथ अपने प्रभाव से वोट हासिल करके वे हार-जीत के लिए छुपे रूस्तम साबित हो सकते हैं. लेकिन वे मुख्य संघर्ष में फिलहाल नहीं हैं. वंचित समाज पार्टी के डॉ. राशीद चौधरी जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं. वह कुछ मुस्लिम व अन्य वोट ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह संघर्ष में नहीं हैं. एत्मादपुर विधानसभा में साढ़े तीन लाख से भी ज़्यादा मतदाता हैं, इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या दो लाख और महिलाओं के ढेड़ लाख मत हैं. यह क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन के लिए शुरू से अग्रणी रहा है. किसान आंदोलनों के लिए यह विधानसभा चर्चित रहा. पिछले 22 सालों से कांग्रेस और भाजपा जीत के लिए तरसती रही है. यहां से जनता दल दो बार, बसपा दो बार, सपा और रालोद ने एक-एक बार जीत दर्ज कराया है. इस बार भी भाजपा और कांग्रेस यहां से जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही हैं. हालांकि कांग्रेस ने यह सीट अब रालोद प्रत्याशी के लिए छोड़ दी है.

अमिताभ आकाश
feedback@chauthiduniya.com

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

वोट-चोट देने में माहिर स्टार प्रचारक

पार्टी के स्टार प्रचारक लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज पार्टी की विचारधारा से मतदाताओं को रूबरू कराने के अलावा अन्य दलों की ख़ामियां गिनाने का काम करेंगे. अरूण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे नाम बसपा और केंद्र सरकार की क़ानूनी खामियों को उजागर करेंगे. हेमामालिनी और स्मृति ईरानी महिलाओं को लुभाने का काम करेंगी. उन्हें बताएंगी कि मंहगाई डायन को कौन पाल-पोस रहा है.

सभी दलों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. सभी दलों में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें स्टार प्रचारक का तमगा हासिल है. यह वे नेता हैं जो अपने वाकपटुता के दम पर हवाओं का रूख़ मोड़ देने की हिम्मत रखते हैं. भाजपा आलाकमान ने अपने इन स्टार प्रचारकों को उनके स्वभाव और ख़ासकर जाति विशेष में बांटकर प्रचार और वोट दिलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है. तो कई ऐसे स्टार प्रचारक भी हैं जो नाराज़ होकर पार्टी को चोट पहुंचाने का काम करने में लगे हैं. भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई बड़े नेताओं का नाम है लेकिन भाजपा में सबसे चर्चित नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी का. लंबे समय से बीमार चल रहे अटल जी को पिछले कुछ वर्षों से न तो सार्वजनिक जीवन में देखा गया है और न ही वह कभी कैमरे की नज़र में आए. भाजपा ने चुनाव आयोग को जो लिस्ट सौंपी है, उसमें अन्य लोगों के अलावा अटलजी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है. भाजपा के जो स्टार प्रचारक इस समय चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं, उसमें साध्वी उमा भारती, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, महासचिव कलराज मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, विनय कटियार का नाम प्रमुख है. आने वाले दिनों में भाजपा अपने दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज ख़ान, नरेंद्र मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, नवजोत सिंह सिद्धू और सांसद कीर्ति आज़ाद हैं.

इनके अलावा पार्टी अपने फायर ब्रांड नेता वरूण गांधी की छवि को भी भुनाने का प्रयास करेगी. नरेंद्र मोदी जो बिहार चुनाव के समय वहां गठबंधन की मजबूरी के चलते नहीं जा पाए थे, उत्तर प्रदेश में अपना रंग जमाने आएंगे. नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल पार्टी मुसलमानों में व्याप्त भय को दूर करने के लिए करेगी ताकि वोटों का ध्रुवीकरण रोका जा सके. मोदी गुजरात में मुसलमानों के विकास के कसीदे पढ़ते नज़र आ सकते हैं. उक्त सभी नेता बसपा सरकार पर तो हल्ला बोलेंगे ही केंद्र के भ्रष्टाचार से भी जनता को रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, ताकि राहुल जो कांग्रेस की छवि जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर से पर्दा हट सके. युवराज को कटघरे में खड़ा कर के भाजपा अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेगी, वहीं कांग्रेस–सपा और बसपा की नूराकुश्ती का भी पर्दाफाश करेगी. भाजपा के स्टार प्रचारकों में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ब्राह्मणों को लुभाने के काम आएगा. अटल के नाम की सीडी और उनके नाम का इस्तेमाल करके पार्टी सवर्णों और ख़ासकर ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है. भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने इसे नेतृत्व की मजबूरी मानने से इंकार किया. उनका कहना था कि वाजपेयी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और सभी के प्रेरणास्त्रोत भी. चुनावी बेला में अंत समय पर वाजपेयी के नाम से अपील जारी कराई जा सकती है. वैसे कलराज मिश्र और मुरली मनोहर जोशी भी ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं. भाजपा के नंबर दो के नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज आदि नेता पार्टी की विचारधारा से मतदाताओं को रूबरू कराने के अलावा अन्य दलों की ख़ामियां गिनाने का काम करेंगे. अरूण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे नाम बसपा और केंद्र सरकार की क़ानूनी खामियों को उजागर करेंगे. वह बताएंगे कि किस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है. धर्म आधारित आरक्षण और लोकपाल के मामले में जिस तरह संविधान का माखौल उड़ाया गया उसकी कलई खोलने का काम उक्त नेताओं के ज़िम्मे होगा. मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज मुसलमानों को बताएंगे कि किस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें भाजपा का हौवा दिखाकर बरगला रहे हैं, जबकि हक़ीक़त में भाजपा मुसलमानों को वोट बैंक न मानकर उनका सार्वजनिक जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है. हेमामालिनी और स्मृति ईरानी महिलाओं को लुभाने का काम करेंगी. उन्हें बताएंगी कि मंहगाई डायन को कौन पाल–पोस रहा है. नवजोत सिंह सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा अपने जोशीले भाषणों से जनता और युवाओं में क्रांति लाने का काम करेंगे.

भाजपा की जहन में ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की बात भी है. इसीलिए भाजपा बाबू सिंह कुशवाहा का बचाव करने में लगी है. भाजपा नेता जनता को बताएंगे कि उन्होंने तो बाबू को अपने साथ लिया क्योंकि वह पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे और उनके ऊपर कोई आरोप भी तय नहीं हुए हैं. लेकिन कांग्रेस तो उसी बसपा के समर्थन से केंद्र में सरकार चला रही है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा है. ओबीसी नेताओं में उमा भारती, ओम प्रकाश सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा के नाम के सहारे भाजपा पिछड़ा कार्ड मजबूती से खेलना चाहती है. ओबीसी को लुभाने के लिए भाजपा बड़े पैमाने पर अपने मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए मैदान में उतारेगी. पार्टी के कई मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री ओबीसी कोटे से ताल्लुक रखते हैं. उनमें नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और सुशील मोदी प्रमुख हैं. भाजपा का कहना है कि अल्पसंख्यक कोटे पर पिछड़े वर्ग में बढ़ रही नाराज़गी को भाजपा ने भांप लिया है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस ओबीसी पर खुलकर बोलने से कतरा रही है कि कहीं अल्पसंख्यक नाराज़ न हो जाए. तीनों दल मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं तो भाजपा ओबीसी कार्ड के सहारे उन्हें मात देने का सपना पाल रही है. बसपा के दाग़ी नेता बाबू सिंह कुशवाहा के ख़िलाफ़ मुंह खोलने वाले अपने युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व एमएलसी रामाशीष राय को बाहर का रास्ता दिखाने में ज़रा भी देरी नहीं की. इसी प्रकरण में विरोध करने वाले भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आईपी सिंह को निलंबित कर दिया गया था. अन्य नेताओं को भी आगाह कर दिया गया है कि वह कुशवाहा के ख़िलाफ़ कुछ न बोलें. भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के जरिए भ्रष्टाचार और सुशासन की जगह ओबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है. भाजपा आलाकमान का मानना है कि 52 प्रतिशत ओबीसी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा इसका बेड़ा पार लगा सकता है. पार्टी उसे अपने अध्यक्ष नितिन गडकरी के दस प्रतिशत ओबीसी वोट बैंक बढ़ाने के फार्मूले से जोड़कर देख रही है. भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के सहारे यूपी की जंग जितना चाहती है, लेकिन अंर्तविरोध इसके लिए अभी भी नासूर बना है. भाजपा के कई नाराज़ दिग्गज नेता पार्टी की जड़े खोद सकते हैं. जिस प्रकार से पार्टी में उमा भारती और संजय जोशी का विरोध हो रहा है. उमा और संजय को गडकरी यूपी का मिशन 2012 पूरा करने के लिए लेकर आए थे. उमा पर सबसे पहले कलराज मिश्र ने यह कहते हुए हमला बोला था कि प्रदेश के बाहर का कोई नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं होगा. राजनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही और विनय कटियार जैसे नेताओं को भी लगता है कि उमा के आने से उनका महत्व घटा है. इसलिए वे नेता उमा को भी कल्याण सिंह के मुक़ाम पर पहुंचा देना चाहते हैं. वर्ष 2007 में कल्याण को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, लेकिन उनकी टिकट बंटवारे में एक नहीं चलने दी गई और जब पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो सारा ठीकरा उनके सिर फोड़कर राजनाथ सिंह जैसे नेता बच निकले. कल्याण सिंह को वर्ष 2007 में भीतरघात के कारण मुंह की खानी पडी, उन्हीं कल्याण ने 1999 के लोकसभा चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए अटल बिहारी बाजपेयी को झटका देने का काम किया था. जिसके कारण भाजपा को 1999 में सिर्फ़ 29 सीटें ही मिल पाईं थीं, जबकि क़रीब साल भर पूर्व 1998 में हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम 58 सीटों पर लहरा रहा था.

भाजपा के स्टार प्रचारकों में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ब्राह्मणों को लुभाने के काम आएगा. अटल के नाम की सीडी और उनके नाम का इस्तेमाल करके पार्टी सवर्णों और ख़ासकर ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है. भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने इसे नेतृत्व की मजबूरी मानने से इंकार किया. उनका कहना था कि वाजपेयी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और सभी के प्रेरणास्त्रोत भी. चुनावी बेला में अंत समय पर वाजपेयी के नाम से अपील जारी कराई जा सकती है.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

चुनावी हलचल

कांग्रेस मंत्री बनाम कांग्रेस विधायक

केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल एवं निवर्तमान कांग्रेसी विधायक अजय कपूर के बीच प्रत्याशी को लेकर ठन गई है. स्थानीय कांग्रेसियों का मानना है कि यह द्वंद्व किसी तीसरे को लाभ पहुंचा सकता है. इस सीट पर जहां समाजवादी पार्टी और बसपा सघन रूप से जनसंपर्क में मशगूल है. वहीं भाजपा अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है. परिसीमन के चलते गोविंद नगर विधानसभा सीट तीन हिस्सों में विभाजित हो गया है. चुनावी समीकरण को देखते हुए गोविंद नगर के विधायक अजय कपूर अपना उम्मीदवार उतारने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाए हुए हैं, वही उनके धुर विरोधी रहे केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल इस सीट पर अपना मनपसंद प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं. श्रीप्रकाश जायसवाल जहां डॉ. शैलेंद्र दीक्षित को सामने लाने के लिए नेतृत्व पर दबाव बनाते नज़र आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कपूर अंबुज शुक्ला के लिए प्रेशर बनाए हुए है. वैसे राजनीतिक आकाओं की माने तो सीट पर कोई तीसरा दावेदार बाज़ी मार ले जाए तो कोई शक नहीं. फिलहाल दोनों नेता शीर्ष नेतृत्व को अपने अपने ढंग से जिताऊ प्रत्याशी का पाठ पढ़ा कर दावेदारी करने में जी जान से जुटे हैं. सपा ने भी इस सीट पर अब तक कई प्रत्याशी बदल डाले हैं. पहले अशोक अंशवानी और नीलम रोमिला सिंह के बाद अब अशोक अंशवानी को चुनाव मैदान में उतारा गया हैं. बहुजन समाज पार्टी ने भी इस सीट पर पहले मथुरा पाल को उतारा था फिर उनके कांग्रेस में चले जाने के बाद सचिन त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है. भाजपा भी गोविंद नगर सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन अब तक उसका प्रत्याशी ही तय नहीं हो सका हैं. एक तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस क्षेत्र के मतदाताओं की निगाहें भी भाजपा प्रत्याशी पर टिकी हुई हैं . इस सीट पर भाजपा से पूर्व मंत्री बालचंद्र मिश्रा, महापौर रवींद्र पाटनी के साथ चंद्र कुमार गंगवानी समेत कई दिग्गज अपनी दावेदारी शीर्ष नेतृत्व से कर रहे हैं. इन्हीं नामों से एक प्रत्याशी बन सकता है.

– अजय कुमार,लखनऊ ब्यूरो

घर में घिरे भाजपा अध्यक्ष

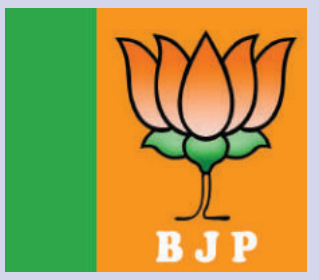

भाजपा अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही अपने ही गृह जनपद में घिरते जा रहे हैं. यह विरोध तब और बढ़ गया जब बसपा के भ्रष्ट मंत्री रहे कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर लिया गया और अपनों को दरकिनार कर ग़ैर लोगों को भाजपा प्रत्याशी बनाकर टिकट दे दिया. भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विश्वसनीय और पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर ग़ैर लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं. यह कार्यकर्ता एकजुट होकर अब शाही को उनके ही गढ़ में उन्हें हराने की योजना बना रहे हैं. इस कार्य योजना को सफ़ल बनाने के लिए क्षेत्र के पुराने कार्यकर्ता अपना प्रत्याशी भाजपा के समानांतर खड़ा कर के जवाब देंगे. नाराज़ कार्यकर्ता ज़िले की रूद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से निषाद समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय साहनी को भाजपा के जयप्रकाश निषाद के ख़िलाफ़ चुनावी समर में उतार सकते हैं. देवरिया विधानसभा क्षेत्र से डॉ. सत्य प्रकाश मणि व विजय प्रताप मणि भाजपा के घोषित प्रत्याशी जनमेजय सिंह के ख़िलाफ़ मैदान में होंगे. इस विधानसभा सीट के लिए तो डॉ. सत्य प्रकाश मणि अपना संपर्क दौरा भी शुरू कर चुके हैं. वहीं सूर्यप्रताप शाही के पथरदेवा से भाजपा के वरिष्ठ नेता मारकंडेय तिवारी असंतुष्टों के प्रत्याशी होंगे. बरहज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बने नरेंद्र मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र जो पहले सपा की साइकिल पर सवार होकर टिकट के दावेदार थे लेकिन उन्हें भाजपा ने टिकट दे दिया . इसके कारण भाजपा के कार्यकर्ता सख्त नाराज़ हैं. इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता दो दिन का धरना प्रदर्शन कर चुके हैं. धरने में भाजपा के पूर्व ज़िला मंत्री विजय चंद्र कौशिक, पूर्व चेयरमैन डॉ. शिवहरि सिंह, राम निवास उपाध्याय, हरेंद्र यादव, हरेंद्र मल्ल, विनय पाठक व बुद्धिचंद्र विश्वकर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाई है. बहरहाल संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि नाराज़ लोग विजय चंद्र कौशिक को निर्दल प्रत्याशी के रूप में भाजपा के विरूद्ध खड़ा करेंगे.

कुशवाहा का आरक्षण बचाओ अभियान

अपना पुराना घर बसपा छोड़कर आए बाबू सिंह कुशवाहा को भले ही वैधानिक तौर पर नया घर अभी तक नहीं मिल पाया हो. लेकिन सिर पर भाजपाइयों के हाथ फेरने से उनका धैर्य बरकरार है. चुनाव में कुशवाहा खुलकर जनसभाएं करने लगे हैं. भाजपा में शामिल होते समय कुशवाहा ने कहा था कि यह उनकी सैद्धांतिक लड़ाई का हिस्सा है. इसी लड़ाई के कारण उन्हें बसपा और कांग्रेस की मिली-जुली साजिश का शिकार होना पड़ा है. दरअसल कांग्रेस सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ों में साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण देने का विरोध करने वाले कुशवाहा का मानना है कि इससे अन्य पिछड़ी जातियों का भारी नुक़सान हुआ है. अल्पसंख्यक आरक्षण का खामियाजा उन्हें भुगतने को मजबूर होना पडेगा. यह कांग्रेस का षड्यंत्र है. बसपा भी इसका समर्थन करती रही है. इसीलिए जब कुशवाहा भाजपा में शामिल हुए तो हल्ला मचाने वालों में कांग्रेस और बसपा सबसे आगे रही. कुशवाहा ने तब भी कहा कि वे किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी बात शोर-शराबे में अनसुनी कर दी गई. आख़िरकार उन्हें भाजपा की सदस्यता स्थगित करनी पड़ी. उसी दिन लखनऊ में विनय कटियार ने कहा था कि कुशवाहा जल्द ही महत्वपूर्ण ख़ुलासा करने वाले हैं. राष्ट्रीय अधिकार मंच के संयोजक परशुराम कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश भर के कुशवाहा, मौर्य, पाल, प्रजापति, सैनी, शाक्य समाज समेत अन्य पिछड़ी जातियों के लोग सभा में भाग लेंगे. इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, आरक्षण बचाओ सम्मेलन. कुशवाहा इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगे. पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर रैली सभाएं एवं सम्मेलन करेंगे. फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की भले ही एक बदनाम बसपाई को पार्टी में लेने से विभिन्न दलों के नेताओं के विरोध का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान में कल्याण के बाद शून्य पड़ी पिछड़ों के कद्दावर नेता की जगह को भरने का दुस्साहसिक क़दम उठाया है. कुशवाहा से हाथ मिलाने के बाद कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी और काछी समाज में प्रत्यक्ष रूप से संदेश गया है. जिससे भाजपा मंत्रमुग्ध है कि उसे कुशवाहा के कारण ही पिछड़ा वोट मिलने की संभावना है. देखना यह है कि भाजपा को कुशवाहा से लाभ मिलेगा या नहीं .

– चौथी दुनिया, लखनऊ ब्यूरो

प्रियंका की पाठशाला

संजय सक्सेना

आख़िरकार मां और भाई का प्यार बहन प्रियंका को अमेठी–रायबरेली खींच ही लाया. क़रीब ढाई साल बाद(लोकसभा चुनाव के पश्चात) चुनावी मौसम में भाई के संसदीय क्षेत्र पहुंची प्रियंका को लोगों ने सिर–आंखों पर बैठा लिया. उन्होंने सबसे पहले ढाई साल तक नहीं आने के लिए माफ़ी मांगी इसके बाद वह राहुल गांधी के मिशन 2012 को पूरा करने में लग गई. समय कम था, इसलिए चुनावी रणनीतियां युद्ध स्तर पर बनाई गई थी. भावनाओं की चासनी में डुबोकर लोगों को खींचने का प्रयास किया गया. युवाओं की नज़र में प्रियंका एक आईकॉन थीं तो बुजुर्ग लोगों को उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखाई दी. हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्रियंका की पाठशाला में आने के बाद असंतुष्टों का गुस्सा काफुर हो गया. प्रियंका गांधी की पाठशाला में युवक–बुजुर्ग सभी ने बढ़–चढकर हिस्सा लिया. किसी के पास कांग्रेस के लिए वीजन था तो कोई प्रियंका को क़रीब से देखने की लालसा पाले था. बात असंतोष की आई तो प्रियंका ने साफ़ कर दिया कि गिले शिकवे अपनी जगह, राहुल भैया का सभी को साथ देना है. बात प्रियंका के अमेठी पहुंचने से की जाए तो सबसे पहले उनका जो जुमला सुनाई दिया वह था, आप पहले मुझे डांट लीजिए, मैं काफी दिनों बाद आई हूं. चेहरे पर अपराधबोध लिए प्रियंका ने यह बात जब कही तो लोगों की जुबान सिल गई और हाथ आशीर्वाद के लिए ही उठ गए. सवाल यह भी उठा कि प्रियंका को राजनीति से दूर क्यों रखा जा रहा है, क्या उन्हें बेटी होने की सजा मिल रही है, लेकिन इन बातों की तरफ़ प्रियंका ने कोई तवज्जो नहीं दी. प्रियंका ने ब्लॉकवार मीटिंग करके सबसे बात की. प्रियंका ने जगदीशपुर के विधायक राम सेवक धोबी के निवेदन पर उनके नाती राधेश्याम चौधरी को जगदीशपुर से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा कि तो तो लोगों ने उनका तालियां बजाकर अभिनंदन किया. पार्टी ने टिकट रामसेवक को ही दिया था लेकिन 90 वर्षीय रामसेवक ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हुए नाती के लिए टिकट मांगा था. इसी प्रकार गौरीगंज सीट की दावेदारी को लेकर चल रहे विवाद में अहम किरदार निभाते हुए प्रबल दावेदार मो. नईम को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने की भी बात कही. क़रीब ढाई साल बाद इस इलाक़े में पहुंची प्रियंका के लिए यह नए किस्म का अनुभव था, लेकिन प्रियंका ज़रा भी विचलित नहीं हुई न कहीं चेहरे पर तनाव दिखा और न ही गुस्सा. बेलाग, कह दिया जो भी पार्टी तय करेगी, उसे सभी को मानना होगा.

प्रियंका की पाठशाला में लोगों ने बढ़–चढकर हिस्सा लिया. प्रियंका ने अमेठी में कहा कि आप पहले मुझे डांट लीजिए, मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूं. यह सुनकर लोगों में चुप्पी छा गई और हाथ आशीर्वाद में उठ गए. साथ हीं उन्होंने यह भी कहा कि गिले शिकवे अपनी जगह, राहुल भैया का सभी को साथ देना है.

feedback@chauthiduniya.com